हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 फरवरी 2009

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 12 फरवरी, 2009

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(3)1
ताराकिंत प्रश्न एवं उत्तर	(3)3
हिन्दु कन्या महाविद्यालय, जगाधरी तथा राजकीय महाविद्यालय बरवाला के विद्यार्थियों का अभिनन्दन	(3)8
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3)8
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(3)57
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)39
अनुपस्थिति की अनुमति	(3)44
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(3)45
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(3)45
(नियम 30 के निलम्बन के लिए)	
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)46

सदस्यों का निलम्बन	(3)59
वाक आउट	(3)65
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)68
बैठक का समय बढ़ाना	(3)98
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)98
बैठक का समय बढ़ाना	(3)107
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)107

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 12 फरवरी, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में दोपहर अपराहन 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, कल ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी की धर्मपत्नी का निधन हुआ है और कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो एक–एक करके हमें छोड़ते जा रहे हैं उनके बारे में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहता हूँ। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी की धर्मपत्नी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रणबीर सिंह सिंह महेन्द्रा जी की माता, हरियाणा राज्य मंत्री श्रीमती किरण चौधरी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री सोमवीर सिंह जी की सास श्रीमती विद्या देवी के 10 फरवरी, 2009 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है यह सदन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है जिन्होंने देश

की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: – श्री शिगारा सिंह, करनालय श्री जयगोपाल शर्मा, यमुनानगरय श्री मौजी राम, गांव रूपावास जिला सिरसाय श्री रामपत ठाकरान गांव खोडू जिला गुड़गांव हैं। यह महान् सदन इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक वेदना प्रकट करता है।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ): अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने आप को इन शोक प्रस्तावों के साथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी की धर्मपत्नी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा की माता, हरियाणा की राज्य मंत्री श्रीमती किरण चौधरी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री सोमवीर सिंह जी की सास श्रीमती विद्या देवी जी के 10 फरवरी को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। श्रीमती विद्या देवी का जन्म गांव बूथनवकलां जिला फतेहाबाद में हुआ। धार्मिक एवं सामाजिक महिला क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य

योगदान दिया। इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री शिगारा सिंह, करनालय श्री जयगोपाल शर्मा, यमुनानगरय श्री मौजीराम गांव रूपावास जिला सिरसा तथा श्री रामपत ठाकरान गांव खोडू जिला गुडगांव ओंय मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता हूँ तथा शोक सैतपा परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है मैं इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और इस शोक प्रस्ताव में श्री शिगारा सिंह, श्री जयगोपाल शर्मा जी, श्री रामपत ठाकरान जी तथा श्री मौजी राम जी के निधन पर हार्दिक दु:ख प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती विद्या देवी जी के दु:खद निधन का शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है। 'अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस परिवार के नजदीक रह कर मैंने उनके सादे जीवन को देखा। वे एक ऐसी विभूति थी जिन्होंने इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी लेकर इतनी बड़ी सत्ता को प्राप्त करके भी अपनी जिन्दगी में सादगी को कभी नहीं छोड़ा। एक बहुत ही साधारण किसान की तरह साधारण परिवार में जो एक हमारी मर्यादा है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी गुजारी। हमारे समाज में महिलाओं की एक अहम् भूमिका होती है उस

भूमिका को निभाते हुए उन्होंने अपने जीवन का निर्वहन किया। हर अच्छे और बुरे दिनों में चौधरी बंसी लाल जी और उनके बेटे चौधरी सुरेन्द्र सिंह और सारे परिवार का उन्होंने सदा साथ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी जब मुख्यमंत्री होते थे तो वे खेती–बाड़ी के काम की खुद देखभाल करती थी। स्पीकर सर, उनके रूप में एक महान् विभूति हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई है। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धाजति अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। मुझे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी वैसी लाल जी की धर्मपत्नी, हमारे विधानसभा के सदस्य श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा की माता, हरियाणा की राज्य मंत्री श्रीमती किरण चौधरी और हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री सोमवीर सिंह की सास श्रीमती विद्या देवी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उन्होंने अपना जीवन बड़े ही सादे ढंग से समाज की सेवा करते हुए जिया। मुझे श्रीमती विद्या देवी जी के निधन पर गहरा दुःख है। हाउस में जिन स्वतंत्रता सेनानियों के दुःखद निधन के बारे में शोक प्रस्ताव आया है, इन सभी के दुःखद निधन पर मुझे गहरा शोक है। मैं परमपिता परमात्मा से इन दिवंगत आत्माओं की

शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ और इनके शोक संतप्त परिवारों को सदन की संवेदना पहुंचा दी जाएगी। अब इन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ।

(इस समय दिवंगत आत्माओ के सम्मान में सदन के सदस्यों खरा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

More Bus Routes for Private Operators

***1165 Sh. Tejender Pal Singh Mann :** Will the Transport Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to offer some more bus routes to private operators in the near future ;

(b) whether department is satisfied about the monitoring system of private operators ; and

(c) the measures being taken to make sure the plying of private buses on their sanctioned routes ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):

(क) हां, श्रीमान जी, निकट भविष्य में नई परिवहन नीति के तहत निजी आपरेटरों को कुछ और बस रूट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) हां, श्रीमान जी, मानीटरिंग सिस्टम को सुधारा जा रहा है। सभी जिलों में सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की नियुक्ति की जा चुकी है। वे निजी आपरेटरों के परिवहन संचालन की मानीटरिंग तथा उसमें उचित कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) विभाग ने एनफोर्समैंट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पग उठाए हुए हें, जो अन्य कार्यों के साथ–साथ निजी आपरेटरों के बस परिवहन संचालन का भी निरीक्षण करेंगे। इस विंग के लिए (1)120 पद मोटर वाहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक तथा परिवहन उप निरीक्षक के पदों को भरा जा रहा है। (2) एनफोर्समैंट प्राधिकारियों की सहायता के लिए पुलिस विभाग से 90 मुख्य सिपाही कम चालक तथा सिपाही प्रति नि मुक्ति के आधार पर लिये जा रहे हैं। (3) एक नई परिवहन नीति बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य निजी परिवहन संचालन को सुव्यवस्थित करना है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, यह बात तो ठीक है कि आर०टी०ए० ने नए बस रूटस दोबारा से स्थापित किए हैं। लेकिन जनता की बड़ी भारी समस्या है कि जहां–जहां प्राईवेट

बसों के रूटस हैं या तो वे वायबल नहीं हैं या कुछ लोग इनका दुरुपयोग करते हैं और वे रूट/खाली रह जाते हैं। जनता हमारे पास आती है कि साहब इनको कहिए कि बस चलाएं। वे चलाते नहीं है और सरकार की बसें उन रूटस पर चल नहीं सकती हैं। जब हम कहते हैं तो हमें वहां जी०एम० द्वारा यह बताया जाता है कि यहां तो प्राईवेट बस वाले चलते हैं। हम फील्ड में आर०टी०ए० को कान्टैक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मई इनको चलवाओ। स्पीकर सर, यह बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। इस बारे में कोई न कोई ऐसी पुख्ता नीति होनी चाहिए कि उनकी वायबिल्टी भी करार की जाए, उसमें चाहे उनको रूट बढ़ाकर दें या किसी और तरह से करें। अगर उनको नुकसान होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें जनता की सुविधा के लिए भी काम करना चाहिए। अब मेरे हल्के में 2–9 रूटस हैं। एक पाई से कैथल तक चलता है। स्पीकर सर, सिसला, सिसवा के लोग कहते हैं हमारे पास बस नहीं आती है। कोई पुण्डरी से वापिस चला जाता है कोई दूसरी जगह से चला जाता है। इसी प्रकार से असंध से सड़ा रूट है। राढा भी मेरे हल्के में हे, उसके रास्ते में रतक है और भी गांव वहां हैं और वहां पर कोई कस नहीं चलती है। वह प्राईवेट बस का रूट है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि अगर कोई अपने रूट पर नहीं चलता है तो उन पर उचित कार्यवाही तो करे ही लेकिन जनता की सुविधा के लिए आप वहां पर 2 या 3 सरकारी बसें चलाने का प्रबन्ध कर दें। जहां–जहां इस प्रकार की समस्याएं हैं तो उनके बारे में मुझे उम्मीद है कि नयी ट्रांसपोर्ट

पोलिसी बनने के बाद ये समस्याएं दूर होंगी। स्पीकर सर, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बर्ड मुश्किल से यह सारा काम करवाया था, क्योंकि हमने जनता को वचन दिया था। उसके बाद दस साल तक दूसरी सरकारी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया जिसके कारण इनकी हालत बद से बदतर होती चली गयी। उन्होंने इसको इम्प्रूव ही नहीं किया इसलिए अभी भी इसमे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सरकार ने 900 नयी बसिज खरीदने के लिए गवर्नर ऐड्रेस में कहा है। स्पीकर सर, जितना पैसा सरकार के पास है उतना वह लगाए और बाकी प्राईवेट आपरेटरों को सरकार यह काम दे दें ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और जनता की समस्या का समाधान भी हो।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रत्य किया है। पहले हरियाणा रोडवेज की बसिज ही सारे हरियाणा के गांवों को कवर करती थीं लेकिन ज्यों–ज्यों आबादी बड़ी त्यों–त्यों यह मांग बढ़ती गयी। 1993 में सरकार ने दोबारा से इस बारे में विचार किया क्योंकि सरकार सभी जगहों पर हरियाणा रोडवेज की बसिज नहीं दे पा रही थी। उस समय यह सोचा गया कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको कोओपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से प्राईवेट रूटस बनाकर दे दिए जाएं। उस वक्त गांवों को जोड़ते हुए रूटस बनाये गए थे। इन रूटस के साथ दस किलोमीटर की सीमा तक नेशनल– हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर प्राईवेट आपरेटर्ज को अपनी बासेज चलाने की छूट दी

गयी थी। बाद में यह देखा गया कि ये रूटस वायबल नहीं रह गए थे जिसके कारण कुछ रूटस खल हो रहे थे। इसके बाद 2002 में फिर इस बारे में विचार किया गया और इस दस किलोमीटर की सीमा को बढ़ाकर 29 किलोमीटर तक नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर प्राईवेट आपरेटर्ज को बसिज चलाने की इजाजत दे दी गयी। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह मानकर चलते हैं कि कुछ रूटस वायबल नहीं रहे हैं इसलिए वे बद हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी कारण मान साहब की मांग जायज है लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जहां–जहां पर प्राईवेट रूटस दिए गए हैं उन पर सरकारी रोडवेज की बसिज नहीं चल सकती। परन्तु फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने प्राईवेट रूटस पर बसिज नहीं चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, हमने हर जिले में सचिव, आर०टी०ए० को इसके लिए लगाया है। उनका पहला परपज लगाने का यही है कि जो रूटस सोसाययईज के माध्यम से प्राइवेट आपरेटर्ज को अपनी बसिज चलाने के लिए सरकार ने दे रखें हैं और वे अपनी बसिज नहीं चला रहे हैं तो वह उनको चौक करें कि वे क्यों नहीं अपनी बसिज चला रहे हैं। अगर वे इन रूटस पर अपनी बसिज नहीं चला सक्ते तो हम उनके रूटस कैंसिल करेंगे और उन पर हरियाणा रोडवेज की बसिज चलाएंगे। स्पीकर साहब, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्राईवेट सोसायटीज वाले हाई कोर्ट में चले गए और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस नीति पर सरकार दोबारा से विचार करे ताकि प्राईवेट सैक्टर में जो रूटस

हैं जोकि वायबल नहीं हैं, बंद हो रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में अपने ओफिसर्ज की एक कमेटी बनायी है वह कमेटी इस मामले को पूरी तरह से ऐग्जामिन कर रही है। मार्च के अंत तक हम इस बारे में नयी नीति ला रहे हैं। जो पुराने रूटस दिए गए थे अगर वे वायबल नहीं हैं तो उनको वायबल करने के लिए हम वे रूटस और बढाएंगे तथा नये रूटस जिन पर बसिज नहीं जा पा रही हैं उन पर भी प्राईवेट आपरेटर को बसिज चलाने देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मार्च के अंत तक 800 नयी बसिज भी हम ऐड कर रहे हैं। जिन–जिन रूटस पर बसिज नहीं जा पा रही हैं उन पर हम नयी बसिज भी लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च के अंत तक हमारे हरियाणा में हरियाणा रोडवेज की बसिज की डिमांड की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, भिवानी हल्के में रूपगढ–झरवाही–नंदगाव और अजीतपुर ऐसे गांव हैं जहां पर न तो हरियाणा रोडवेज की बसिज चलती हैं और न ही प्राईवेट बसिज चलती हैं। स्पेशली जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो उस वक्त हजारों बच्चे सड्कों पर बसिज की इंतजार में खड़े रहते हैं। अगर कोई प्राईवेट वाहन उनको मिल जाता है तो वे उसमें बैठ कर अपने स्कूलों में चले जाते हैं वरना वे वहीं पर खड़े रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस तरह के रूटस पर आप

कब तक बसिज का प्रबन्ध कर देंगे ताकि जनता की परेशानी दूर हो सके।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, जो बात मान साहब ने कही है वही हर विधायक की शिकायत हो सकती है। कुछ गांवों में अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसिज नहीं जा रही हैं इसके दो ही कारण हैं। एक तो हमारी बसिज की कमी हैं और दूसरे सोसायटीज को जो रूटस दिए हुए हैं उन्होंने वे बंद कर रखे हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए ही हमने एक कमेटी बनायी है। स्टुडैंट्स के लिए तो हम विशेष रूप से रूटस देकर उनका स्कूल भिजवाने का काम कर रहे हैं।

श्री अमीर चंद मक्कडः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्राइवेट ऑपरेटरों को रूट्स दे रुखे है और वे उन रूट्स पर सही ढंग से नहीं चलते क्या उनके रूट्स कैंसिल करने की सरकार के पास कोई तजवीज है क्योंकि बसें न होने की वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो नयी पालिसी बना रहे हैं उसमें नये तौर पर जी०टी० रोड पर कितने किलोमीटर का रूट देने का प्रावधान हैं। मेरे हल्के के गांवों में हांसी से गढ़ी, बटोर, सीसर, खरबला, अय और मंगरहेडी का रूट दिया हुआ है लेकिन मेरे हल्के के लोगों की यह मांग है कि हांसी से सीधा मेहम का रूट दिया जाए। क्या रूट बदलने की कोई तजवीज नयी पॉलिसी में है यह भी मैं जानना चाहूँगा?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैंनें पहले ही इस बोर मै बता दिया है कुछ गांवों में ऐसी प्रौब्लम्ज हैं। जहां पहले इसमें दस किलोमीटर स्टेट हाइवे पर प्राईवेट रूट्ज चल सकता था उनको और वायबल बनाने पर पुनर्विचार करते हुए 29 किलोमीटर तक का हमने प्रौविजन किया था लेकिन वह मामला हाई कोर्ट में चौलैंज हुआ और कोर्ट ने उसकी सीमा 29 किलोमीटर से घटाकर 24 किलोमीटर कर दी है। मैं माननीय विधायक साथी को बताना चाहूँगा कि उससे ज्यादा हम उस सीमा को अब नहीं बढ़ा सकते हैं। जो नयी नीति हम बना रहे हैं उसमें हम विचार कर रहे हैं कि इसको किस तरह से वायबल बनाया जाए कि कोई भी रूट बगैर चले न रहे और जहां आज के दिन हम बसें नहीं चला पा रहे हैं उन रूट्स को या तो कैंसिल किया जाएगा या उन पर बसों को चलाया जाएगा, ऐसा हम हाउस में विश्वास दे रहे हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यकक्ष महोदय, दो साल पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा पैकेज देकर प्राइवेट ऑपरेटर्ज के रूट्ज को वायबल बनाने की कोशिश की थी लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं हुआ। हल इसलिए नहीं हुआ है कि जहां तक मैं समझता हूँ इसमें बिलफुल डिफॉस्टर्स हैं और जब तक सरकार उन पर कंट्रोल नही करेगी, उन पर प्रतिबंध नहीं लगायेगी तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसमें कुछ ऑपरेटर्ज तो वायबिलिटी न होने की वजह से नहीं चल पा रहे हैं

वे कहते हैं कि बच्चे ढोने में कुछ बचता नहीं है। इस समस्या का समाधान नयी पॉलिसी में किया जा सकता है। उसका बैस्ट हल यह है कि 1 –2 रूट सरकार के हों और 2–3 प्राइवेट ऑपरेटर्ज के हों ताकि कंपीटिशन भी रहे और जनता को सुविधा भी रहे।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो फैसला रूल्ज के मुताबिक लिया गया था उसमें हम जहां प्राईवेट सोसायटीज की बस के रूट थे वहां सरकार रोडवेज की बसिज नहीं चला सकती थी। इस जरूरत को समझते हुए यदि प्राइवेट सोसायटी वाले बसिज न चलाएं तो यह सरकार का दायित्व बनता है कि वहां हम बसें चलाएं। जो नयी नीति हम बना रहे हें उसमें हम विचार कर रहे हैं और आप सभी सदस्यगण के सुझाव लेकर ही नयी नीति तैयार की जाएगी।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मेरे हल्के के नाहड ब्लॉक के गवर्नमैंट कालेज नाहड में लगभग 2 हजार बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से 1200 तो छात्राएं ही पड़ती हैं। वह रूट सहकारी समिति की बसिज को अलाट किया गया है लेकिन कोई भी बस वहां से होकर नहीं निकलती है। हमने पिछले दिनों कह सुनकर एक दो बार सरकारी बस उस रूट पर लगवाई थी, अब वह बस भी वहां से होकर नहीं निकलती हैं। बसिज वाले कोताही कर जाते हैं और बाई पास से होकर ले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि जो रूट रिवाड़ी वाया नाहड, कुहाड और बहु का है वहां सहकारी समिति की बसों का प्रबन्ध किया जाए। जैसा मान साहब ने भी बताया छै मेरे हल्के में भी लड़कियां इतनी दूर साइकिल से पढ़ने जाती हैं या जीपों में लटककर जाती हैं इसके बावजूद भी हमारी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। कृपा करके इस समस्या का समाधान निकालने का कष्ट करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह भी सेम क्यैश्चन है। इन प्राइवेट बसिज को वाच करन के लिए कि ये पक्के तीर पर उसी रूट पर चलें जो उनको अलाट किया गया है उसके लिए हमने अपने विभाग में अभी एक इकोर्समैट विंग बनाने का प्रयास किया है और उसके तहत आर०टी०ए० लगा रहे हैं वे चौक करेंगे। सरकार से हमने इसकी अप्रूवल ले ली है और इन पदों के लिए हमने ऐडवर्टाइजमैंट भी दे दी है और बहुत जल्द ही ये अधिकारी लग भी जाएंगे और उम्मीद है कि यह जो समस्या आ रही है यह खत्म हो जाएगी और यदि इसके बावजूद समस्या रह जाएगी तो वहां सरकार बसें लगाने का प्रयास करेगी। श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने सदन में जो अश्वासन दिया है कि एक कमेटी बनाई है जो बसों के रूट्स के बारे में फैसला करेगी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के अन्दर है जहां बसें ठीक तरह से नहीं चल पा रही हैं। इसके बारे में मैं

यह कहना चाहता हूँ कि जिला के डिप्टी कमीशनर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में उस एरिया के विधायक को चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हो और वहां के जिला परिषद् के सदस्य को शामिल किया जाए और रूट्स की जो भी दिक्कत हो उस बारे में ये सभी सदस्य बैठकर फैसला कर लें।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, इस बारे में मंत्री जी ने बता दिया है कि आर०टी०ए० और दूसरे अधिकारी हैं वे सारे एरेंजमैंट् स को देखेंगे he will take more seriously. हाउस की जो चिन्ता है उसको मंत्री जी समझ रहे हैं जो आप कह रहे हें उस संबंध में मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री उदयभानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हर जगह पर बसों के रूट्स की बहुत दिक्कत है और मान साहब का यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी रूट्स के लिए सब जगह यही पोजीशन है। सभी रूटों पर मेरे हल्के में भी यही पोजीशन है चाहे वह पलवल–हसनपुर हो, होडल–हसनपुर और पामीखेडा–हसनपुर। इससे जाहिर हे कि चाहे प्राईवेट बसें हों या सोसायटीज की बसें हों ये सारी लाल में चल रही है। इसी वजह से बसें नहीं चलती अगर वे प्रोफिट में होती तो निश्चित तौर से चलती। इसके समाधान के लिए सरकार कोई तो रास्ता निकाले जिससे वे बसें लास में न रहें और उनको रोजगार भी मिले।

श्री अध्यक्षः अभी मंत्री जी ने बताया तो है कि जो पहले 10–11 किलोमीटर का एरिया था उसे 24 किलोमीटर किया है इसी बात को लेकर कि they can ply on the appropriate routes.

श्री उदयभानः अध्यक्ष महोदय, सरकारी बसें भी नहीं चल रही हैं और प्राईवेट वसों को रूट दे रखे हैं उन रूट्स पर सरकारी बस नहीं चल सख्ती हैं।

श्री अध्यक्षः आपका क्यैश्चन भी वही है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की शिकायत वाजिब है इसलिए सरकार ने इस पर गौर किया है इसीलिए कमेटी बनाई है। माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव आयेंगे उन पर भी सरकार विचार करेगी। लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जो इतनी जल्दी नहीं हो सक्ता। कोई न कोई नीति बनाकर ही चलना पड़ेगा। सरकार एप्रूव कर देगी उसके बाद ही हमारा प्रयास यह है कि जितनी चिन्ता इनको है सरकार को भी इसकी बड़ी भारी चिन्ता है, डिपार्टमैंट को भी चिन्ता है कि जनता की सुविधा के लिए हम गाँव–गाँव तक बसें प्रोवाईड कर सकें। चाहे वह प्राईवेट सैक्टर की बसे हो चाहे वह सरकार की बसें हों।

हिन्दु कन्या महाविद्यालय, जगाधरी तथा राजकीय महाविद्यालय बरवाला के विधार्थियों का अभिनन्दन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हिन्दु

कन्या कॉलेज, जगाधरी और गवर्नमैंट कॉलेज, बरवाला की छात्राएं दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। देश की एक अगली पीढ़ी जिनमें से शायद बहुत तो इस सदन में भी बैठेंगे और हरियाणा का और देश का नाम रोशन करेंगे, मैं उन सभी का सदन की तरफ से स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री राधे श्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि जहां पर रूट्स वायब्ल हैं वहां भी बसे नहीं जा रही हैं। जहां पर रूट्स वायब्ल हैं और प्राईवेट सोसायटीज को परमिट मिला हुआ है और सरकारी बसें भी बहुत हैं उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जीपें भरी हुई जाती हैं और एक्सीडैंट्स भी बहुत होते हैं।

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, यह नई बात नहीं है इस बारे में पहले बात हो चुकी है। श्री राधेश्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, जहां वायब्ल रूट्स हैं जहां बसें हैं उसके बावजूद भी अधिकारी उनको रूट के हिसाब से नहीं चलने देते। उसका क्या इलाज है। **श्री अध्यक्षः** मंत्री जी ने बता दिया है कि आर०टी०ए० और दूसरे अधिकारियों की जिम्मेवारी लगा दी है उनकी रिपोर्ट आयेगी उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 1209

(इस समय माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र चौधरी सदन में मौजूद नही थें, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

तारांकित प्रश्न सख्यां 1082

(इस समय माननीय सदस्य थी रणधीर सिंह महेन्द्रा सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1193

(इस समय माननीय सदस्या श्रीमती सुमिता सिंह सदन में मौजूद नहीं थी, इसलिए यह प्रश्न पूछा नही गया।)

New Sewerage Cleaning Mechines for Bhiwani

***1067 Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal to purchase new sewerage cleaning machine/supersuckers for Bhiwani ; if so, the time by which these machines are likely to be purchased ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir, the department has sent a demand for purchasing five supersucker machines to the Revenue Department under the Disaster Management Programme. The said machines will be purchased on receipt of requisite funds. One such machine is proposed to be stationed at Bhiwani.

I am also to inform the learned member that a new Hydraulic Sewer cleaning Machine costing about Rs. 18 Lacs has already been purchased during September 2008 for

Bhiwani Town. In addition, two such Sewer Cleaning Machines are also working in this town.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, भिवानी में सीवरेज की विकट समस्या है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर तीन साल से ज्यादा हो गये हें लेकिन सीवरेज की रिपेयर व सफाई नहीं हो पाई है। एक प्वायंट तो ऐसा हैं जहां पंजाब नेशनल बैंक के सामने अभी तक उस सीवर की सफाई नहीं हो पाई है। हालू मौहल्ला और दूसरे 11 प्वायंट्स ऐसे हैं जो हमने आईडैंटिफाई किए हैं जिनमें कुल्ले में कुछ समय के लिए सुपर सकर से यह सुविधा मिली थी पता नहीं वह किराये पर लिया था या इस सीवर को साफ करने के लिए कान्ट्रैक्ट पर बुलाया गया था। उसमें कुछ सुविधा कुछ समय के लिए मिली थी। अब फिलहाल जो मशीन का जिक्र किया गया है। अभी तक वह मशीन भिवानी में नहीं आई है। मुझे आज ही पता चला है कि उसकी बाडी लगनी है जो बहादुरगढ़ में स्टेशंड है। एक मशीन आज यमुनानगर से हमारे पास ट्रांसफर की गई है, यह मशीन ठीक नहीं रहती है। में समझता हूँ कि अगर 3 मशीनें ठीक से काम करें तो समस्या को सुलझाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सीवरेज की समस्या को सुलझाने के लिए मंत्री जी क्या–क्या कदम उठाएंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, भिवानी में सीवरेज की समस्या है माननीय सदस्य की यह बात वाजिब है। जो

सरकूलर रोड का इलाका है वह 90 परसैंट सीवरेज सिस्टम से कवर्ड है। जो नयू डिवैल्पड कॉलोनीज हैं वे मात्र 20 परसैंट सीवरेज सिस्टम से कवर्ड हैं। माननीय सदस्य ने पी०एन०बी० के अपोजिट जो प्वायट हैं उनकी चर्चा की, उसमें उठ इंच से 39 इंच का मेन सीवरेज है उसकी डिस्पोजल और मेन सीवरेज की रिपेयर का हमने ट्रैचलैस स्टाइल टैक्नोलोजी से करने का निर्णय किया है ताकि बिल्डिंग्ज को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि भिवानी में 2008–09 में 3.25 लाख रुपये सीवरेज की सप्लाई और नए सीवरेज डालने के लिए दिए गए थे। इससे पहले हमने 98 लाख रुपये दिए थे और इससे भी पहले 182 लाख 60 हजार रुपये हमने दिए थे तथा इसके लिए और भी बहुत से पैसों की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को पता भी है कि पिछले साल मुख्यमंत्री महोदय जी जब वहां गए थे तो उन्होंने सीधा यह राशि 98 लाख रुपये से बढ़ाकर 525 लाख रुपये कर दी थी। इस साल उतनी या उससे भी ज्यादा राशि हम सीवरेज के लिए देने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां–जहां बड़े शहर हैं या बहुत पुराने शहर हैं वहां समस्याएं भी पुरानी हैं। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां सीवरेज नहीं डाले गए। सुपर सकर मशीन जिसकी कोस्ट 80 लाख रुपये की है। हमारे पास यह मशीन नहीं थी इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि वे इसके लिए पैसे दे रहे हैं और जैसे ही यह मशीन आएगी, इससे पूरे सीवरेजिज की सफाई भी करवाई जाएगी।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जहां तक भिवानी का सम्बन्ध है यहां स्टार्म वाटर ड्रेनेज और सीवरेज अलग–अलग नहीं है। इस वजह से जब भी बरसात होती है तो करीब–करीब सारा भिवानी जल–मग्न हो जाता है जिसमें से कुछ कालोनीज ऐसी हैं वहां बहुत बुरा हाल हो जाता है। जैसे हाउसिंग बोर्ड कालोनी में मुख्यमंत्री महोदय स्वयं बरसात के मौसम में गए थे और उन्होंने स्वयं देखा है कि वहां क्या हालात थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि एक मास्टर प्लान बनाकर स्टार्म वाटर ड्रेनेज को अलग से बनाएंगे और सीवरेज को अलग से बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है इसलिए माननीय सदस्य मेरे पास लिखकर भिजवा दें, मैं इनको जवाब भिजवा दूंगा।

श्री रणधीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के दौरान मैंने प्रश्न दिया था कि मेरे इलाके में कुछ बूस्टिंग स्टेशन हैं जिनका कार्य सुचारू रूप से अभी तक चालू नहीं हुआ है। मंत्री जी द्वारा उस बारे में आश्वासन भी दिया गया था कि इनमें 20 मई तक पानी पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा।

Mr. Speaker : It is not possible to give reply at this time क्योंकि यह पृथक प्रश्न है।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा प्रश्न थोड़ा हटकर है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2006 में कोसली में विकास रैली में आए थे। ग्राम पंचायत बाखली के अंडर रेलवे स्टेशन कोसली आता है। विश्वकर्मा कालोनी, कोसली रेलवे स्टेशन, नई अनाज मंडी, नई बस्ती और सैनिक बस्ती, सब को मिलाकर 6000 वोट रेलवे स्टेशन कोसली के हैं। उसमें विशेषकर में विश्वकर्मा कॉलोनी का जिक्र करना चाहती हूँ। वहां गलियां कच्ची हें ओर वहां आज तक कोई नया पैसा नहीं लगा। वहां पर गंदा पानी, विशेषकर सीवरेज का पानी खड़ा रहता है। गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वे घर में टायलैट बनवा सकें इसलिए उनको घर से बाहर टायलैट के लिए जाना पड़ता है। आज से लगभग एक महीने पहले सीवरेज सिस्टम वहां बनना शुरू हो गया था। विश्वकर्मा कॉलोनी में कब तक सीवरेज सिस्टम चल जाएगा। सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल जाता है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि इस समस्या से वहां के लोगों को कब निजात मिलेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने पूछा है हालांकि ये पृथक प्रश्न है फिर भी मैं

उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कोसली में देश की आजादी और हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद से किसी सरकार ने सीवरेज डाला ही नहीं पहली बार माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कोसली का सीवरेज मंजूर किया है। पैसा भी दे दिया है यह बात माननीय सदस्या खुद मान रही हैं कि सीवरेज मौके पर बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि सीवरेज एक दिन में नहीं बन सक्ता यह एक लम्बी प्रोसैस का काम है it will take little time but I will assure her कि हम उनके पूरे के पूरे कोसली के इलाके के अन्दर सीवरेज डालकर देंगे। इस काम के लिए पर्याप्त पैसा हमारे पास है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे कि भिवानी के अन्दर मुश्किल आई हुई है दादरी में भी इसी प्रकार की मुश्किल पेश आ रही है। दादरी के अन्दर जो पुराना सीवरेज सिस्टम है वह लगभग 50 परसैंट लाक पड़ा हुआ है और उसकी वजह से ही दादरी शहर के अन्दर जब भी बारिश आती है तो उस समय यह सारी की सारी प्रॉब्लम राईज हौती हे। स्टार्म वाटर, ड्रेनेज और सीवरेज के लिए कोई अलग–अलग बन्दोबस्त नहीं किया गया है। जब तक हम सीवरेज सिस्टम को खोलेंगे नहीं तय तक न तो स्टार्म वाटर ड्रेनेज का कोई बन्दोबस्त हो सकेगा और

न ही सीवरेज का। इसके लिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कोई मशीन दादरी शहर के लिए भी परचेज करें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह पृथक प्रश्न है सुपर सकर मशीन हम खरीद रहे हैं जो भिवानी के लिए लगायेंगे स्वाभाविक है कि वह केवल एक शहर के लिए नहीं हो सकती। भिवानी जिले के अन्दर जो दादरी समेत बाकी के शहर हैं उनमें भी हम उस सुपरसकर मशीन को इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इन प्रिंसीपल दो करोड़ रुपये की अप्रूवल दे रखी है। उसके लिए आवश्यक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शायद इसी महीने होने वाली है। जैसे ही फ्लड कंट्रोल बोर्ड से हमें अप्रूवल मिल जायेगी उन मशीनज को बहुत जल्दी ही खरीदकर दो, तीन या चार जितनी भी हम खरीद पायेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको सप्रैड–आउट करें यह नहीं कि हम उसको एक ही शहर में स्टेंशड कर दें। हमारा प्रयास यह होगा कि हम उनको पूरे हरियाणा में जहां–जहां आवश्यक्ता है वहां–वहां पर इस्तेमाल करेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गोहाना के अन्दर जो सीवरेज की स्थिति इन्होंने स्वयं देखी है उन हालात को इम्प्रूव करने के लिए गोहाना में भी कोई मशीन नहीं है जिससे कि सीवरेज की सफाई हो सके। क्या मंत्री महोदय गोहाना के लिए

कोई ऐसी मशीन तजवीज करेंगे जिससे वहां के सीवरेज की सफाई हो सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह भी पृथक प्रश्न है फिर भी यह जानकारी एक माननीय सदस्य श्री रामफल चिड़ाना जी ने मांगी थी इसलिए मैंने इसे मंगवा लिया था और संयोगवश यह मेरे पास उपलब्ध भी है। अध्यक्ष महोदय, गोहाना में नया सीवरेज सिस्टम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 मई, 2007 को 421 लाख 50 हजार रुपया अप्रूव किया था। इसके सारे फण्ड्ज हमने रिलीज कर दिये हैं और उसमें से 554 लाख 27 हजार रूपया खर्च हो चुका है। पूरा गोहाना शहर इस समय समस्याग्रस्त लगता है क्योंकि अधिकतर शहर की खुदाई हो चुकी है। इसलिए वह समस्या अभी थोड़ी ज्यादा लगती होगी। लेकिन पैसा भी गोहाना को ज्यादा दिया गया है इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पूरे शहर की कवरेज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य अलग–अलग भी जानना चाहें तो महम रोड जो रेलवे क्रासिंग तक जींद रोड पर जाती है वहां हमने 4 जनवरी, 2009 को काम शुरू किया और 31 जुलाई, 2008 को पूरा कर दिया। इस कुल सीवर की लम्बाई 7 एम०एम० की 457 मीटर, एक 365 मीटर, एक 488 मीटर और 274 मीटर थी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ड्रेन नम्बर 8 से जो मेहम रोड है वहां तक 472 मीटर कलैर्कि्टग टैक, पम्प चेम्बरस, सक्रीनिग चौम्बरस ये 31 दिसम्बर, 2009 को काम पूरा हो गया है।

पम्पिंग मशीनरी लगाई जानी अभी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अलता मेहम रोड, अलता बरौदा रोड फाऊंटेन चौंक से बस स्टैण्ड 914 मीटर, 610 मीटर, 100 मीटर और 610 मीटर इसके चार पैच 30 अगस्त, 2009 तक पूरे कर लिये जायेंगे। वहां पर 55 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो वहां पर चल रहे हैं, मैं माननीय सदस्य को उनकी लिस्ट अलग से दे दूंगा।

Facilities and Posting of Doctors of Government Hospital, Safidon

***1084. Slid Bachan Singh A rya : Will the Health** Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the 50 Beds General Hospital in place of C.H.C., Safidon was inaugurated by the Hon'ble Chief Minister on 11th June, 2006 ; and

(b) whether it is a also fact that the existing staff of C.H.C. is still working there but the doctors, machinery staff and other facilities of General Hospital has not been provided there so far ; if so, the time by which these are likely to be provided ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala):

(a) Yes Sir,

(b) Sanction of additional staff and other facilities is under process and is likely to be provided in six months. अध्यक्ष महोदय, हमने लिखित जवाब में छ महीने के लिए कहा था

हम छ महीने की बजाए इसको 2 महीने मैं ही कर देंगे।

श्री बचन सिंह आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने दो महीने में ही इस काम को करने के लिए कहा है और मुझे उम्मीद है कि कर भी देंगे। सफीदों में 50 बैड का इतना बड़ा हॉस्पीटल बनाया है उसको जनरल हॉस्पीटल का दर्जा दिया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर डॉक्टरों के स्वीकृत 10 पदों में से 7 पद खाली पड़े हैं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहाँ पर डाक्टर कब तक नियुक्त हो जायेंगे और मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा हॉस्पीटल होने के बावजूद वहाँ पर पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है अध्यक्ष महोदय, वहाँ से जीन्द बहुत दूर पड़ता है, क्या सफीदों में पोस्ट मार्टम की सुविधा भी दी जायेगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक 50 बैड के अस्पताल की बात है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने नये नॉर्मस स्थिय किये हैं जिसके मुताबिक नये हॉस्पीटल में छ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियुक्त किये जायेंगे। जिसमें पिडियझोन, गाइनोकोलॉजिस्ट, सर्जन, जनरल फीजिसियन, स्किन स्पेशलिस्ट, ओरथो, एनेस्थीसिया, आई स्पेशलिस्ट, ये तो हम इनको देंगे ही। इसके साथ–साथ डेंटल डॉक्टर भी हम देंगे और दिन–रात की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराएंगे इसके लिए 4 एमब्बीध्यी०एस०

डाक्टर भी उस अस्पताल में होंगे। इसके साथ ही साथ दो अपै नये पद मंजूर करने के अलावा वहां पर हम एक फार्मासिस्ट का अतिरिक्त पद भी दे रहे हैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। अध्यक्ष महोदय, अलासाज्जं मशीन भी वहां पर लगाई जा रही है। उस. हॉस्पीटल की लैब को भी स्ट्रैंग्धन किया जा रहा है और आई केयर की सुविधा भी 'वहां पर दी जा रही है। इसके अलावा ब्लड स्टोरेज की सुविधा वहां पर पहले ही हम दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि पहली बार ऑन गोइंग प्रोसैस से हम डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा में डॉक्टरों की बड़ी भारी दिक्कत थी और वर्षों तक रही। पहले जहां पर 20 पद स्वीकृत होते थे वहां पर 2 ही डॉक्टर काम करते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई नीति बनवाई है और उसके मुताबिक हमने ऑन गोइंग रिकूटमैंट प्रोसैस किया है। अब हर महीने की 10 तारीख की नये डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए इंटरच्छू होते हैं चाहे उस दिन छुट्टी भी हो। इस प्रक्रिया के तहत पिल्ले समय में हम 535 डॉक्टर नियुक्त कर चुके हैं जिनमें से 4ध्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियुक्त करके विभिन्न अस्पतालों में लगाये हैं ये जनवरी में ही लगाये हैं? इसके अलावा इस प्रोसैस से 10 फरवरी, 2009 को हमने 74 और नये डाक्टर्ज लगाये हैं। जिनमें से 52 डाक्टर स्पेशलिस्ट हें। आज जब पूरी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है सरकार एक मर्डिल इम्पलायर के तौर पर नये स्पेशलिस्ट 'अप्तायंट करके न केवल माननीय सदस्य के हॉस्पीटल

में वल्कि पूरे हरियाणा के हॉस्पीटलों में नये डाक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद है कि इस प्रोसैस से कोई हास्पीटल नहीं बचेगा और हमारी सीव्यचकी० और पीव्यचब्सी० जहां हम डॉक्टर नहीं दे पाते उनमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। रही वात पोस्टमार्टम सुविधा की तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि वह भी इनके हॉस्पीटल में हम पोस्टमार्टम की सुविधा देने वाले हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह अपग्रेडेशन का सवाल सफईदी का है। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो अपग्रेडेशन पी०एचक्सी० से सीध्यचब्सी० और सीज्ज्वष्मी० से जनरल हास्पीटल में इसके लिए क्या नामर्स हैं और जो इन नार्मस को पूरा करते हैं क्या वहां पर अपग्रेडेशन की जाएगी? मेरे ख्याल से एक लाख तक की आबादी का नार्मस होगा वह एरिया जहां एक लाख से ज्यादा की आबादी है और वहां पर पी०एचब्सी० है तो क्या उसको सीम्पचकी० में अपग्रेड किया जायेगा। पानी–पतला के मेरे क्षेत्र में जहां लाखों की आबादी है, जहां किसान, मजदूर और गरीब लोग रहते हैं, क्या मंत्री जी वहां की पीव्यचब्सी० को सीब्धचब्सी० में अपग्रेड करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक अपग्रेडेशन के नार्मस का मामला है मेरे पास वह इनफोर्मेशन उपलब्ध है इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा और हमारे पास फण्ड्स भी उपलब्ध हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने

भी कहा है इसलिए मैं इनको अश्वस्त करना चाहूंगा कि वे नॉर्मस के मुताबिक हमें जमीन उपलब्ध करवा दें और मदद करेंगे तो वे जहां भी कहेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र में हम पीव्यचब्सी० खोल कर देंगे।

श्री के० एस० वर्माः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जनवरी में डॉक्टरों की भर्ती करके डिफरैंट होस्पीटल्म में लगाए गए हैं। शाहबाद में करीब छः महीने से मेरी गुजारिश थी और वहां पर तीन डाक्टर्ज भेजे गए थे लेकिन उन तीनों के तीनों डॉक्टर्ज ने अपनी ज्वायनिंग देकर वहां से अपने आर्डरज का कैंसलेशन करवा लिया। स्पीकर सर, वहां पर पिल्ले छः महीने से कोई सर्जन नहीं है। वहां अई पोजीशन यह है कि शाहबाद जीध्वी० रोड पर है। उसके साथ लाडवा और बण्डा दो और सड़कें आकर जुड़ती हैं तथा वहां पर एक्सीडैंट्स वहुत होते रहते हैं। वहां के अस्पताल में पिल्ले एक साल से कोई सर्जन नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन डाक्टर्ज के आर्डरज का कैंसलेशन हुआ है क्या उन्हें या किसी दूसरे सर्जन तथा डाक्टर्ज को लगाने की कृपा करेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अगले 15 दिनों के भीतर वहां पर डॉक्टर्ज नियुक्त कर देंगे? (विघ्न)

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, कोसली विधान सभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्र रहा है और ये वहां से चार बार पार्लियामैंट के मैम्बर रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी के अत्र श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी अब वहां से एम०पी० हैं वे अपने आप ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं किन्हीं अधिकारियों की कोई कोताही से कोसली गांव में पी०एच०सी० से होस्पीटल बनना है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर विकास रैली में 50 बिस्तर का होस्पीटल एनाउस करके आए थे लेकिन वहां पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि कोसली में 200 से 250 तक पेशैंटस हर रोज ओ०पी०डी० में आते हैं लेकिन वहां पर एक डॉक्टर तथा दो फार्मासिस्ट्स को नियुक्त किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करती हूं कि वहां पर स्टॉफ लगाया जाए और यह भी जानना चाहती हूं कि वहां पर होस्पीटल का काम कब तक चालू हो पाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सैपरेट प्रश्न है। मैं माननीय सदस्या से यह कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इनके पड़ोस से ही हैं इनके साथ ही अगला उनका क्षेत्र लगता है। अगर इन्होंने लिख कर दिया होता तो इनकी समस्या का समाधान हो जाता। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि यह लिख कर स्वास्थ्य मंत्री जी को भिजवा दें तो गौर करेंगे। जहां तक वहां पर कंस्ट्रक्शन का सम्बन्ध है, निर्धारित समय सीमा

के अन्दर वह हो जाएगा। स्पीकर सर, डॉक्टर्ज की जो कमी है उनके बारे में मैंने बताया है कि हर महीने की 10 तारीख को हम डॉक्टर्ज की नियुक्ति करेंगे। 500 के करीब डॉक्टरों के पद हम भर रहे हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि भर्ती की प्रक्रिया को सरल किया गया है डाक्टर्ज के जो भी पद है उनको लम्बे प्रोसैस से गुजरना पड़ेगा जल्दी ही उनकी भर्ती करके उनको काम दिया जाएगा और डाक्टर्ज की कमी को पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती अनीता यादव जी को कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल कर बात करें और अगर जरूरत हो तो वे मुझ से भी बात कर सकती हैं। केवल विधान सभा में प्रश्न पूछने तक ही सीमित न रहें। अपने हल्के की चीजों कै बारे में विधायकों की अपनी जिम्मदारी होती है इसलिए वे विधान सभा में प्रश्न पूछने से पहले कन्सर्ड मंत्री से बात करें और जरूरत पड़े तो मुझ से बात कर सकते हैं जो मी हल हो सकता होगा वह कर सकते हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्ज की बहुत कमी है मैंने इस बारे में पिछले सैशन में भी सवाल पूछा था।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में मंत्री जी ने अभी जवाब दे तो दिया है।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसलः अध्यक्ष महोदय, वहां पर इंस्ट्रमैंटस की बहुत कमी है और वहां पर 30% से ज्यादा मरीजों के आपरेशज होते हैं। काफी समय से इंस्ट्रूमैंटस खरीदने के लिए प्रोसैस चल रहा है लेकिन वहां पर लेटैस्ट इंस्ट्रूमैंटस नहीं खरीदे जा सके हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात लिखकर स्वास्थ्य मंत्री जी को भिजवा दें हम अगले 15 दिन में डाक्टर्ज की नियुक्ति कर देंगे क्योंकि अब डॉक्टर्ज और स्पैशलिस्ट्स की कोई समस्या नहीं रहेगी जल्दी से जल्दी इन पदों को भर दिया जाएगा। जहां तक मैडीकल ऐक्विपमैंट्स की बात है, उसके लिए परचेज का प्रोसीजर है। आप इस बारे में लिख कर माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया जी को भिजवा दें। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 202.31 करोड़ रुपये की लागत से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। आज के दिन 95 अस्पताल, 302 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज, 1502 सब–सैंटर्ज इस सरकार के बनने के बाद बनाए गए हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 8 हॉस्पिटल्ज 3 ट्रामा सैंटर्ज जिनकी ये चर्चा भी कर रहे थे 8 कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर्ज, 68 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज, 79 सब–सैंटर्ज 202 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं जो इस साल के अन्दर बनकर पूरे हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, यह जो रिवाल्विंग इम्पलायमैंट की स्कीम है यह बहुत बढ़िया स्कीम है। क्या पैरा मैडीकल स्टाफ के बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं ? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर एक्स–रे की मशीनें तो हैं लेकिन उन मशीनों को चलाने वाला स्टॉफ नहीं है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार सी०एम०ओ० को यह हक दे दे कि जब तक परमानैंट नियुक्ति न हो जाए तब तक डी०सी० रेट पर इनको लगाने का प्रावधान करें ताकि यह जो इम्बैलेंस है वह खत्म हो जाए।

श्री रणदीप सिहं सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो समस्या है वह जायज है। मैं भी अपने को इनके साथ जोड़ता हूं क्योंकि पैरा मैडीक्स भी डाक्टरों के साथ महत्वपूर्ण हैं। उनके बगैर कोई भी अस्पताल चाहे वह पी०एच०सी० हो या सी०एच०सी० हो कामयाब नहीं हो सकता है। बहुत सारे पैरा मैडिक्स और स्बोर्डिनेट स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इस सरकार के आने से पहले यहां पर एक बीमार सरकार रही थी जिसने स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई काम नहीं किया था। हमारी सरकार आने के बाद अब इन दोनों पर बहुत काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनको नोट कर लिया गया है और मैं इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से कहूंगा कि इस पर विचार कर लें।

Repair of Canal

***1041. Shri Radhey Shyam Sharma Amar:** Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal to repair the canal of villages Moround, Niyamatpur, Gothri, Amarpur, Budhwal ahead the pump house near Bamanwas Kheta of Nawalpur distributary ; if so, the time by which it will be repaired ;

(b) whether there is any proposal to supply the water ahead of the village Bhungarka through the Nawalpur distributary ; and

(c) whether there is any proposal to supply the water in the Shahbajpur-Alipur area through the Shahbajpur distributary ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes Sir, there is a proposal to repair the canal of villages Moround, Niyamatpur, Gothri, Amarpur, Budhwal ahead of Pump House near Bamanwas Kheta of Nawalpur distributary which is actually called Nolpur distributary. The repair will be completed by 30-06-2009.

(b) No Sir, water already reaches ahead of village Bhungarka through Nawalpur distributary that is upto viiiage Mohanpur during the present month.

(c) Yes Sir, there is a proposal to supply water in the Shahbajpur-Alipur area through the Shahbajpur distributary.

श्री राधे आम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो नवलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी है, वह बूडवाल, गोठड़ी और नियामतपुर तक जाती है। वह आज तक दबी हुई है। उसकी ईटें भी उठा कर ले गए हैं। वहां पर किसी ने एक कस्सी भी नहीं मारी है और न ही कोई काम हुआ है और उसको देखा भी जा सकता है। यह जो इन्होंने इस बारे में 30 जून का समय दिया है कि उसको पूरा कर देंगे, जब वहां पर काम ही शुरू नहीं हुआ, उसका कोई टैण्डर ही नहीं हुआ है तो उसको पूरा कैसे कर देंगे?

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, मंत्री जी ने आपको समय दे दिया है और यह उनका काम है कि उन्होंने इसको कैसे पूरा करना है। आप बैठ जाएं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ जिले के अन्दर 66 के करीव टेल्ज हैं। हमारी सरकार के आने से पहले उनमें से सिर्फ 9 टेल्ज तक ही पानी जाता था। हमने इन चार सालों में 66 टेल्ज में से 38 टेल्ज तक पानी पहुंचा दिया है और जो बाकी रह गई हैं उनमें भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

Completion of Railway Over Bridges

***1111. Sh. Dharambir :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the time by which the Railway

Over Bridges at the level crossing of Daultabad Gurgaon road and Dhankot - Basai road are likely to be completed.

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : The Railway Over Bridges at the level crossings of Daultabad Gurgaon road & Dhankot-Basai road (Gurgaon - Farrukhnagar road) pertaining to PWD (B & R) are likely to be completed by 31.05.2009.

श्री धर्मवीरः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो जवाब में लिखा है कि "likely to be completed in May." Is it the definite date are you to proceed further ?

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नहीं है। On the floor of the House, the Minister has given the assurance कि इस टाईम तक काम हो जाएगा। अब आप और क्या चाहते हैं?

तारांकित प्रश्न संख्या 1205

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय सदन में माननीय सदस्य थी नरेश यादव उपस्थित नही थे।)

PHC at Sihol

***1123. Sh. Udai Bhan :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to set up a Primary Health Centre (PHC) at Sihol in Hassanpur consitituency ; if so, the time by which the work of the said Primary Health Centre will be completed ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. However, time limit cannot be prescribed. अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने इसकी मंजूरी दे दी है, पैसा पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) को दे दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रुवल दे दी गयी है। 11.11.2008 को हमने टैडंर भी क्त दिए हैं। इन टैंडर्ज के रेट ज्यादा थे इसलिए अब फैश टैंडर्ज रि–कॉल किए गए हैं। ई०आई०सी० और सैक्रेटरी, पी०डब्ल्यू०डी०(बी० एण्ड आर०) ने मुझे बताया है कि एक हफ्ते के अंदर–अंदर टैंडर फाईनल करके इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देंगे।

श्री उदयभानः स्पीकर साहब, मंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसम्बर, 2005 को यह स्कीम अनाउंसमेंट की थी। सवा तनि साल हो गये हैं लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। अब माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इसके टैंडर्ज कॉल कर लिए गए हैं। मैं अपिके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी शुरूआत आप कैसे कराएगे और कब से यह काम शुरू करवा देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, एक महीने के अंदर–अंदर हम इसकी कंस्टक्शन शुरू करने का प्रयास करेंगे।

Replacement of L.T. Wires

***1102. Maj. Nirpender Singh Sangwan :** Will the Power Minister be pleased to state whether it is a fact that the Hon'ble Chief Minister has announced the replacement of L.T. wires in the old city of Dadri ; if so, the time by which the said L.T. wires are likely to be replaced ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, the announcement made by Hon'ble C.M. Haryana was "Replacement of Old Iron Electric Poles & Cables of Dadri Town". Accordingly, 142 nos. old iron electric poles and 21.595 kms. conductor of 4 nos. 11 KVHT feeders have been replaced at a cost of Rs. 43.32 Lacs.

Besides, a comprehensive scheme has been prepared and submitted to the World Bank for funding to further strengthen the existing 11 KVHT network and to revamp the LT distribution system in Dadri Town. Under this scheme, all the remaining iron poles, old cables and conductor will be replaced. The scheme cost is Rs. 27.10 crores and the work is likely to be completed by March 2010. Speaker Sir, 1 want to tell the hon' ble Member that in addition thereto, Government of India has now revised norms for APDRP whereby they are giving us funding for all towns with a population more than thirty thousand or more. We have also added Dadri Town in this scheme. Chief Minister has taken a review in this regard and a meeting is being called shortly by Government of India. Hopefully, we will get money for Dadri Town from there also.

मेजर नृपेद सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, यह बहुत अच्छी बात है कि दादरी के पुराने शहर में एल०टी० तारों के

बदलने का कुछ काम हो चुका है और कुछ होने वाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह काम कब शुरू होगा? स्पीकर साहब, दादरी के अंदर एल०टी० तारों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं इसलिए मंत्री जी कब तक इनको बदलवाने का काम शुरू करवा देंगे? जब तक यह काम पूरा नहीं होता तब तक उनके लिए कुछ न कुछ इंतजामात किया जाना चाहिए ताकि वहां पर हादसे न हों क्योंकि जो बिजली वाले . अधिकारी हैं वे असमर्थ हैं और वे कहते हैं कि unless we get proper equipment, we cannot do anything.

Shri Randeep Singh Surjewala Speaker Sir, I have already answered the question that the money required for Dadri Town is Rs. 2710 Lacs and for that we have posed to the World Bank and have given him a deadline by which we will complete it. However, hon'ble Chief Minister has directed us that it has to be done on a war-footing and possibly earlier. That's why we have also posed this to APDRP for similar funding. Wherever, we get funding quickest, we start the work.

श्रीमती अनीता यादवः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है इसलिए जबाव तो आ ही गया है लेकिन एक पर्टीकुलर साल्हावास गांव की ढाणी में भी लोहे के पोल्ज हैं इसलिए इनको भी बदलने का मामला सरकार अपने प्रोग्राम में शामिल कर ले।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, माननीय सदस्या, इस बारे में लिखकर भिजवा दें, मैं अपने अधिकारियों से

बोलूंगा कि वे इस को प्राथमिकता पर लेकर थे पोल्ज चेंज कर दें।

तारांकित प्रश्न संख्या 1089

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय सदन में माननीय सदस्य डा० सुशील इन्दौरा उपस्थित नहीं थे।)

Upliftment of SC, BC and Women

***1053. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister be pleased to state the year-wise details of the steps and measures taken by the State Government for the upliftnient of the Scheduled Castes and Backward Classes and women in the State since the year 2000 till date ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को मुबारिकबाद देना चाहूंगा। हालांकि जवाब वहुत लम्बा है और हमने टेबल की शक्ल में यह सदन में रखा है। लेकिन जवाब यह बहुत वाजिव है। स्पीकर साहब, गरीब और आम आदमी जो इस सरकार की प्राथमिकता है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। Sir, I have laid the answer the shape of a table on the floor of the House. A statement is laid on the table of the House.

Statement showing steps and measures taken for the upliftment of Scheduled Castes and Backward Classes by the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes

Department, Haryana.

A number of schemes of the State Govt. were in operation before 2000-01 and have continued till date with enhanced budget. The names of the main schemes are given below :—

1. Housing scheme for Scheduled Castes and Denotified Tribes to facilitate housing for BPL SCs.

2. Post Matric Scholarship to Scheduled Castes students funded by Govt. of India and State Govt. for facilitating SC students to study diploma/degree after 10th class whose parents income is below one lakh per annum.

3. Award of Scholarship and Reimbursement of Tuition Fee/Examination Fee for Scheduled Castes students in 9th to 12th classes.

4. Scholarship / Opportunity Cost to Scheduled Castes Students in 6th to 8th Classes.

5. Grant for the purchase of stationery articles to Scheduled Castes students in 6th to 12th classes.

6. Award of Scholarship and Reimbursement of Tuition Fee/Examination Fee for Backward Classes students in 9th to 12th classes.

7. Tailoring training to Scheduled Castes widows/destitute women/ girls.

The year-wise detail of new steps and measures taken by the State Govt. for the Welfare of Scheduled Castes

and Backward Classes from the year 2000 to 2008 is given as under : -

2000-01 :

No new step was taken.

2001-02 :

1. The subsidy amount given to Scheduled Castes and Denotifred Tribes persons under Housing Subsidy Scheme was enhanced from Rs. 5000/- to Rs. 10,000 I- w.e.f 1.4.2001.

2. The rate of scholarship/opportunity cost given to SC students in 6th to 8th classes was enhanced from Rs. 15/- p.m. to Rs. 30 p.m. w.e.f. 1.4.2001.

3. The rate of scholarship given to Scheduled Castes and Backward Classes (Block-A) students in 9th to 12th classes was enhanced from Rs. 20/- p.m. to Rs. 40. p.m. w.e.f 1.4.2001.

4. The rates of stationery grant given to Scheduled Castes students in 6th to 8th classes enhanced from Rs. 40/- p.a. to Rs. 80 p.a. and in 9th to 12th classes were enhanced from Rs. 60/- p.a. to Rs. 120/- p.a. w.e.f 1.4.2001.

2002-03 :

1. New scheme namely Providing of free residential facilities to the meritorious Scheduled Castes students was launched. Under this scheme besides scholarship @ Rs. 700/- p.m., the students are also given Rs.

2,000/- p.a. for purchase of books & stationery and Rs. 1,500/- p.a. for miscellaneous expenditure are given to the students.

2003-04 :

No new step was taken.

2004-05:

—do-

2005-06 :

1. New scheme namely Indira Gandhi Priyadarshani Vivah Shagun Yojna was launched w.e.f. 14.5.2005. Under the scheme, the BPL SC/Denotified Tribe/Tapriwas Jati persons and BPL widows of all sections of society are given grant-in-aid @ Rs. 5,000/- for the marriage of their daughters and BPL persons of other sections of society are given grant-in-aid @ Rs. 5,100/- for the marriage of their daughters. A widow who wants to re-marry is also eligible to get benefit under the scheme.

2. New scheme namely Dr. Ambedkar Medhavi Chhatra Yojna was launched. Under the scheme 5,000 Scheduled Castes, 1,000 Backward Classes (Block 'A') and 750 Backward Classes (Block 'B') students who secure 60% or more marks in 10th Class are given scholarship @ Rs. 1,000/- per month (for 10 months) in 10+1 & 10+2 and Diploma courses for 2 years.

3. The rate of scholarship/opportunity cost given to Scheduled Castes students in 6th to 8th classes was

enhanced from Rs. 30/- p.m. to Rs. 75 p.m. w.e.f 1.1.2006.

4. The rate of scholarship given to Scheduled Castes students in 9th to 12th classes was enhanced from Rs. 40/- p.m. to Rs. Rs. 100/- p.m. w.e.f. 1.1.2006.

5. The rates of stationery grant given to Scheduled Castes students in 7th, 8th classes were enhanced from Rs. 80/- p.a. to Rs. 50/- p.a. and in 9th to 12th classes were enhanced from Rs. 120/- p.a. to Rs. 200/p.a. w.e.f. 1.1.2006.

6. The Rate of interest charged by Haryana Scheduled Castes Finance & Development Corporation and Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam from the loanees under various schemes reduced from 6% to 5% per annum for those who are regular in the repayment of their loans.

2006-07 :

1. The subsidy amount given to Scheduled Castes and Denotified Tribes persons under Housing Subsidy Scheme for construction of house was enhanced from Rs. 10,000/- to Rs. 50,000/- and a provision was made for grant of Rs. 10,000/- for repair of house w.e.f. 1.4.2006.

2. The rates of financial assistance given to Scheduled Castes and Backward Classes candidates for obtaining coaching for higher competitive/entrance examinations through private reputed Insitutions were enhanced from Rs. 3,000-4,000 to Rs. 8,000-10,000 w.e.f 1.2.2007. The income ceiling for obtaining benefit under this

scheme was also enhanced from Rs. 44,500/- to Rs. 1.00 lac p.a.

3. The rate of incentive given under the Inter-caste Marriage scheme was enhanced from Rs. 25,000/- to Rs. 50,000/- w.e.f. 22.9.2006. One of the spouse should be Scheduled Castes and permanent resident of Haryana State for obtaining benefit under the scheme.

4. New scheme namely Housing Finance Scheme for Backward Classes and Minorities was launched under which a soft loan of Rs. 1.00 lac is given at the interest rate of 3% p.a.

2007-08

1. The rates of incentive given to Scheduled Castes Students under the scheme Meritorious incentive to SC Students who get 1St Div. from Post Matric to post Graduate Classes including medical/Engg./ Agri/Vety. etc. were enhanced from Rs. 1,000, 1,500 and Rs. 2,000 to Rs. 3,000, 4,500 and Rs. 6,000 respectively for different clases w.e.f. 1.42007.

2. Centrally sponsored Post Matric Scholarship scheme for OBC students was implemented in the State. Under this scheme besides scholarship @ Rs. 90/- per month to Rs. 425/- per month in different classes, the compulsory non refundable fees is also reimbursed to the students. The students whose parents income does not exceed Rs. 44,500/- are eligible to get benefit under the scheme. Under the scheme over & above the committed liability of the State Govt., 100% funds are provided by the Central Govt.

3. The rates of scholarship given to the students residing in the six hostels run by this Department at Ambala, Karnal, Rohtak, Rewari and Faridabad for the students whose parents are engaged in unclean occupations and at Jind for the students of Denotified Tribes/Tapriwas Jatis were enhanced from Rs. 400/- per month to Rs. 650/-per month w.e.f. 1.4.2007.

4. Centrally sponsored scheme namely Construction of OBC Girls/Boys Hostel was launched under which the expenditure is shared on 50 : 50 basis by the Central and State Governments. The cost of construction of hostel is calculated on the basis of PWD rates.

5. The rate of incentive given to Panchayats for doing outstanding work for the welfare of Scheduled Castes was enhanced from Rs. 5,000/- to Rs. 50,000/-.

6. The Government waived off the normal and penal interest of the loanees of Haryana Scheduled Castes Finance & Development Corporation and Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam, if the loanees made the payment of the entire outstanding principal amount upto 16th March, 2008.

7. The State Govt. opened separate minor budget head — 789 — for Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) under major functional head of concerned departments from the year 2007-08. The SCSP funds have been made non divertible and the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department has been declared as nodal department for formulation, implementation and monitoring of SCSP.

2008-09 (Upto December, 2008) :

1. With the objective to streamline the educational schemes being implemented for the Scheduled Castes students and to provide more benefit to the students, the following schemes of this department worth Rs. 39.00 crores have been merged with the Education Department. As a result each Scheduled Caste boy in school will get stipend @ Rs. 100/- per month and each girl @ Rs. 50/- per month in class 1st. This will go upto Rs. 400/- in class 12th. Besides stipend, the SC boys and girls will also get annual allowance of Rs. 740/- to Rs. 1450/- in different classes from 1st to 12th class:

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of the Scheme	Approved outlay 2008-09
1.	Scholarship/opportunity cost to Scheduled Caste students studying in 6th to 8th classes.	1500.00
2.	Award of scholarship & reimbursement of tuition fees for Scheduled Castes students in 9th to 12th classes.	1200.00,
3.	Grant for the purchase of stationery articles to SC students in Post 10+2 and Post Graduate classes	600.00

4.	Grant for the purchase of stationery articles to SC students in 6th to 12th classes	600.00

2. A new scheme namely Upgradation of the Typing and Data Entry Skill of Scheduled Castes and Backward Classes Unemployed Youth through Computer Training was launched w.e.f. 15.12.2008 under which the SC and BC candidates will be given one year training and during the training they will be given stipend @ Rs. 250/- per month. The candidates whose parents, income does not exceed Rs. 1.5 lac. p.a. arc eligible to get benefit under the scheme.

Statement Showing Steps and measures taken for upliftment of women by Department of Social Justice and Empowerment, Haryana.

1. Haryana pension to widows and destitute women scheme (widow pension) - Year wise revision of rate of pension is as under :—

Year	Rate of Pension
2000-2001	Rs. 200/- p.m.
2001-2002	No change
2002-2003	do
2003-2004	do
2004-2005	enhance to Rs. 200/- to 300/- p.m.
2005-2006	The Haryana Govt. has disbursed widow pension at double rate i.e.

	Rs. 600/- per beneficiary during the month of November, 2005 on the eve of Haryana Day and Dipawali.
2006-2007	Rate increased from Rs. 300/- to Rs. 350/-p.m. from 1.5.2006
2007-2008	-to change
2008-2009 upto 12/2008	do

2. Steps and measures taken in Departmental Institutions being run for widows/destitute women -

There are three Mahila Ashrams being run by the State Govt. at Karnal, Rohtak & Faridabad for widows and destitute women to provide accommodation, ration money, clothing, allowance & education and training and rehabilitation facilities to the inmates of these Institutions. During 2000-2001 ration money and clothing allowance was being given to each inmate of Mahila Ashrams @ Rs. 200/- and Rs. 50/- per month respectively. Besides a State After Care Home is also functioning at Karnal in order to provide institutional care, protection, Social Security, maintenance, education and training to the girls/women who have no means of subsistence. During 2000-2001 ration money for these inmates was being provided @ Rs. 500 per month. In addition to this marriage grant of Rs. 10,000/- was also being given to the inmate and their dependent girl of all above Institutions at the time of their marriage. Year wise detail of steps and measures taken by the Department are as under :—

Year	Steps and Measures
2000-2001	No new step was taken.
2001-2002	No new step was taken.
2002-2003	No new step was taken.
2003-2004	No new step was taken.
2004-2005	Ration meney for each inmate of Mahila Ashram Rohtak, Karnal & Faridabad was increased from Rs. 200/- to Rs. 275/- per month and clothing allowance from Rs. 50/- to 75/- per month since 1-4-04. Ration money of inmates residing in State After Care Home for girl Karnal was increased from Rs. 500 to Rs. 600 since 9/2004.
2005-2006	Ration money of single women (without encumbrances) was raised from Rs. 275/- to Rs. 425/- residing in Mahila Ashram since 1-8-05. State After Care Home, Karnal has been notified as Observation Home for girls under Juvenile Justice Act, 2000
2006-07	Ration money of inmates residing in State After Care Home for girl Karnal

	was increased from Rs. 600/- to Rs. 700/- since 1-1-07.
2007-2008	Marriage grant for inmates of Mahila Ashram was raised from Rs. 10,000/- to 15,000/- since 1.5.2007 Ration money for each inmate of Mahila Ashram has been revised from Rs. 275/- to Rs. 450/- and clothing allowance was increased from Rs. 75/- to Rs. 125/- since 1-1-2008.
2008-2009	No new step was taken.

Women and Child Development Department, Haryana

The year wise details of steps and measures taken by the State Govt. for the upliftment of women in state since the year 2000 till date is as under :

2000-01

Steps & Measures/Schemes started prior to 2000-01 and continued during the Year 2000-01

(on going schemes)

1. Kishori Shakti Yojna is being implemented to improve the health and nutrition status of Adolescent Girls and also to provide trainings for developing their vocational skills

2. Balika Samridhi Yonja was implemented with

the objective of raising overall status of girl child by providing post birth grant and scholarships for education.

3. Apni Bell Apna Dhan scheme was started to improve the status of girl child in the society.

4. National Maternity Benefit Scheme implemented to provide financial assistance to the pregnant women belonging to BPL

5. Integrated Child Development Service Scheme is being implemented in the State in 137 projects having 17444 AWCs under which services of supplementary nutrition, immunization, health check-up, referral services, health and nutritional education are being provided to Rs. 2.86 Lacs pregnant and nursing mothers along with other services.

6. Schemes of Training-cum-Production Centre for Women & Financial Assistance to Voluntary Organizations are being implemented to provide financial assistance to vol. orgs. for running training projects and generating awareness regarding eradication of social evils.

7. The Scheme of Working Women Hostels is being implemented to provide safe accommodation at economical rates to working women at district level.

8. UNFPA Assisted Integrated Women's Empowernment and Development Project/Programme for Advancement of Gender Equality (PAGE) aimed to being about a change in the present scenario by generating awareness, mobilizing women into self help groups and making intervention in the areas of health

and education to ensure women's survival, dignity and enhanced status in the society.

9. Anti Dowry Programme is being implemented to generate awareness against the deep rooted social evil of dowry in the State.

10. Awareness Generation and Social Mobilization

(i) Mahila Mandal Schemes-

Promotion and Strengthening of Mahila Mandals, Inter State study tours/exposure visits of Mahila Mandals, Incentive Awards to Mahila Mandals and Mahila Sammelan schemes are being implemented for creating awareness among rural women.

(ii) The year 2001 celebrated as Women's Empowerment Year.

11. National Programme on Improved Chulha implemented to provide subsidy to rural women for providing smoke-free atmosphere.

12. Swablamban (NORAD) scheme is being implemented to provide financial assistance to NGOs for running various trainings for women.

13. Swadhar Scheme is to provide shelter and rehabilitation services to needy women, especially the women in difficult circumstances like widow, destitute and deserted women, women ex-prisoners, victims of sexual abuse and crimes.

14. Short Stay Homes is to provide temporary shelter to the needy women and girls, who are exposed to moral danger or are victims of family discord.

15. Haryana State Commission for Women has been setup to protect the consittutional and legal rights of women and to redress the grievances of women.

16. Haryana Women Development Corporation is functioning to promote activities for women's development, awareness generation, vocational training and arranging institutional finance for self-employment of women.

17. Swa-Shakti Project was implemented in Sonipat, Jind and Bhiwani district for improving the socio-economic status of rural women through thrift and saving activities.

18. Women Awareness and Management Academy (WAMA), Rai was upgraded to the Regional Level Gender Training Institute. This institute is providing trainings on Gender Sensitization & other issues for grass root level workers.

19. Haryana State Social Welfare Board :—

(i) Awareness Generation Projects for Rural and Poor Women.

(ii) Family Counseling Centres

(iii) Condensed Course of Education for Women.

(iv) Short Stay Homes.

2000-01 : No new scheme was initiated.

2001-02 :

New steps

1. Swayamsidha, a centrally sponsored programme based on the formation of SHGs, in an integrated scheme for women's empowerment implemented during the year 2001-02, with the objective of women's empowerment through training on capacity building, awareness generation and economic empowerment activities.

2. Haryana Govt. has enhanced the financial norms of Supplementary Nutrition under ICDS from Rs. 1.73 to 2.50 per day per mother/ adolescent girls so that the protein and calories requirement could be ensured.

On going schemes

All other Steps & Measures/Schemes remained continued during the Year 2001-02.

2002-03 : New steps

1. Construction of Buildings for Anganwadi Centres —The scheme is being implemented to provide clean environment for women and children and creating assets for them.

2. Honorarium increased from Rs. 500/- to 1000!- for AWWs and Rs. 260/- to Rs. 500/- for Helpers per month by Govt. of India.

3. Sexual Harassment Committees have been

constituted in all Govt. Departments/Boards/Corporation to protect women from sexual harassment at their work place.

4. Creation of Core Consitutency in every village and town for eradication of social evils/women problem.

5. Administered oath to students of schools and colleges and other institutions against sex determination tests, female foeticide and dowry.

On going steps

All other Steps & Measures/Schemes remained continued during the Year 2002-03.

Schemes discontinued

(i) National Programme on Imporved Chulha Scheme discontinued by

(ii) National Maternity Benefit Scheme transferred to Health Department in Aug. 2002.

2003-04 : New steps

1. Special Additional Central Assistance-Pilot Project is being implemented to improve the nutritional status of low weight Adolescent Girls in Ambala and Yamunanagar district.

On going steps

All other Steps & measures/Schemes remained continued during the Year 2003-04.

2004-05 :

No new scheme was started.

All other Steps & Measures/Schemes remained continued during the Year 2004-05.

2005-06 : New steps

1. Ladli Scheme is being implemented to combat the problem of female foeticide and arrest the declining sex ratio in Haryana. A sum of Rs. 5000/- per year is invested on the birth of 2nd daughter for five years.

2. Award to Rural Adolescent Girls is being implemented in order to encourage the rural girls for pursuing higher education.

3. Best Mother Award Scheme is being implemented to encourage women for proper rearing of their children, especialy the girl child with a view to improve their nutrition and health status.

4. Honorarium increased from Rs. 1000/- to 1200/- for AWWs and Rs. 500/- to Rs. 600/- for Helpers per month by the Govt. of Haryana.

5. Sports Meet for Rural Women scheme is being implemented in the State for providing recreational and sport opportunity to the rural women.

6. Gender Sensitization Programme is implemented to sensitize the rural community on gender issues.

7. Conversion of Mahila Mandals into Self Help Groups Scheme was implemented to empower women through capacity building trainings like groups dynamics, account keeping, legal literacy, gender sensitization and social evils including aids.

8. **Girl Child Year 2006 :-**

The year 2006 was celebrated as "Year of the Girl Child". During this year different departments launched new programmes for girls and women in the light of decision taken by the State Govt. The brief details of decision taken and programme launched are as under :—

- A Women University namely "Bhagat Phool Singh Women University" established at Khanpur Kalan, Sonipat to encourage women towards pursuing higher education.

- EDUSAT connectivity being provided to all the Government Girls Senior Secondary Schools in the State.

- Providing electrification in all the Girls Primary Schools.

- Awards of Rs. One lac instituted for the Panchayats, which achieve the enrolment of 100% eligible girls in schools.

- Separate toilets for girls are being constructed in all Government Schools.

- Girl students in the State provided special concession facility to travel in Haryana Roadways buses. In a

month 5 single fares are charged instead of 10 single fares.

- "Janani Suvidha Yojna" launched for women living in urban slums.

- Health check-up of all school going girls upto the age of 18 years is being done and every girl child is being issued health card.

- 25 percent reservation made for girls in Industrial Training Institutes and Institutions of Technical Education.

- Merit based awards for girl students separately in ITIs/Polytechnics/ Engineering Colleges etc.

- Free Tool Kits/Books to girl students in ITIs/Polytechnics/ Engineering Colleges etc.

On going steps

All other Steps & Measures / Schemes remained continued during the Year 2005-06.

Schemes discontinued

- **The scheme namely Apni Beti Apna Dhan was discontinued in 2005-06. The Scheme of Apni Beti Apna Dhan was replaced by Ladli Scheme.**

- **Swa-Sbakti Project was discontinued in 2005-06.**

2006-07 New Steps

1. Constitution of Village Level Committees set

up to facilitate the implementation of programmes pertaining to development of women & children and these are converged with PRI's. About 6173 village level committee have started functioning.

2. Supplementary Nutrition started through women SHGs. Haryana Govt. dispensed with centralized system of procuring the RTE food items for the beneficiaries of ICDS and entrusted the responsibility of preparation of food items to women Self Help Groups/Mother's Groups w.e.f. 1.1.2007.

3. Sakshar Mahila Samooh (SMS), a group of educated women in every village formed to lend the necessary resource support to the Gram Panchayat and generates awareness on key issues of sex ratio, literacy, universalization of elementary education, health and nutrition, opportunities for economic empowerment for women etc.

4. Micro Credit through SMS in collaboration with Rashtriya Mahila Kosh (RMK). RMK has recognized SMS as an eligible NGO for the purpose of promoting micro credit and undertaken the responsibility of training of members of SMS. RMK also advances credit to the selected SMSs at cheaper rate of interest.

5. Honorarium of AWWs and Helpers increased from Rs. 100/- per month per year for 5 years by the state Govt.

6. Haryana Govt. has enhanced the financial norms of Supplementary Nutrition under ICDS from Rs. 2.50 to Rs. 5.00 per day per mother/ adolescent girls so that the

protein and calories requirement could be ensured.

7. Incentive Awards for Improvement in Sex Ratio is being implemented to curb the declining sex ratio in the State.

8. Balika Samman & Mahila Samman Samaroh was celebrated to recognize the women and girls achievers in various fields like education, sports, and cultural activities. These women and girls were honored by Hon'ble Chief Minister.

On going steps

All other Steps & Measures/Schemes remained continued during the Year 2006-07.

2007-08 New steps

1. Education Loan for Girls/Women scheme is implemented providing loan on cheaper rates to promote and encourage the girls for pursuing higher education at Graduate/Post Graduate/Doctoral/Post Doctoral level in the country and abroad.

2. Surakshit Bhavishya Yojna for Anaganwadi Workers and Helpers is implemented w.e.f 1-1-2008 under which Rs. 100/- is invested in LIC of India out of which Rs. 83/- are utilized for savings and Rs. 17/- are as risk premium for Anganwadi Workers and Helpers. A sum of Rs. 50000/- will also be paid on her sudden death.

3. Protection of Women from Domestic Violence Act (Setting up of Cells) is being implemented to combat the

problem of Domestic Violence in the State.

On going steps

All Steps & Measures/Schemes remained continued during the Year 2007-08.

Schemes discontinued

(i) The scheme of Conversion of Mahila Mandals in to SHGs discontinued.

(ii) Swayamsidha discontinued in March 2008.

2008-09

New steps

1. Honorarium increased by GOI from Rs. 1000/- to 500/- for matric pass AWWs and Rs. 500/- to Rs. 750/- for Helpers per month and enhancement of Rs. 500/- for AWWs and 250/- for helpers is under active consideration of the State Govt. Now the honorarium of an AWW will be Rs. 2500/- p.m and for Helper will be Rs. 1400/- p.m.

2. The retirement age of Anganwadi Workers and Helpers has been increased from 58 years to 60 years by the State Govt.

3. GOI has also enhanced the norms of SNP recently from Rs. 2.00 to Rs. 4.00 for children, Rs. 2.70 to Rs. 6.00 for severely malnourished children and Rs. 2.30 to Rs. 5.00 for pregnant and lactating mothers with immediate effect.

4. Special Scheme to Curb Anemia scheme is

implemented to curb anemia amongst women and children under which nutritional supplements i.e. lion and Folic Acid and De-worming tablets are to be provided to women and adolescent girls.

5. Manufacturing of Sanitary Napkin - State Govt. has setup Sanitary Napkin Manufacturing Units through SMSs in all districts to promote health and hygiene among women.

6. Mahila Chaupals renamed as Mahila Shakti Sadans are being constructed through the Department of Development and Panchayats.

On going steps

All other Steps & Measures/Schemes remained continued during the Year 2008-09.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब से इनकी सरकार बनी है हरियाणा में पहली बार महिलाओं के उत्थान के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वह सराहनीय हैं। साथ ही साथ मैं उलाहना भी देना चाहूंगा कि हमारे एक माननीय सदस्य जो आज सदन में उपस्थित नहीं हैं वे यहां दुनिया भर की बातें करते हैं। यह जो जवाब आज माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है यह दर्शाता है कि वर्ष 2000–2005 तक इस हरियाणा के अंदर जब चौटाला जी की सरकार थी तब महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों की भलाई के

लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले 4 साल के अर्से में किस तरीके से हौसला अफजाई करने के लिए जो विधवायें, हमारी बहनें और बहू बेटियां हैं उनकी धनराशि को बढ़ाया। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह भी करना चाहूंगा कि जहां इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं वह दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से हमारे प्रदेश की महिलाएं और बच्चे खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि गांवों में रहने वाले और शहरों में गरीब बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाएं या उनके घरों में शौचालय बनाने के लिए कोई अलग से कार्यक्रम बनाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही कंप्रीहैंसिव सवाल था उसका हमने बड़ा व्यापक जवाब दिया है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि क्या–क्या नयी चीजें अनुसूचित जातियों के लिए, पिछड़े वर्गो के लिए और महिलाओं के लिए साल 2000 के बाद ली गईं। इस बारे में दुर्भाग्य से जब हमने सारी जानकारी इकट्ठी की तो पाया कि वर्ष 2000–01 में No new steps were taken, 2001 –02 में 2 नये कदम उठाए गए, 2002–03 में 1 कदम उठाया गया और 2003–04 और 2004–05 में कोई भी नया कदम नहीं उठाया गया। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की मानसिकता का परिचायक था। इस सरकार ने बहुत सारे नये कदम उठाये हैं उनमें से कुछ की अवश्य चर्चा करना

चाहूंगा। कुछ आकड़े ऐसे हैं जो उस समय की सरकार के और आज की सरकार के मन, रास्ते और ध्येय की कहानी कहते हैं उसके यारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैल्फेयर ऑफ एस०सी० एस०टी० डिपार्टमैंट में वर्ष 2004–05 में मात्र 55 करोड़, 95 लाख 91 हजार रुपये पिछली सरकार दिया करती थी और दिसम्बर 2008–09 में 16464 करोड़ रुपये की राशि इस मद में दी गई है। हमारी और उनकी सरकार के समय में यह अंतर है। गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों, आम आदमी, महिलायें और वे सारे वर्ग जिनके समाज में विशेष उत्थान के लिए हर सरकार को अग्रसर रहना चाहिए, यह सरकार की मानसिकता का परिचायक है और उसके लिए कई महत्वपूर्ण स्कीमें हमारी सरकार ने लागू की हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन का समय लेकर 4–5 चीजों के बारे में 2–2 शब्दों में व्याख्या करना चाहूंगा। पहली बार देश में किस सरकार ने इंदिरा गांधी पेयजल परियोजना चलाई जिसमें 9 लाख से अधिक दलित परिवारों को तकरीबन 4 हजार रुपये की लागत से दो सौ लीटर की एकएक पानी की टंकी मुफ्त, हर गरीब के घर में ईंट और सीमेंट के 8–4 फुट के प्लेटफार्म बनाकर, एक बॉल मुफ्त, एक टूटी मुफ्त, पाइप का सारा खर्चा मुफ्त और घर के अंदर के सारे पाइप का खर्चा मुफ्त और कनैक्शन का भी सारा खर्चा छोड़ दिया गया है, यह काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह से शिक्षा विभाग में पहली बार हमारी सरकार ने नयी बाबा अम्बेडकर साहब मेधावी छात्रवृत्ति स्कीम लागू की है ताकि पहली से पांचवी कक्षा तक के 5वीं से 8वी कक्षा तक के और 8वी से 12वीं कक्षा तक के

अनुसूचित जाति के हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जाएं। इसके अलावा जो बच्चे समाज के अनुसूचित वर्गों से हैं जो तरक्की और शिक्षा से महरूम रह जाते थे उनके लिए विशेष वजीफा योजनाएं हैं। किसी गरीब लड़के को जब वह स्कूल में जायेगा तो उसे 100 रुपये प्रति महीना और लड़की को 150 रुपये प्रति मास दिया जायेगा और यह राशि 12वीं कक्षा तक बढ़ते–बढ़ते 300 रुपये और 150 रुपये तक हो जाती हे। इस स्कीम से तकरीबन साढ़े तीन लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार चार लाख से अधिक परिवारों को इन्दिरा गान्धी पेय जल योजना'' के तहत हम अब तक कनैक्शन दे पाए हैं। इसमें खासतौर से गरीब महिलाओं की तरफ ध्यान केन्द्रित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो पंचायत और डिवलपमैंट डिपार्टमैंट है उसने पूरे हरियाणा में ' महात्मा गान्धी ग्रामीण बस्ती योजना' ' में हमारे सभी बैकवर्ड क्लास ए के भाइयों को अरि आठ लाख से अधिक दलित भाइयों को 100–100 गज के प्लाट देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं उनके लिए यह फैसला लिया है जो बरसों से नहीं हो पाया था। मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक लाख से अधिक प्लॉट तो अब तक हम दे चुके हैं और बाकियों कै लिए ड्रॉ ऑफ लाट की प्रक्रिया इस समय जारी है। हम इस बात पर केन्द्रित हैं कि हम अगले 6 से 9 महीनों तक में दे पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अर्बन लोकल बॉडिज डिपार्टमैंट ने हर उस वार्ड में जहां 50 प्रतिशत आबादी दलित भाइयों की थी एक करोड़ रुपया विकास के कार्यों के लिए दिया है। मेरी जानकारी में कई वार्ड ऐसे हैं और माननीय सदस्यों की भी जानकारी में होंगे, वे साथी कहते तो हैं लेकिन वहां .पर सारी सुविधाएं तो होंगी लेकिन जो पैसा आ रहा है वह कहां खर्च करेंगे। कई–कई दलित भाइयों के वार्ड ऐसे हैं जहां एकएक करोड़ रुपया दिया गया है। हर वार्ड के अन्दर बगैर ये देखे कि वहां से किस पार्टी के विधायक हैं सब के वार्डों में पैसा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा में जो एस.सीज. चौपाल हैं उनकी रिपेयर की एक स्पेशल स्कीम चलाई गयी है और इसके लिए 17 करोड़ रुपये ईयर मार्क किए गये हैं। जिनमें से 15 करोड़ रुपये एच०आर०डी०एफ० ने दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, टोटल सैनीटेशन कैम्पेन के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है इसलिए इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सैन्ट्रली स्पोन्सर्ड जो स्कीम थी उसके तहत हमने 2 लाख रुपये दलित परिवारों को इन्डिविजुअल लैट्रिन कन्सट्रक्सन के लिए दिए हैं। 899 जो बुमन सैनीटेरी कम्पलैक्सिज हैं जहां दस टायलटस तक बनाये जाते हैं, वहां दलित मोहल्लों में आज तक सरकार ने बनाये हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति गांव उत्थान एवं मलिन बस्ती की विकास योजना' मुख्यमंत्री जी ने शुरू करवाई है ताकि जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक दलित पापुलेशन है उन सारे गांवों के अन्दर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर दे सकें। वर्ष 2001 के सैन्सस में हमने 391 गांव आईडैटिफाई किए हैं।

मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी है कि वर्ष 2008–09 में 9275 लाख रुपये विशेष तौर से इस सरकार ने इन 391 गांवों के लिए दिए हे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नै सैनीटशन की चिन्ता ज्यादा जाहिर भक्त है, सैनीटेशन के लिए फाईनैंशिएल एसिसटैंस उन ग्राम पंचायतों को हमने देने की कोशिश की है। जहां 50 प्रतिशत से अधिक दलित पोपुलेशन है। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में हमने 11 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। हमारे बहुत सारे दलित भाइयों को उसमें रोजगार भी मिला है और गांवों में सफाई की व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ बनी है। इस पर 44 करोड़ रुपये हमने खर्च किये हैं। मैं इस बारे में बताने लगू तो यह लम्बा पुलिन्दा है परन्तु यह सरकार की मानसिकता, सदन के नेता की मानसिकता को दर्शाता है कि हर गरीव, हर पिछड़ा, हर दलित भाई और हर महिला इस सरकार की प्राथमिकता के एजैंडे पर हैं यह मैं सदन को और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा।

ताराकिंत प्रश्न संख्या 1174

(इस समय माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

ताराकिंत प्रश्न संख्या 1100

(इस समय माननीय सदस्य थी रमेश ता सदन में फैक नहीं थे, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Ambedkar Medhavi Chhater Yojna

***1127. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Ambedkar Medhavi Chhater Yojna beyond +2 (12th standard) to pursue higher education such as MBBS and B. Tech. etc. together with the district-wise number of beneficiaries to whom disbursement of scholarship under the said scheme has been made during the year 2007-08 and 2008-09.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir. A Statement is placed on the table of the House, regarding number of beneficiaries during the year 2007-08 and 2008-09.

Statements

Statement showing the district wise SC, BC (A & B) beneficiaries/ disbursement of scholarship during the year 2007-08

Sr. No.	Name of District	Scheduled Castes & Backward Classes (Block A and B) (10+1, 1st year diploma in Poly./ ITI and 10+2 Class)	
		No. of Beneficiaries	Amount Disbursed
			(Rs. in lacs)

1.	Ambala	229	22.90
2.	Bhiwani	773	7730
3.	Faridabad	427	42.70
4.	Fatehabad	271	27.10
5.	Gurgaon	239	23.90
6.	Hisar	991	99.10
7.	Jhajjar	505	5030
8.	Jind	659	65.90
9.	Kaithal	270	27.00
10.	Karnal	448	44.80
11.	Kurukshetra	289	28.90
12.	Narnaul	777	77.70
13.	Mewat	074	7.40
14	Panchkula	135	13.50
15.	Panipat	372	3720
16.	Rewari	685	68.50
17.	Rohtak	616	61.60
18.	Sirsa	458	45.80
19.	Sonipat	573	5730

20.	Yamuna Nagar	363	3630
	Total	9154	915.40

Statement showing the district wise SC, BC (A& B) +2, 2nd year diploma in Polytechnic / I.T.I. covered under the scheme, number of beneficiaries / disbursement of scholarship during the year 2008-09

Sr. No.	Name of District	Scheduled Castes & Backward Classes (Block A and B) (10+2, 1st year diploma in Poly. / ITI	
		No. of Beneficiaries	Amount Disbursed (Rs. in lacs)
1.	Ambala	114	11.40
2.	Bhiwani	472	47.20
3.	Faridabad	129	12.90
4.	Fatehabad	145	14.50
5.	Gurgaon	143	1430
6.	Hisar	498	49.80
7.	Jhajjar	319	31.90
8.	Jind	328	32.80

9.	Kaithal	119	11.90
10.	Karnal	220	22.00
11.	Kurukshetra	132	13.20
12.	Narnaul	496	49.60
13.	Mewat	42	420
14.	Panchkula	63	630
15.	Panipat	210	21.00
16.	Rewari	507	50.70
17.	Rohtak	236	23.60
18.	Sirsa	270	27.00
19.	Sonipat	283	28.30
20.	Yamuna Nagar	245	24.50
21.	Palwal	120	12.00
	Total	5091	509.10

Note :-The list of the beneficiaries who are studying in 10+1/1.T.I./ Polytechnic 1st year is being prepared and is likely to be-sanctioned shortly.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना जो अभी सरकार ने शुरू की है उसका

क्राइटेरिया क्या फिक्स किया गया है। इसकी लिस्ट को शार्ट लिस्ट करने केलिए क्या मापदंड दिए गए हैं और हमारे पास कितनी एप्लीकेशंज आई हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के तहत एस०सी० और बी०सी० ''ए'' में जो लड़के और लड़कियां आती हैं जो 10वी कक्षा में 60 परसैंट या उससे ज्यादा मार्क्स लेते हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति माह 10 महीनों के लिए दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इन्होंने संख्या जानने की बात कही है तो 2008–09 में जनवरी, 2009 तक 5091 बच्चों को 509 लाख 10 हजार रुपये दिए गए हैं। दलित भाइयों के बेटी या बेटे और पिछड़े वर्ग के बच्चों को इस स्कीम का लाभ दिया गया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना 10+2 के बच्चों के लिए है। अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि जो बच्चे एम०बी०ए०, बी०टैक० या हायर एजुकेशन लेना चाहते है उनके लिए क्या–क्या स्कीमें हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमने अनेकों स्कीष्टा शुरू की हैं। उनके लिए Post-matric Scholarships to Scheduled Castes According to this Scheme, Scheduled Castes Students studying in post-matric classes are awarded scholarships under the Government of India's Scholarships

Scheme ranging from Rs. 140 to Rs. 740 per month in different classes. The students are also reimbursed compulsory nonrefundable fees. Under this scheme the limit of annual income of the parents and guardians is Rs. I lac. Sir, there is one more scheme for backward classes which is identical i.e. Post-matric Scholarships to other Backward Classes students. There the limit is Rs. 90 to Rs. 425 per month and the income criteria is Rs. 44,500 per month.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए ताराकिंत प्रश्नों के लिखित उत्तर

Disbursement of Ex-Gratia

***1132. Shri Sher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give the responsibility of disbursement of Ex-Gratia and like grants of Paramilitary Forces Personnel to the Secretaries of Soldier Boards ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): नहीं, श्रीमान जी।

Desilting / Repair of Bhakra Main Canal

***1138. Dr. Sita Ram :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

(a) the number of times for which the Bhakra Main Canal was desilted / repaired in the financial year 2007-08 and in the year after March 31st, 2008 in the area of

Punjab & Haryana togetherwith the name of agency which executed the said work ; and

(b) whether the Haryana State is getting full share of water through the said canal ?

कृषि मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) भाखड़ा मेन लाईन पर मिले अप्रैल 1992 के गत बंद के पश्चात् कोई बंद नहीं मिला है। इसलिए वर्ष 2007–08 के दौरान तथा 51 मार्च, 2009 के बाद भाखड़ा मेन लाईन से गाद निकालने का कोई कार्य नहीं किया गया। यद्यपि उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान पंजाब सिंचाई विभाग द्वारा कुछ छोटे मोटे मरम्मत के कार्य किये गये थे। हरियाणा द्वारा वर्ष 2007–08 तथा चालू वित्त वर्ष के लिए अपने हिस्से की राशि क्रमशः 600 करोड़ रुपये तथा 500 करोड़ रुपये पंजाब सिंचाई विभाग के पास जमा करवाये जा चुके हैं। क्योंकि कार्य पंजाब सिंचाई विभाग द्वारा करवाया गया है, इसलिए संस्थाओं की सूची हरियाणा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

Regularization of Jhuggi-Jhonpari Colonies

***1151. Sh. Mahender Par Singh :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state :-

(a) the number of Jhuggi-Jhonpari colonies in the three zones of

Faridahad Municipal Corporation area ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the said colonies at the same place or at any other alternate place ; if so, the details thereof ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

(क) नगर निगम फरीदाबाद की सीमा में 59 झुग्गी झोपड़ी कालोनियां (33 एन०आई०टी० जोन, 9 बल्लबगढ़ जोन तथा 17 ओल्ड फरीदाबाद जोन) है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। इन झुग्गी झोपड़ी कालोनियों को उनके वर्तमान स्थान पर नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे०एन०एन०यू० आर०एम०) योजना के अन्तर्गत, दो रिहायशी योजनाओं के अन्तर्गत, डबुआ कालोनी में 1968 मकान तथा बापू नगर में 1280 मकान, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एन०बी०सी०सी०) के माध्यम से निर्माणाधीन हैं। यह मकान नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बसे झुग्गी–झोंपड़ी निवासियों को अलाट किये जायेंगे।

Opening a Dispensary at Village Wasser

***1160. Smt. Raj Rani Poonam : Will** the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a dispensary at village Wasser in Assandh constituency ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): नहीं श्रीमान जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Number of Government Senior Secondary Schools

148. Shri Karan Singh Dalal : Will the Education Minister be pleased to state :-

(a) the number of Government Senior Secondary Schools district wise in the state in Rural and Urban area separately in which science faculty, medical or non-medical or both is being run during the academic year 2008-09 ; and

(b) the number of the schools in (a) above in which the post of regular or guest teachers required for the subjects being taught were not vacant during the first semester and second semester of the current academic year 2008-09 ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे सम गुप्ता): श्रीमान् जी,

(ए) शैक्षणिक सत्र वर्ष 2008–09 के दौरान, राज्य में, विज्ञान संकाय मैडीकल या नॉन–मैडीकल या दोनों संकायों में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पृथक–पृथक चलाए जा रहे कुल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की जिलावार सूची निम्नलिखित है –

जिला	विज्ञान संकाय के विद्यालयों की संख्या	ग्रामीण	शहरी	केवल मैडीकल	केवल नॉन–मैडीकल	मैडीकल एवं नॉन–मैडीकल दोनों
1	2	3	4	5	6	7
अम्बाला	14	7	7	—	7	7
भिवानी	30	23	7	2	16	12
फरीदाबाद / पलवल	30	11	19	1	12	17
फतेहाबाद	12	6	6	2	5	5
गुड़गांव	26	17	9	—	10	16
हिसार	21	12	9	-	8	13
झज्जर	12	6	6	-	4	8
जीन्द	12	6	6	-	4	8
कैथल	10	4	6	-	6	4

करनाल	16	7	9	-	7	9
कुरुक्षेत्र	11	6	5	-	4	7
महेन्द्रगढ़	14	10	4	-	8	6
मेवात	10	5	5	-	7	3
पंचकूला	11	4	7		5	6
पानीपत	14	9	5	-	8	6
रेवाड़ी	23	19	4	-	13	10
रोहतक	21	10	11	-	11	10
सिरसा	13	5	8	1	8	4
सोनीपत	19	10	9	2	5	12
यमुनानगर	14	10	4	-	6	8
कुल संख्या	333	187	146	8	154	171

(बी) उपरलिखित सूची (ए) में दिए गए विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2008–09 के प्रथम एवं द्वितीय समैस्टर के दौरान पढ़ाए गए विषयों के नियमित या अतिथि अध्यापकों के पद खाली नहीं थे, वे निम्नलिखित हैं–

जिलों के नाम	विज्ञान संकाय के विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जिनमें विज्ञान अध्यापकों के सभी पद रिक्त नहीं हें प्रथम समैस्टर	विद्यालयों की संख्या जिनमें विज्ञान अध्यापकों के सभी पद रिक्त नही हैं द्वितीय समैस्टर
1	2	3	4
अम्बाला	14	14	14
भिवानी	30	17	17
फरीदाबाद / पलवल	30	27	27
फतेहाबाद	12	04	04
गुड़गांव	26	18	17
हिसार	21	15	18
झज्जर	12	07	07
जीन्द	12	07	09
कैथल	10	04	04

करनाल	16	13	13
कुरुक्षेत्र	11	08	09
महेन्द्रगढ़	14	11	11
मेवात	10	04	04
पंचकूला	11	10	10
पानीपत	14	12	09
रेवाड़ी	23	07	08
रोहतक	21	15	06
सिरसा	13	08	11
सोनीपत	19	17	15
यमुनानगर	14	11	10
कुल संख्या	333	229	223

नोट – जिन विद्यालयों में एक पद भी रिक्त है, वे उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

Drinking Water Pipe Line

141. Dr. Sita Ram : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact

that the amount released under M.P. Scheme for drinking water pipe line for Dhani Hardyal Singh, Kaur Singh, Balwinder Singh etc. and village Gardrana, District Sirsa, but work of drinking water pipe lining is still pending ; if so, the time by which the said scheme is likely to be completed ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): गांव गरडराणा की ढाणी कौर सिंह और बलविंदर सिंह के लिए पीने के पानी की पाईप लाइन 2.25 लाख रुपये की लागत से पहले ही बिछाई जा चुकी है। परन्तु गांव गरडराणा की ढाणी हरदयाल सिंह में 1.00 लाख रुपये लागत से लगने वाली पीने के पानी की पाईप लाईन ग्रामवासियों के झगड़े के कारण नहीं बिछाई गई। उक्त झगड़े की वजह से इस कार्य के पूरा होने की कोई समय–सीमा नहीं दी जा सकती।

Number of Rooms Constructed in Schools

152. Sh. Naresh Yadav : Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the school wise and blockwise number of schools in district Mahendergarh in which new rooms have been constructed and also the number of schools from Primary to 1042 where boundary walls have been constructed togetherwith the details of expenditure incurred thereon ; and

(b) the number of guest teachers appointed togetherwith the details of number of posts lying vacant in district Mahendergarh ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):

(क) श्रीमान् जी, वर्ष 2005–06 से अब तक जिला महेन्द्रगढ़ में 1864.09 लाख रुपये की लागत से 473 राजकीय विद्यालयों में 545 नये कमरों का निर्माण किया गया है तथा 70 राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 157.91 लाख रुपये की लागत सै चार दीवारी का निर्माण किया गया है। ब्लाकवार विवरण निम्नानुसार है–

ब्लाक का नाम	राजकीय प्राथमिक माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जिनमें नये कमरों का निर्माण करवाया गया है की संख्या	कुल नये निर्माण किये गये कमरों की संख्या	कुल खर्च की गई राशि	राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जिनमें चार दीवारी का निर्माण करवाया गया है की संख्या	कुल खर्च की गई राशि
नांगल चौधरी	118	129	553.75 लाख	12	29.61 लाख

महेन्द्रगढ़	120	134	460.70 लाख	12	31.48 लाख
कनीना	79	92	299.50 लाख	22	24.00 लाख
अटेली	66	84	154.39 लाख	13	51.73 लाख
नारनौल	90	106	395.75 लाख	11	21.09 लाख
योग	473	545	1864.09 लाख	70	157.91 लाख

(ख) जिला महेन्द्रगढ़ में नियुक्त विभिन्न कैटेगरी के अतिथि अध्यापकों बारे स्थिति रिक्तियों सहित निम्नानुसार है –

क्रमांक	कैटेगरी	कुल रिक्तियां	नियुक्त अतिथि अध्यापकों की संख्या
1	प्राध्यापक	118	89
2	मास्टर	231	114
3.	सी. एण्ड वी. अध्यापक	256	48

4.	जे.बी.टी. अध्यापक	107	78

Officers/Officials Booked under Prevention of Corruption Act, 1998

149. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of officers/officials who were booked under the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988 during the years 2000-01 till date ;

(b) the names of officers/officials in (a) above against whom charge sheets have been filed ;

(c) the names of the officers/officials in (a) above against whom cases have been withdrawn by the state Government ; and

(d) the names of officers/officials who have been reinstated during the pendency of trial against them ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान जी, इस सम्बन्ध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि मांगी गई सूचना विभाग में तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इस सूचना को प्राप्त करने में लगने वाला समय एवं परिश्रम इसके प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप, नहीं होगा।

Posting of Doctors

153. Sh. Naresh Yadav : Will the Health Minister

be pleased to state whether it is a fact that the posts of Lady doctors are lying vacant in Community Health Centres and Primary Health Centres of District Mahendergarh ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): श्रीमान जी, जिला महेन्द्रगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हैं। महेन्द्रगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त नहीं हैं।

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received Leave of Absence dated 6th February, 2009 from Shri Phool Chand Mullana, M.L.A. which reads as under :-

"Respected Speaker Sir,

I shall be away on 12th and 13th February. My absence from the Haryana Vidhan Sabha sittings for 12th and 13th February, 2009, may please be condoned."

Mr. Speaker: Question is -

That Leave of Absence be granted to Shri Phool Chand Mullana, M.L.A. to remain absent from sittings of the House for 12th and 13th February, 2009.

Voices : Yes, yes.

(The motion was carried.)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, 1 have received Leave of Absence dated 12th February, 2009 from Smt. Kartar

Devi, Health, Social Welfare and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Minister which reads as under :-

"Most respected Speaker Sahib,

I have the honour to request herewith that due to fever, I will not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha today, the 12th February, 2009. Kindly excuse my absence.

With profound regards."

Mr. Speaker : Question is -

That Leave ofAbsence be granted to Smt. Kartar Devi, Health, Social Welfare and Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Minister to remain absent from the sittings of the House today, the 12th February, 2009.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have preceived Leave ofAbsence dated 11th February, 2009 from Shri Ranbir Singh Mahendra, MLA, which reads as under—

Dear Sir,

"It is with profound grief that I inform you of my mother's demise on the night of 10th February, 2009. I will be unable to attend the present Session because of duties during this period of mourning.

I am to request you to kindly grant me leave of

absence from the current Session."

Mr. Speaker : Question is -

That Leave of Absence be granted to Shri Ranbir Singh Mahendra, M.L.A. to remain absent from the sittings of the House during the current Session.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried.

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Private Secretary to Ch. Ram Kishan, Parliamentary Secretary, Irrigation & Power Deptt. dated 12th February, 2009, vide which he has informed that due to some unavoidable circumstances, Ch. Ram Kishan, Parliamentary Secretary would not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 12th and 13th February, 2009.

Hon'ble Members, I am also to inform the House that I have received a letter from Private Secretary to Smt. Kiran Choudhary, Minister of State for Forests, Environment, Tourism, Sports & Youth Affairs dated 12th February, 2009, vide which he has informed that due to sudden demise of her mother-in-law, Smt. Kiran Choudhary would not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

(नियम 30 के निलम्बन के लिए)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 12th February, 2009.

Sir, I also beg to move—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on 12th February, 2009.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 12th February, 2009.

and also

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on 12th February, 2009.

Mr. Speaker : Question is -

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 12th February, 2009.

and also

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on 12th February, 2009.

The motion was carried.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion on the Governor's Address be resumed. I would request the Hon'ble Members to kindly conclude your speech within 10 minutes because 10 minutes are sufficient to say or to suggest something on the Governor's Address.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (कैथल): स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार शर्मा जी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रखा था मैं उसके अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, गर्वनर साहब के अभिभाषण के शुरू में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी जो कि इस प्रान्त के ही नहीं बल्कि इस देश के एक बहुत ही०ंचे दर्जे के स्वतन्त्रता सेनानी थे, कांस्टीचुएंट असैम्बली के हरियाणा क्षेत्र से

एकमात्र नुमाइंदे थे, ज्वायंट पंजाब के इरीगेशन और पावर मिनिस्टर रहे थे और एक ऐसे परिवार से सम्बन्ध रखते थे जिस परिवार की दो–दो, तीन–तीन पीढ़ियों ने आजादी की लड़ाई में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। स्व० चौधरी रणबीर सिंह जी के लिए एक सूटेबल स्मारक बनना चाहिए और इसके लिए बहुत से सुझाव हो सकते हैं लेकिन मैं भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमें लोकसभा स्पीकर से, संसद भवन प्रैमिसिस जिसके दायरे अख्तियार में है बात करके वहाँ चौधरी रणबीर सिंह का स्टैच्यू लगवाना चाहिए। इसके लिए उनसे रिक्यैस्ट की जानी चाहिए और इस बात के लिए हमें प्रयत्न भी करने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की 4 साल की जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में अगर चर्चा करूँगा तो जो आपने 10 मिनट की समय सीमा तय की है वह उसके लिए बहुत कम समय है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप तो 10 घण्टे भी बोल सकते हैं और बोले भी हैं लेकिन we have to provide opportunities to the new Hon'ble MLAs.

श्री एस० एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, सरकार की अनगिनत उपलब्धियां हैं और मैं एक बात कह कर इस चौप्टर को खत्म करूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री कितने उदार हृदय हैं और कितनी वे आगे की सोचते हैं और अपने प्रान्त के हर तबके के लिए विशेष तौर से जो गरीब तबके हैं, महिलाएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे–बच्चियाँ हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं,

सरकारी नौकरी करने वाले हैं और कोई ऐसा एरिया उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके बारे में पिछले 4 साल में 'अभूतपूर्व प्रगति के काम न हुए हो। मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार अपने 'आप भै एक रिकॉर्ड है। इससे पहले हरियाणा में कोई ऐसी सरकार आई का नहीं और देश में भी बहुत कम ऐसी सरकारें होंगी जिनकी इतनी उपलब्धियां होंगी। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग में भै। यह घोषणा की और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह बात है कि वर्ष 2009– 10 को किसान–मजदूर के नाम से किसान व मजदूर वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार ने इससे पहले भी किसानों मजदूरों और गरीब तबके के लिए बहुत कुछ किया है। इस सरकार ने जहाँ कर्जे माफ किये, बिजली के बिल माफ किये, किसानों की जमीनों के और फसलों के०ंचे दाम दिये। इस सरकार के कार्यकाल में ब्याज की दरें भी बहुत कम हुई। किसान अगर कर्जा वापिस जमा नहीं करवा पाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इस सरकार ने उस गिरफ्तारी के काले कानून को निरस्त किया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी भी एक और काला कानून बाकी है जिसको खत्म करने के बारे में मैं इससे पहले भी कई साल से माँग करता आ रहा हूँ। वह काला कानून यह है कि जिस किसान को किसी बैंक का कर्जा देना है या किसी प्राईवेट आदमी या साहूकार का कर्जा देना है तो उस कर्जे के बदले में उनके पास अपनी जमीन प्लैज कर देता है। अगर किसान वह कर्जा नहीं दे पाता है तो उसकी

जमीन, कोर्ट से डिक्री लेकर नीलाम की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि किसान के लिए, गरीब के लिए. खेती करने वाले के लिए इससे बुरा कानून कोई नहीं हो सकता है और मैं इस सरकार से पूरी उम्मीद करता हूँ कि यही एक सरकार है, कांग्रेस पार्टी की यही सरकार ही कानून की किताब से इस काले कानून को खत्म कर सकती है। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की चर्चा की है लेकिन उन्होंने हमेशा यही जाहिर किया है कि वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज मैं वह भी बताना चाहता हूँ कि वे कैसे इस काम को कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं 2–5 बातें और कहना चाहूँगा। किसान जब ट्रैक्टर या ट्यूबवैल के लिए कर्जा लेता है तो उसके लिए बहुत सख्त रूल्ज बनाए हुए हैं। 4–5 लाख रुपये के ट्रैक्टर के बदले एक तो उसके ट्रैक्टर को गिरवी रख लिया जाता है और साथ ही उसकी तीन एकड़ जमीन जिसकी मार्कीट में कम से कम अगर कीमत आंकी जाये तो यह 40–50 लाख रुपये है, उसको भी गिरवी रख लिया जाता है। स्पीकर सर, अगर 3 से 5 लाख का कर्ज किसान ट्रैक्टर के लिए लेता है तो उस कर्ज के लिए वह अपनी जमीन गिरवी रखता है। (इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री शादी लाल बतरा पदासीन हुए) अगर कोई आदमी आज कार लेना चाहे या कोई लग्जरी आईटम लेना चाहे तो उसकी जमीन जायदाद, मकान दुकान कोई रेहन नहीं रखे जाते केवल वह आईटम और वह चीज प्लैज की जाती है। अगर वह कार के लिए कर्ज लेता है

तो कार प्लैज होगी। स्पीकर सर, इस प्रकार के जो एंटी फार्मर कानून–कायदे हैं इनको खत्म करना चाहिए। किसी भी सूरत में किसान की जमीन प्लैज नहीं होनी चाहिए। अगर वह कर्ज लेकर ट्रैक्टर लेता है तो वह ट्रैक्टर प्लैज मैच। सकता है। अगर किसान कोई और औजार या चीज के लिए कर्ज लेता है तो वह प्लैज हो सकती है। अगर वह अपने खेत में मकान बनाता है तो मकान प्लैज हो सकता हैं लेकिन किसान की जमीन प्लैज नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर्ज के लिए कोआपरैटिव बेक लैण्ड मोर्टगेज बैंक्स जो कर्जा देते हैं उसकी ब्याज की दर साढ़े ग्यारह परसैंट हैं। आज कार या रैफीजिरेटर, एयर कण्डीशनर्ज और दूसरी लग्जरी आईटम्ज तो कम्पनियां जीरो ब्याज पर लोगों को देती हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 परसैंट तक किसी भी लग्जरी आईटमज के लिए कम्पनियां या बैंक कर्ज देते हैं लेकिन किसान के ट्रैक्टर के लिए 11 परसैंट का ब्याज बहुत ज्यादा और नाजायज है इसको खत्म किया जाना चाहिए और किसी भी सूरत में यह ब्याज की दर 6–7 परसैंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है। करीब चार साल पहले भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि किसान 3 लाख रुपये कर्ज अगर खेती के लिए लेगा तो 7 परसैंट ब्याज देगा जबकि इससे पहले एन०डी०ए० की सरकार में 14 से 18 परसैंट ब्याज लगता था। इस सरकार ने उस ब्याज दर को सात परसैंट किया और हमने उनका स्वागत किया। पूरे देश के गरीब और

किसान ने सरकार के उस फैसले का स्वागत किया। आज चार साल के बाद वह समय आ गया है कि इस ब्याज दर को और घटा कर पांच प्रतिशत किया जाए। भूमिहीन लोगों के लिए इस ब्याज की दर तीन प्रतिशत होनी चाहिए। चेयरमैन सर, यह समय बहुत तंगी का समय है। हर तबका तंग है और गरीब आदमीं और किसान के लिए०ंची ब्याज दर देना सम्भव नहीं है। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो जमीन है वह हमारी मां है और कोई भी व्यक्ति मां को बेचता नहीं है मां को बेच नहीं सकता है। बहुत दु:ख की बात है कि किसान जिसका एकमात्र सहारा जमीन है, पांच किल्ले, 7 किल्ले जिसने उसको प्लैज करके कर्जा लिया था जब वह कर्जा वापिस नहीं दे सकै और मजबूर होकर अपनी मां को वापिस न छुड़वा सके तो उसकी जमीन को नीलाम करने का जो कानून है इससे ज्यादा और बुरा काला कानून कोई और नहीं हो सकता है। चेयरमैन सर, इसके बारे में मैं सरकार को एक सुझाव देता हूँ। किसान की जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को चाहिए कि अगर कोई किसान चाहे प्राईवेट कर्जा या बैंक का कर्जा वापिस न कर पाए और किसी ने कोर्ट से डिक्री ले रखी है उसकी जमीन कर्जे के वाल्यूम को देखते हुए एक से पांच साल के लिए चकोदे पर दे दी जाए। चकौदे का फसल का आधा पैसा किसान के परिवार को जाना चाहिए ताकि वह अपना गुजारा कर सके और आधा पैसा उस कर्जे के बट्टे खाते में जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चकौदा की दर 20 हजार रूपये प्रति एकड़ से शुरू होकर 30–35 हजार रुपये प्रति एकड़ है। 5 से 8

एकड़ वाला किसान भी उस पर दो से चार लाख रुपये तक का कर्जा 3–4 साल में उतार सकता है और जब उसका कर्जा पूरा हो जाए तो उसकी जमीन उसको वापिस दे दी जानी चाहिए। इस प्रकार से आप किसान की जमीन हमेशा–हमेशा के लिए बिकने से बचा सकते हैं। चेयरमैन सर, इस सरकार ने किसान और मजदूर साल मनाने का जो फैसला किया है उसके लिए मेरे 4– 5 और सुझाव हैं। अगर वाकई ही आप किसान और मजदूर के नाम से यह साल मनाना चाहते हैं और सरकार इसके बारे में सीरियस है तो किसान की जमीन को नीलाम करने के कानून को हमेशा–हमेशा के लिए निरस्त करना पड़ेगा। मैंने जो सुझाव दिए हैं, मेरे अलावा और भी मैम्बर्ज अपने सुझाव दे सकते हैं। मेरा यह कहना है कि हर हालत में जमीन नीलाम और बेची नहीं जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। नकली बीज, नकली दवाएं, नकली खाद और डीजल में भी मिट्टी के तेल की मिलावट होती है। यहां तक कि खाद में भी नमक कै। मिलावट की जाती है। चेयरमैन सर, आज जो बाजार में कीड़े मारने की दवाएं हैं उनका नाम न तो आज किसानों को और न ही सरकार को पता होता है। मार्किट में रोज नाम बदल कर नई–नई कम्पनियां आ रही हैं और ऐसी मिलावटी दवाएं बेच रही हैं कि उससे फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। कई बार तो ऐसी दवाई आ जाती है कि अगर उसको फसल पर छिड़क दिया जाए तो फसल बिलकुल जल जाती है। वे थैलियों पर मार्का लगाकरॅंचे दामों पर बेचते हैं। हमारे यहां पर जो कानून है वह बहुत ही

पुराना कानून है। उसके तहत आप मिलावट करने वाले को सख्त सजा नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन सर, मेरे पास, इन चीजों के आकड़े तो नहीं हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ और इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, चाहे ये इसके बारे में कुछ भी सोचें। डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट और एग्रीकल्चर के इनपुट्स सामान में मिलावट होती है उसमें सरकारी महकमे के लोग मिले होते हैं। सिविल सप्लाई डिपार्टमैंट का काम यह होता है कि वह यह देखे कहीं पैट्रोल पम्प वाला गलत पैट्रोल तो नहीं बेच रहा है, पूरा पैट्रोल दे रहा है या नहीं दे रहा है। वे मन्थली लेने के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट कै लौग भी बीज, खाद और कीड़े मारने कै। दवाईयां बनाने वालों के– साथ मिले हुए हैं। वे उनसे मन्थली लेते हैं और उनके चालान नहीं काटते हैं। सदन में मंत्री जी ने मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि हरियाणा में द्र में मिलावट करने वालों के कितने सैम्पल लिए और कितनों को सजा हुई। मैं उनको पढ़ कर सदन में बता देता हूँ। अम्बाला में 2006 में 12, 2007 में 14 और 2009 में 6 सैम्पल लिए गए थे और उनमें से 2006 में एक को 2007 में भी एक को और 2008 में 2 को सजा हुई थी। इसी तरह से भिवानी में 2006 में 6,2007 में 5 और 2008 में 12 सैम्पल लिए गए थे और उनमें से किसी को भी सजा नहीं मिली थी। यही हाल बाकी डिस्ट्रीक्ट्स का भी है। मेवात में भी 2006 में 2 केस पकड़े गए और 2009 में 1 पकड़ा गया लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। चेयरमैन सर, चाहे मिट्टी के तेल में

मिलावट की बात हो या दूसरी चीजों में मिलावट की बात हो इस बारे में हमारा कानून बहुत ही कमजोर है कि इसमें जमानत हो जाती है उनको गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। इसमें आप किसी को पकड़कर सख्त सजा दे नहीं सकते हैं। कोर्ट के भी इसमें हाथ बंधे हुए हैं। कोर्ट भी 4–5 महीने की ही सजा दे सकती है। मैं इस बारे में सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर कोई किसान और मजदूर के साथ खिलवाड़ करता है उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जो कम्पनी यह काम करती है उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ मिलावट का केस साबित हो जाए तो कम से कम उस व्यक्ति को 10 साल की कैद होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ। चेयरमैन सर, हमारे जो छोटे और सीमान्त किसान तथा भूमिहीन मजदूर हैं वे आज की तारीख में दवाईयों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। वह इलाज न करवाने की वजह से मर जाते हैं तथा अपने पीछे पूरे का पूरा परिवार छोड़ जाते हैं। चेयरमैन सर, भारत सरकार ने गरीब आदमियों की पैंशन की स्कीम बनाई है लेकिन हरियाणा में यह लागू नहीं है। हरियाणा सरकार को छोटे और सीमान्त किसानों, गरीब आदमियों और भूमिहीन मजदूरों की कम्पलसरी हैल्थ इंश्योरैंस करनी चाहिए। आज गांवों के रहने वाले बच्चे नम्बर 2 के सिटीजन बनते जा रहे हैं। गांवों में बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, टीचर्ज को अंग्रेजी नहीं आती है, गांवों के स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम नहीं है, गांवों में अंग्रेजी कम्पलसरी

नहीं है। साईंस की क्लासिज नहीं हैं, टैक्नीक्ल विषय नहीं हैं। इसका नतीजा यह है कि आज जब गांवों के बच्चे कहीं पर भी मैडीकल और इंजीनियरिंग का एन्टरैंस टैस्ट देने जाते हैं तो उनका कहीं पर भी नम्बर नहीं आता है जिसकी वजह से उनको दाखिला नहीं मिलता है। चेयरमैन सर, चाहे पुलिस में सिपाही की भर्ती हो, बेलदार की भर्ती हो या कोई दूसरी नौकरियां हों उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। क्या हरियाणा की गांवों में रहने वाली 70 प्रतिशत जनसंख्या की किस्मत में यही लिखा है। आज गांवों के स्कूलों में भी साईंस कम्पलसरी होनी चाहिए, टैक्नीकल शिक्षा होनी चाहिए और अच्छे पड़े लिखे टीचर्ज स्कूलों में लगाने चाहिएं। चेयरमैन सर, मैं ज्यादा समय न लेकर दो बात और कहकर अपना स्थान ले लूंगा। चेयरमैन सर, गांवों के स्कूलों में खेल भी कम्पलसरी होने चाहिएं। हॉकी, फुटबॉल और वालीवाल जैसे खेल स्कूलों में कम्पलसरी होने चाहिएं। 10+2 पास करने के बाद बच्चों को तब तक इसकी डिग्री नहीं मिलनी चाहिए जब तक वह एक साल तक आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स में नौकरी न करे। चेयरमैन सर, इसके बिना न तो हम शरीर से हृष्ट–पुष्ट बच्चे पैदा कर सकते हैं और न हम देश भक्त बच्चे पैदा कर सकते हैं इसलिए सरकार को इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। चेयरमैन सर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पशु पालन जो है वह किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और पशु पालन के लिए जो वेटरनरी डिपार्टमैंट है वह चाहे कुछ भी क्लेम करता रहे, वह केवल कागजों के०पर ही है क्योंकि गांवों के अंदर कुछ नहीं हो

रहा है। गांवों में पशुओं के किसी प्रकार के इलाज की सहूलियत नहीं है, अच्छी नस्ल पैदा करने की सहूलियत नहीं है। जब तक गांवों में रहने के लिए, खेती करने के लिए, गरीब और मजदूर के लिए सैनेटरी कडीशज रहने के काबिल नहीं होगी, जब तक ऐसे मकान नहीं होंगे तब कुछ होने वाला नहीं है। चेयरमैन सर, वहां के मकानों में कम से कम शौचालय की बहुत जरूरत है, एक बाथरूम की जरूरत है। चेयरमैन सर, आपको भी और हाउस के दूसरे मैम्बर्ज को भी इस बात का पूरी तरह से पता है कि किसी भी गांव में अच्छे भले घरों में भी कोई बाथरूम नहीं है। जब बाथरूम ही नहीं होगा तो औरते कहां नहाएंगी, बच्चे और दूसरे लोग कहां नहाएंगे? गांवों में बाथरूम का कोई भी इंतजाम नहीं है। वहां पर कोई भी अपने दाँत साफ नहीं करता इसलिए गांवों का जब तक पूरी तरह से एन्वायरमैंट ठीक नहीं होगा तब तक खेती करने के लिए, गांवों में रहने के लिए कैसे सोचा जा सकता है? वह कैसे तरक्की करेंगे? चेयरमैन सर, मैं यह चाहता हूँ कि सरकार अगर वाकई में इस बारे में चाहती है जैसा कि मुझे उम्मीद भी है कि सरकार चाहती है कि यह साल किसान और मजदूर के नाम से मनाया जाए तो आपको ये सारे उपाय भी तथा दूसरे उपाय भी करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चेयरमैन सर, एक बात और कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

श्री सभापतिः सुरजेवाला जी, आपको बोलते हुए काफी टाईम हो गया है इसलिए अब आप जल्दी अपनी बात को समाप्त करें।

श्री एस०एस सुरजेवालाः सर, मैं दो मिनट से फालतू समय नहीं लूंगा। अभी पिछले दिनों पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) डिपार्टमैंट ने क्लास फोर की नौकरियों के लिए अखबारों में इश्तहार दिए। इसके बाद रैवेन्यू डिपार्टमैंट ने, ट्रैजरी डिपार्टमैंट ने तथा दूसरे डिपार्टमैंट्स ने भी डिपार्टमैंट की तरफ से उनके लिए अखबारों में इश्तहार दिए थे। अखबारों में इश्तहार देने के बाद हजारों लाखों की गिनती में गरीब आदमियो कै थोड़े पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे इन पोस्टों के लिए ऐप्लाई करते हैं। लेकिन पोजीशन क्या है? दस नौकरी अगर चपरासी की हैं तो चपरासी तो पहले ही लगे हुए हैं। कोई किसी के बर्तन साफ करता है और कोई किसी के बच्चे खिलाता है। कच्चे तो ये लगा ही रखे हैं इसलिए इनको ही पक्का करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जब गरीब आदमी के बच्चे यहां पर इन पोस्टों के लिए आते हैं तो इससे उनका खर्चा भी होता है और बाद में वे मायूस होकर चले जाते हें। इसलिए इस बारे में कानून में प्रावधान कर दिया जाए और इम्प्लायमैंट एक्सचेंज के माध्यम से इसके लिए नाम मांग लिए जाएं। अखबारों में इश्तहार देकर हजारों बच्चों को क्यों इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि वे पैसा खर्च करके यहां आएं। चेयरमैन सर, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। आप भी जब यहां

से सफर करके रोहतक या कहीं और जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि रात के वक्त जितने भी वाहन आपको मिले होंगे चाहे वह फोर व्हीलर हो, ट्रक हो या ट्रैक्टर ट्राली हो, आपने किसी के पीछे भी रैड लाईट लगी नहीं देखी होगी। सड्कों के०पर बड़े–बड़े वाहन खड़े होते हैं और उन वाहनों के पीछे रेड लाइट न होने की वजह से ऐक्सीडैंट्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। चेयरमैन सर, आपको पता है कि ऐसे लोगों की हजारों में गिनती है जो ऐक्सीडेंट में मर जाते हैं। इस बारे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट का कानून है और उसमें पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि कानून इन्फोर्स क्यों नहीं किया जाता है। पूरे समाज ने और पूरे देश ने इस बारे में आखें मीची हुई हैं और इस वजह से बेगुनाह लोग मरने लग रहे हैं और परिवार उजड़ने लग रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को चाहिए कि उस कानून के तहत पुलिस के अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी करे कि जिस वाहन के पीछे लाइट रात की रोशनी के लिए नहीं होगी, उनके खिलाफ पुलिस के अधिकारी को सख्त ऐक्शन लेना चाहिए और इस कानून को सख्ती से इन्फोर्स करना चाहिए।

श्री देवेन्द्र द्वार बंसल (अम्बाला छावनी): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे माननीय साथी श्री विनोद शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि चौधरी रणबीर सिंह जी की प्रतिमा संसद भवन में

लगाई जाए मैं उसका भी अनुमोदन करता हूं। वार्षिक योजना का आकार 6650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये किया गया जोकि व्यापक विकास के लिए बिजली, सड़कें, भवन और जलापूर्ति के लिए किया गया है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कृषि के लिए 41249 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। इस कदम से हमारे गरीब किसान और मजदूरों को प्रोत्साहन मिलेगा! उनका मनोबल बढ़ेगा और वाकई उन्हें महसूस होगा कि उन्हें सरकार की ओर से सम्मान दिया गया है। गेहूं पर सबसिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और भवन व सड्कों के लिए 1540 करोड़ रुपये का वर्ष 2009 में प्रस्ताव रखा गया है, शहरी विकास के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है उसके लिए भी बधाई देता हूँ। चेयरमैन सर, यह जो हाउस टैक्स इस साल माफ किए गए हे उससे कमजोर वर्गों कै लाखों परिवारों को लाभ पहुंचा छै। जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको हाउस टैक्स का भुगतान करने में काफी समस्या होती थी। हाउस टैक्स की माफी के लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हालांकि सरकार को 40 करोड़ रुपये की राशि म्यूनिसिपल कमेटीज को इस नुकसान के ऐवज में देनी पड़ी। हरियाणा में कई विकास के कदम उठाये गये हैं। सड्कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ। कई सुविधायें जनता को दी गई। इनसे उद्योग को काफी बढ़ावा मिला है। इस प्रदेश में 1347 बड़े उद्योग हैं और 80 हजार लघु उद्योग हैं

उन्होंने इस साल 50 हजार करोड़ रुपये की ऐक्सपोर्ट की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने कितना विकास किया है जिसकी वजह से हमारी इण्डस्ट्रीज में से बहुत बड़े लैवल पर ऐक्सपोर्ट हुआ है। इसके अलावा सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त में मकान बनाकर दिये जा रहे हैं, हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है। 50 हजार मकान सरकार कमजोर वर्गों के लिए बनाकर दे रही है। अम्बाला में भी 500 ऐसे मकानों का प्रावधान है और उनका कार्य शुरू हो चुका है। कुछ मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं और कमजोर वर्ग के भाइयों को उनका कब्जा दे दिया गया है। ऐजुकेशन की फील्ड में जो कदम सरकार ने उठाये हैं उनमें आठवीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबें दी हैं, फीस माफ की है। मिड डे मील को आठवीं कक्षा तक बढ़ाया है। चेयरमैन सर, मेरी यह मांग है कि इतना बड़ा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया है तो साथ ही हमारे जो बड़े विद्यार्थी हैं जो 8वीं कक्षा मैं पढ़ते हैं उनका आज की टैक्नीक की पढ़ाई करने के लिए कम्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कैलकुलेटर्ज की हर वक्त जरूरत होती है। उनको इन चीजों को खरीदने में बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके पेरेन्ट्स इसके लिए लोन लेते हैं, कई बार उधार भी लेना पड़ता है। इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि उन बच्चों को इन इंस्ट्रूमैंट्स को खरीदने के लिए कोई न कोई सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि उनको यह इंस्ट्रूमैंट्स खरीदने में आसानी हो सके। चाहे यह लिमिट तय हो जाए कि पांच साल में यह इंस्ट्रूमैंट खरीद सकेंगे, तीन साल में यह मिलेंगे आज यह विद्यार्थियो की

नैसेसिटी बन गई है। आज हर डिपार्टमैंट के लिए लैपटॉप और कम्यूटर जरूरी हो गये हैं। चाहे आर्ट्स फैकल्टी है, चाहे साईंस फैकल्टी है, आज हर स्टुडैण्ट के लिए यह जरूरी हो गया है। आज के समय में जो टैक्नीकल एजुकेशन इंस्टीप्यूट्स दूर–दूर हो गये हैं। उनकी दूरी को कम करने के लिए व्हीकल्ज जरूरी हो गये हैं। इसके लिए आपको कोई न कोई ऐसा कन्सेशन का प्रावधान स्टुडैंट्स के लिए करना चाहिए ताकि वे अपने व्हीकल्ज खरीद सकें। इस कन्सेशन से वे अपने पेरेन्ट्स का बर्डन कम कर सकेंगे पेरेन्ट्स ये चीजें अपने बच्चों को मुहैया करा सकेंगे। अब मैं आपके माध्यम से इस सदन में अम्बाला की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा। अम्बाला कैंट की जनता को काफी समय से सिविल अस्पताल के बारे में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर 7–8 डाक्टर्ज हैं लेकिन इस अस्पताल में कोई भी लेटैस्ट इक्विपमैंट्स नहीं हैं जिसकी वजह से अम्बाला के स्लम इलाके के लोगों को और आसपास के इलाके के लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अम्बाला का अस्पताल केवल रेफरल हॉस्पिटल बन कर रह गया है। अम्बाला में जो फी होल्ड का प्रोसैस था वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने 90 प्रतिशत पूरा कर दिया है। सर, सैंटर द्वारा स्टेट को लैंड ट्रांसफर कर दी गई है लेकिन सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा लैंड ट्रांसफर होनी बाकी है। वह कार्य भी तुरन्त किया जाए क्योंकि इस कार्य के पूरा न होने की वजह से अधिकारी मनमानी करते हैं। वे कभी किसी की दुकान को कभी किसी के मकान को गिरा देते हैं क्योंकि हजारों मकान ऐसे

हैं जिनकी लीज खत्म हो गई हैं। इसी प्रॉबल्म की वजह से वह लीज दोबारा से एक्सटैण्ड नहीं हुई। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इस फीहोल्ड के कार्य को तुरन्त किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अम्बाला छावनी में पीने के लिए नहरी पानी दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके लिए एक समस्या नई आई है नहरी पानी आने की वजह से अम्बाला कैंट में मेन बाजार की कई जगह से सड़कें टूट गई हैं और जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते के अन्दर कई जगह एक्सीडैंट्स हो गये हैं और कई बच्चों को चोटें लग गई हैं और एक दो बच्चे भी उन गड्ढों में गिर गये। इसलिए उन सड्कों की तुरन्त मरम्मत की जाए ताकि यह समस्या खत्म हो सके। इसके अलावा जो ढाबों पर वैट टैक्स लगाया है वह ढाबा चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। उसके लिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि छोटे ढाबों के लिए यह वैट टैक्स चूल्हा टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक सबसे बड़ी समस्या सभी शहरों में यह है कि हर शहर के गेट–वें पर शराब के ठेके खोल रखे हैँ जिसकी वजह सै वहां पर एक बुरा सा इम्प्रैशन पड़ता है क्योंकि वहां पर लोगों का काफी देर तक आना जाना रहता है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि शराब के ठेके शहर के गेट–वे से हटाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किये जाएं। अम्बाला कैंट में जो 70–80 कालोनीज हैं जिनमें छोटा शिवालिक और श्यामनगर की कालोनीज है उन कालोनीज के अन्दर पूरी कंस्ट्रक्शन हुई हैं सड़कें तक बनी हुई हैं every thing

is complete परन्तु वे अन–एथोराईज्ड कॉलोनीज हैं उनको एथोराईज किया जाए ताकि आने वाले समय में वे कॉलोनीज शहर से जुड़ सकें। अम्बाला शहर के साथ लगते जो गांव हैं उनकी सड्कों का निर्माण तो हो चुका है लेकिन कई जगह से वे टूटी हुई हैं उनका जल्दी से निर्माण किया जाए। इसके अलावा अम्बाला कैंट के सीवरेज का कार्य काफी समय पहले शुरू हो चुका है लेकिन 5–6 महीने से वह कार्य बंद है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस कार्य को जल्दी से शुरू करवाया जाए और जल्दी से पूरा किया जाए।

श्री धर्मवीर (गुड़गांव): धन्यवाद चेयरमैन साहब, मैं 10 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा पेश किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्लानिंग का पैसा इस सरकार से मिला है जो पिछले सालों में 6650 करोड़ रुपये के करीब मिला था। इस सरकार की कारगुजारी और डिवैल्पमैंट को देखकर वह पैसा अब दस हजार करोड़ कर दिया गया है। किसी गवर्नमैंट को इससे बड़ा सर्टीफिकेट और क्या मिल सकता है जिसकी प्लानिंग का पैसा आलमोस्ट दुगुना कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस बात के वे हकदार हैं। एक ही बात इनके दिमाग में रहती है कि कैसे डिवैल्पमैंट किया जाए। कैसे पैसे का प्रोपरली पूज किया जाए

और कैसे पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर महकमे के लिए किया जाए। मैं शहरी कांस्टीच्यूंसी को प्रिजाइड करता हूँ। आज शहरों में पावर की, रोड्ज की, सीवरेज की, पानी की और अस्पतालों की जरूरत है इसलिए मैं इनके बारे में जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए इन्होंने प्लानिंग में 120 करोड़ रुपये के करीब पैसा रखा है लेकिन साथ में इन्होंने यह भी शर्त लगा दी कि हमने 73 टाउनस ऐसे इयरमार्क क्य दिए हैं जिन्हें डिवैल्पमैंट की जरूरत है। इस बात को गवर्नमैंट कैसे भूल गई कि कुछ शहरों का शहरीकरण हो रहा है और कुछ शहरों का अभी शहरीकरण होना है। जिन्हें हम अनअथोराइजड कालोनियां कहते हैं जब तक इनको डिवैल्पमैंट में शामिल नहीं किया जाएगा तव तक मसला हल नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं अर्ज करता हूँ कि जब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ था उस समय वहां की आबादी 7000 के करीब थी। जब मैंने 1982 में पहला इलैक्शन लड़ा उस वक्त गुड़गांव की आबादी 95 हजार थी और आज गुड़गांव की आबादी 14 लाख की है। जो गवर्नमैंट का एस्टीमेट है उसके हिसाब से 2021 तक गुड़गांव की आबादी 32 लाख हो जाएगी जबकि मैं समझता हूं कि 2021 तक गुड़गांव की आबादी 40 से 45 लाख तक हो जाएगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस 120 करोड़ रुपये से क्या होगा। अकेले गुड़गांव शहर की ही नहीं बल्कि रोहतक शहर की, फरीदाबाद शहर की और अम्बाला शहर की आबादी बढ़ रही है। हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्यार्टर की 'आबादी बढ़ रही है? इसलिए हमें पैसा चाहिए। हमें डिवैल्पमैंट के कामों के लिए

पैसा चाहिए। रोड्ज के काटसे के लिए भी पैसा चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए मुख्यमंत्री महोदय की दाद देना चाहूंगा कि मेरी उनसे कई बार बात हुई कि आप मीटिंग्ज में बार–बार अनाउसमैंट करते हैं कि हम 2010 अप्रैल में बिजली देंगें जबकि मैं कहता हूँ कि इलैक्शन फरवरी में हो जाएंगें तो वे कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता बल्कि जो असलियत है मैं वहीं कहूँगा। जबकि विपक्ष के लोग मेरी कांस्टीच्युंसी के बस्तर गांव में 35 आदमियों के साथ आए। 4 गांवों से आदमी इकट्ठे करके भी ये 100 आदमी पूरे नहीं कर पाए। अनाउसमैट तो जो किया सो किया लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि वहां उस मीटिंग में एक नौजवान को खड़े होना पड़ा और कहना पड़ा कि अब तक आप हमें बहकाते रहे हो, अबा बहकाना बंद करो। अब हम तुम्हारे साथ नहीं लगेगें। यह सारा किस्सा बहुपुर गांव का है। वह नौजवान कहने लगा कि आप हमें यह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक करोड़ का किल्ला दूंगा, जिस वक्त आप पावर में थे उस वक्त दो लाख देते थे इसलिए अब अगर पावर में आ गए तो ये भी नहीं दोगे और ये भी छीन लोगे इसलिए हमारे से ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। उस नौजवान ने मीटिंग में इनको मुंह पर ऐसा कह दिया। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वे कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता बल्कि जो असलियत है वही कहता हूँ। ये कहते हैं कि हम अप्रैल, 2010 तक बिजली दे पाएंगें, फरवरी, 2010 तक पूरी बिजली नहीं दे पाएंगें। गुड़गांव में मैट्रो के बारे में भी इन्होंने यही कहा कि गुड़गांव में मैट्रो आ रहा है और वह जनवरी फरवरी में शुरू हो

यह मैं नही कहता, मैट्रो 2009 में शुरू हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री महोदय की दाद देता हूं कि ये सच बोलते हैं क्योंकि झूठ के तो पैर नहीं हुआ करते। सभापति महोदय, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर कर दिया है। हाउस में हैल्थ के बारे में बहुत चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जितनी डिवैल्पमैंट शहरों के अदर हुई है उतनी गांवों के अंदर नहीं हुई। मैं एक बात ज्या हूँ कि क्या गांव वालों को हरियाणा में रहने का हक नहीं है। हम हैल्थ के बारे में कितनी फेसीलिटीज गांव वालों को देते हैं और शहर में हैल्थ की कितनी फेसीलिटीज हैं और कितनी अभी और जरूरत हैं। कल फाइनैंस बिल आ रहा है उसमें पता लग जाएगा कि कितना पैसा इन्होंने इसके लिए रखा है। कितना पैसा और डिवैल्पमैंट के लिए है। सभापति महोदय, आज शहरों में स्पैशलाइजेशन की बहुत जरूरत है। हमारे गुड़गांव के अस्पताल में स्पैशलाईजेशन बहुत ज्यादा है। वहाँ पर एम०आर०आई० का सिस्टम भी है, अल्ट्रासाऊंड के साथ–साथ और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारा कुछ हमें वहाँ पर प्रोवाईड किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाकी शहरों को भी आज इसकी जरूरत है। हैल्थ के बारे में हमें बहुत कुछ सोच विचार करके करना पड़ेगा। रोड्ज के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि रोड्ज के बारे में जो कुछ कहा गया है वह काफी है, सफीशिएंट है। लेकिन आज जिस तरीके से हमें रोड् ज की जरूरत पड़ रही है। हमारे गुड़गांव के अंदर पहले दिल्ली को जाने के लिए एक रास्ता होता था। लेकिन आज पांच रास्ते

हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि यह सफीशिएंट है। हमें आज भी और रोड्ज की जरूरत है। हमारे रोड्ज की कंस्ट्रक्शन का काम हुडा, हमारी नगर निगम और पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा किया जाता है। माननीय मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं वरना तो मैं उन्हें कहता कि एक सौ गज के रेलवे ओवरब्रिज के लिए तीन साल लग जायें इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। क्या उनको इस रेलवे ओवरब्रिज कै न होने से लोगों को होने वाली दिक्कत महसूस नहीं होती। ये स्वयं तो एयरकंडीशंड कमरों में बैठे रहते हैं इन्हें क्या पता कि लोग हमारी कितनी जान खाते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप इनको कहो कि ये इस मामले को एक्सपिडाईट करें। गुड़गांव में जहां तक रोड्ज का सम्बन्ध है इनका हरेक मामला सुस्त पड़ा है। मुझे आज ये बता दें कि गुड़गांव के अन्दर कोई पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा रोड बनाई गई हो। आखिरकार हमें ही नगर निगम को रोड्ज को टेकओवर करने के लिए गुजारिश करनी पड़ी कि नगर निगम ही गुडगांव के रोड्ज को बना दे और पी०डब्ल्यू०डी० वाले न बनायें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि माननीय सदस्यों और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन रोड्ज के लिए जितना भी प्लानिंग में बजट रखा गया है वह शायद सफीशिएंट नहीं रहेगा और आखिरकार हमें उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पावर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री

महोदय ने बहुत कुछ कहा है कि 1500 मैगावाट का प्रोविजन सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में भी है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड, हिसार में भी है और सबसे बड़ा जो थर्मल प्लांट झाडली, झज्जर में बनाया जा रहा है उसमें भी 750 मैगावाट बिजली हमें मिलेगी। इसके अलावा भी सरकार ने प्रोविजन रखा है कि अगर कोई प्राईवेट तौर पर बिजली का उत्पादन करके सरकार को देना चाहे तो सरकार उसको भी ले लेगी। इस प्रकार से हम विकास के मामले में बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम डिवैल्पमैंट भी सत त् करते जा रहे हैं और हमारा इरादा भी है कि डिवैल्पमैंट भी बहुत ज्यादा हो। मैं समझता हूँ कि इस ओर हमारी सरकार चल रही है कि किसी न किसी तरीके से हम विकास के शिखर पर पहुंच जायें। आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है और पूरे हिन्दुस्तान में हम गोवा के बाद दूसरे नम्बर पर हैं। मैं यह कहता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा हमसे आगे क्यों हैं। अगर हमारे सभी प्रोग्राम्ज और ज्यादा अच्छे हो जायें तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम गोवा से भी आगे निकल सकते हैं और पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर आ सकते हैं। अगर ऐसा हो जाये तो वह अच्छा ही होगा। किसानों के बारे में सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सोचा और गन्ने के रेट क्रमशः 160, 165 और 170 रुपये प्रति क्विंटल तक निर्धारित किये। यह हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि जितनी भी सहूलियतें सरकार किसानों को दे वह अच्छा है। सभापति महोदय मैं बी०पी०एल० के

कार्डों के बारे में एक बात करना चाहता हूं बी०पी०एल० के कार्ड सरकार द्वारा बहुत ज्यादा संख्या में लगभग 7 लाख के करीब जारी कर दिए गए .हैं। लेकिन मेरी फिर भी सरकार से यह रिक्वैस्ट है कि इतनी भारी संख्या में बी०पी०एल० कार्ड जारी करने के बावजूद भी कोई डिजरविंग कैंडीडेट नहीं रहना चाहिए भले ही उनकी संख्या 7 लाख के स्थान पर 9 लाख हो जाये यही मेरी आपके माध्यम से गवर्नमैंट से रिक्वैस्ट है। इसी प्रकार से और भी डिवैल्पमैंट के काम सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। टूरिज्म का भी जिक्र किया गया है। फारस्ट की डिवैल्पमैंट के लिए भी सरकार प्रयासरत है। सभापति महोदय, मैं आपसे एक रिक्वैस्ट यह करूंगा कि आप परिवहन मंत्री से कहकर ट्रांसपोर्ट को थोड़ा ठीक करवा दें क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट के बारे में यहां पर काफी कुछ कहा गया है। मैं भी यह मानता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ही खराब है। मेरी भी गुप्ता जी से यही रिक्वैस्ट है कि जितना हो सके उसमें सुधार करने की कोशिश करें क्योंकि ट्रॉंसपोर्ट की सही सुविधा न होने के कारण शहरों के साथ–साथ गांव के लोगों को भी बहुत ज्यादा असुविधा होती है। आज प्राईवेट ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी है कि कोई साधारण आदमी उसका खर्च वहन नहीं कर सकता। सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापतिः मान साहब, आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई): सभापति महोदय, पहले इनको चुप तो कराओ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः सभापति महोदय, ...

श्री सभापतिः डॉ० इन्दौरा प्लीज टेक यूअर सीट। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौराः सभापति महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्षः आप किसकी परमिशन से बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded. Mr. Indora. you must behave properly. You must behave properly. It is not the way. आप कितने मिनट बोले थे? क्या किसी ने इन्टरफियर किया? आपने क्या–क्या कहा लेकिन कोई भी बीच में नहीं बोला।

डॉ० सुशील इन्दौराः सर, मैं 50 मिनट बोला था। लेकिन्.। मेरा प्याइंट ऑफ ऑर्डर है सर।

Mr. Speaker : With my permission Shri Tejender Pal Singh Mann is speaking and he is on his legs. (Interruptions) No point of order.

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्षः ये क्या कर रहे हैं आप? It is not the way. (Interruptions) It is not the way (interruptions) You must behave properly. क्या शर्म और बेशर्म की डैफिनेशन का पता है आपको? आप 54 मिनट बोले लेकिन no Member has pointed out anything. You have explained many-many things. You have made many derogatory remarks against the Government. No Member has objected. (interruptions) Mann Sahib, please speak.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में बहुत सी महान् विभूतियाँ हमें छोड़ कर चली गयी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः 100 चूहे खा कर बिल्ली हज को चली (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. (interruptions) Nothing to be recorded. Marm Sahib, please continue your speech.

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. मान साहब,

आप बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः सर, मैं ऐसे कैसे बोलूं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ० सीता राम जी, आप लोगों को कोई चाबी भर कर भेजता है क्या? (शोर एवं व्यवधान) चलो अगर नहीं भरी है तो कोई बात नहीं Mann Sahib, please continue your speech. (शोर एवं व्यवधान) एक माननीय शरस्य अपनी बात कह रहा है। गवर्नर एड्रैस पर बोल रहा है। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन और इस सैशन के बीच बहुत सी महान विभूतियाँ हमें छोड़ कर चली गई उनमें पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. (interruptions) Dr. Sahib, is it a pre-planed to disturb the House. अगर आपकी प्लान यह है कि आपने हाऊस को डिस्टर्ब करना है तो I am sorry. I am sorry. (interruptions) Nothing to be recorded. (interruptions) Nothing to be recorded. डॉ० साहब, आप क्या सिखा रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded. माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। मान साहब,

आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के ही बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी, हम सबके जाने पहचाने आज हमारे बीच में नहीं रहे उनके बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, ...

16.00 बजे

Mr. Speaker : Nothing to be recorded (Interruptions). भाई साहब, आप इनको क्या सिखा रहे हैं। आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

डा० सीता रामः स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker : Nothing to be recorded (Interruptions).

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, ये लोग सड़क पर गुण्डगर्दी करते हैं जो बड़ी शर्म की बात है। (विष्य) ऐसा सब को बुरा लगता है और हर गरीब आदमी इनको शर्मिन्दा करता है ऐसी सूरत में तो ऐसे लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्षः डॉ० साहब, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) I am on legs please go to your seats.

(Interruptions) Mr. Chirana, go to your seat. (Interruptions and noices) Mr. Chirana, I warn you. (Interruptions) I warn you. I warn you. (Interruptions) Please take your seats. (Interruptions) Nothing to be recorded. (Interruptions)

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्षः इन्दौरा साहब, आप अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) डा० साहब, आप अपनी सीट पर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर सर, ...

श्री साहिदा खानः स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्षः डा० साहब, आप इनको अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहें। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded.

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, ये लोग केवल खबर बनाने के लिए हाउस में आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः Nothing to be recorded (Interruptions and noices) इन्दौरा साहब, आप कल 54 मिनट्स बोल चुके हैं। इन 54 मिनट्स की अपनी लीच में क्या आपने कोई बात उठाई।

(शोर एवं व्यवधान) आज इस खिलौने में आप कौन सी चाबी भर कर लाये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, इनकी रैली फेल हो गई है। (शोर एवं व्यवधान) इनकी रैली में आदमी आए नहीं इसलिए ये लोग यहां पर सस्पैंड होने के लिए आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is a matter of shame on your part. (interruptions). It is a matter of shame on your part. नरेश शर्मा जी, आप प्लीज अपनी सीट पर जाएं। छत्तरपाल सिंह जी, प्लीज आप भी अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) डाक्टर इन्दौरा जी, आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, आप जो भी बोलना चाहते हैं वह अपनी सीट पर जाकर बोलें। (शोर एवं व्यवधान) I allow you to speak. PHease you go to your seat and speak. (Noise and Interruptions). चलो आप जो बोलना चाहते हो वह अपनी सीट पर जाकर बोलो। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, ******

श्री अध्यक्षः आपको जो कुछ भी बोलना है अपनी सीट पर जाकर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, ******

Dr. Sita Ram : Speaker Sir, ******

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram J i, please go to your seat.

Dr. Sita Ram : Speaker Sir, ******* (Noise and Interrutpions).

Mr. Speaker : Hon'ble Member Dr. Sita Ram, who was not present in the Question Hour. उस समय इनका सवाल आया था। डॉक्टर इन्दौरा का भी सवाल आया शा और ये सदन में उपस्थित नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का निलम्बन

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, in the light of the disorderly behaviour of Dr. Sita Ram, **I** hereby want to bring a resolution in the House.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That Dr. Sita Ram M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

Mr. Speaker : Motion moved -

That Dr. Sita Ram M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible

behaviour, unbecoming the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

Mr. Speaker : Question is —

That Dr. Sita Ram M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

(The motion was carried)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram Ji, please go out from the House.

(At this stage Dr. Sita Ram, M.L.A. withdrew from the House himself)

Mr. Speaker : Mr. Mann Sahib, please continue your speech. (Noise and Interruptions).

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, *******

Mr. Speaker : Indora ji, please go to your seat. (Noise and Interrutptions). **Dr. Sushil Indora :** Speaker Sir, ********

Mr. Speaker : Indora ji, I warn you. Please go to your seat. (Noise and Interruptions). Mr. Indora, I again warn you. (Noise and Interruptions).

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक और प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That Dr. Sushi! Indora, M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Dr. Sushi! Indora, M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

Mr. Speaker : Question is —

That Dr. Sushi! Indora, M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

(The motion was carried)

(At this stage Dr. Sushi! Indora, M.L.A. withdrew from the House himself)

Mr. Speaker : Mann Sahib, please continue your speech. (Noise and Interruptions).

Shri Sahida Khan : Speaker Sir, ****

Mr. Speaker : Sahida Khan Ji, I allow you to speak. Please go to your seat. (Noise and Interruptions). Sahida Khan Ji, I allow you to speak. (Noise and Interruptions). Sahida Khan ji, I warn you. साहिदा खान जी, आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Sahida Khan ji, I warn you. Nothing to be recorded.

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब .....

श्री रामफल चिडानाः स्पीकर साहबः .....

श्री ज्ञान चन्द ओढः स्पीकर साहबः .....

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जाएं। I warn all of you. आप अपनी–अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान)। I again warn all of you.

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक और प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That Shri Sahida Khan, Shri Ramphal Chirana, Shri Balwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh, M.L.As be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

Mr. Speaker : Motion moved--

That Shri Sahida Khan, Shri Ramphal Chirana, Shri Balwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh, M.L.As be suspended from the service of the House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

Mr. Speaker : Question is—

That Shri Sahida Khan, Shri Ramphal Chirana, Shri BaHwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh, M.L.As be suspended from the service of the Home for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for the today's sitting of the present session.

(the motion was carried)

Mr. Speaker : Shri Sahida Khan, Shri Ramphal

Chirana, Shri Balwant Singh Sadhaura and Shri Gian Chand Oadh, M.L.As, please go out from the House.

(At this stage Shri Sahida. Khan, Shri Ramphal Chirana, Shri Balwant Singh Salhaura and Shri Ginn Chand Oadh withdrew from the House themselves.

Mr. Speaker : Mann Sahib, please continue your speech. (Noise and Interruptions).

श्रीमती रेखा राणाः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप तो शरीफ हैं इसलिए आप तो बैठें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः रेखा –बेटी, आप तो बैठ जाओ। आप तो अपनी हो इसलिए आप तो बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती रेखा राणाः स्पीकर साहब,. मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि माननीय सदस्य विधान सभा में इस हाउस में जब अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात अनसुनी क्यों की जाती है?

श्री अध्यक्षः बहन जी, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा है कि परसों शायद आप हाउस में नहीं थी इसलिए आपको पता नहीं है। उस दिन सुशील इन्दौरा 54 मिनट बोले थे और रामफल चिड़ाना 19 मिनट बोले थे। इस तरह से 73 मिनट वे दोनों सदस्य

बोले हैं और बीच में कोई टीका टाकी भी नहीं की। उन्होंने सारी बातें तफसील से उठाई और अपनी मर्जी से बैठे, हमने बैठने के लिए भी नहीं कहा। हमने तो यह कहा कि जितना टाइम आप बोलना चाहें, बोलें। यह हाउस है यहां 90 सदस्य बैठते हैं। यहां का टाइम वैल्यूएबल होता है। एक आदमी पूरे हाउस का टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर एक आदमी खांड तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करेगा तो उसे बोलने के लिए कैसे अलाऊ करेंगे? बहन जी, आप तो समझदार हैं, सयानी हैं आप भी ऐसे करेंगी तो कैसे काम चलेगा? (विघ्न)

श्रीमती रेखा राणाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी आप इंक्वायरी करवाइए। विघ्न) सड़कें जो बनाई गई हैं उनकी इंक्यायरी करवाएं। यह मेरी मांग है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, इनको अपनी बात कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्षः बहन जी, मैं आपको मान साहब से पहले अलाऊ करता हूं।

श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय, पर ये लोग बीच में नहीं बोलें। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सदस्य अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए और अच्छाई का आप साथ देते हो तो मैं भी आपका साथ दूंगी। यदि

विपक्ष को आप वाकआउट करने के लिए मजबूर करते हैं या उनको अपनी बात कहने के लिए समय नहीं दिया जाता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सप्लीमैंट्री पूछने का अधिकार सबको

श्री अध्यक्षः कल आपकी पार्टी के सदस्य 73 मिनट कंटीन्यू बोले हैं। आप 2006 से पहले छह साल का रिकार्ड उठाकर देख लें कि क्या कभी इससे पूर्व 73 मिनट विपक्ष को दिये गये हैं। जबकि 22, 30 और 40–40 तक एम०एल०ए० रहे हैं उसके बावजूद भी इतना समय कभी नहीं दिया गया।

श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए क्या–क्या विकास कार्य हो रहे हैं इस बारे में इस साल की रिपोर्ट बताइए। मैं यह विवरण चाहती हूं। लिखित में जवाब चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः महिलाओं के बारे में क्या डिवैल्पमैंट हो रही हे उसकी कॉपी आपको सप्लाई की जाएगी। क्या आपने वह डिवैल्पमैंट पड़ी है जो महिलाओं के बारे में छपी है? श्रीमती रेखा राणाः मैं वर्ष के हिसाब से मांग रही हूं कि इस वर्ष क्या हुआ है? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आपने गवर्नर ऐड्रस पर यह बात उठाई है कल चीफ मिनिस्टर साहब देंगे and he will give the repHy to your question. उनके रिप्लाई के समय आप बैठना और सुनना कि क्या–क्या किया है।

श्रीमती रेखा 'राणाः मैं सुन रही हूं बैठी हूं। सप्लीमैट्री पर कोई सदस्य बोलना चाहता हे तो उसे बोलने नहीं जाता। उनकी अवहेलना की जाती है, उनका अनादर किया जाता हे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः यह गवर्नर ऐड्रस पर डिबेट चल रही है न कि क्वैंशचंज ऑवर पर सप्लीमैंट्री चल रही है।

श्रीमती रेखा राणाः यह जो विकास के बारे में पुलिंदे बांधे जा रहे हैं क्या ये सही. हैं? यदि ये सही नही हैं तो उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दिया जाता है।

श्री हर्ष कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या हर सदस्य की तरफ उंगली कर देती हैं।

श्री अध्यक्षः बहन जी, मैं आपको 1 छ मिनट का समय बोलने के लिए देता हूं। श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उंगली कर देती हूं। उंगली करना इशारा दिखाना है न कि कुछ और है। उंगली उसको दिखाई जाती है जो समझदार होता है 1 (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप ऐसे शब्द न बोलें। हर आदमी को अपने से ज्यादा कोई समझदार लगता ही नहीं है।

श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिए खड़ी हुई हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य जिनको बाहर भेजा गया हे उन्हें

या तो वापस बुला लिया जाए या मैं भी वाकआउट करके जाती हूं।

श्री अध्यक्षः आप भी जाना चाहती हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इन्हें आधे घण्टे का समय बोलने के लिए दिया जाए।

श्रीमती रेखा राणाः सुनवाई तो होती नहीं है, बोलूं क्या।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः हम सुनवाई करेंगे, हम आपके छोटे भाई हैं आपकी बात सुनेंगे।

श्री अध्यक्षः आप यह बताएं कि आप उनको सदन में वापस बुलाने पर जोर दे रही हैं। क्या उनका जो रवैया यहां था वह ठीक था?

श्रीमती रेखा राणाः रवैये के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि रवैया आपके सामने है। आप रवैये के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आढ़तियों के खिलाफ करनाल में घरौंडा मंडी में एफ०आई०आर० लीज हुई, वहां का डी०एफ०एस०ओ० शायद आपके सम्मानित सदस्यों में से किसी का रिश्तेदार भी लगता है। उसने किसानों को कुछ ले देकर किसानों के द्वारा मुआवजा मिलने या न मिलने के बारे में आढ़तियों के खिलाफ एफ०आई०आर० लीज कराई है और उनके खिलाफ केस दर्ज कराये हैं। मैं जानना

चाहती हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है। कसूरवार को कसूरवार ठहराकर उसको दण्डित किया जाए।

वाक आउट

श्री अध्यक्षः ठीक है बहन जी, क्या आपने इसके अलावा कुछ और भी कहना है। श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी पार्टी के जिन सम्मानित साथियों को आपने बाहर भेजा है उनको सदन में वापिस बुला लिया जाए।

श्री अध्यक्षः वे मैंने नहीं भेजे हैं।

श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय, आपने ही उनको बाहर भेजा है। मेरी आपसे पुनः गुजारिश है कि आप उनको सदन में वापिस बुला लें। अगर आप उनको सदन में नहीं बुलाते हैं तो मैं भी एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करती हूं।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी की सदन में उपस्थित एक मात्र सदस्या श्रीमती रेखा राणा सदन से वीक आउट कर गई

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से लगातार हर सत्र में विपक्ष के माननीय सदस्य चाहे वे इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों और चाहे नेशनलिस्टस कांग्रेस पार्टी

के सदस्य हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों और चाहे हमारे इण्डिपेंडेंट सदस्य हों, आपका रवैया हमेशा निष्पक्ष और पक्षपात रहित होता है। आपने सभी सदस्यों को लगातार बोलने का मौका दिया है चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, आपने एक जज के समान सभी को बराबर का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो सदस्य हैं उनके मन की अथाह पीड़ा है और एक बीमार मानसिकता का नतीजा है कि आपके लाख सकारात्मक प्रयासों के बावजूद उनकी वह पीड़ा निकल नहीं पाती। फेल हुई जनआक्रोश पद यात्रा के बाद आज उनकी रैली भी फेल हो गई क्योंकि उनको हरियाणा के लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए न तो सदन के नेता कुछ कर सकते हैं और न ही कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ कर सकते हैं और न ही दूसरे दल के नेता कुछ कर सकते हैं। जब उस रैली में लोग नहीं आये और कुछ को यह कह दिया गया कि तुम अब विधानसभा में जाकर अनर्गल और अशोभनीय बात करें और आज भी सम्मानित सदस्य श्री राधेश्याम शर्मा जी और श्री नरेश शर्मा जी भी उन्हें यह कहने के लिए आये कि श्री तेजेन्द्र पाल मान जी तो इण्डिपेंडेंट चुनकर आये हैं उन्हें भी अपनी बात कहने का बराबर का हक सदन में है। इनैलो के सदस्यों को आपने 75 मिनट का बोलने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय यहां तक कि आपने परसों डाक्टर सीताराम जी के पास अपने सचिव को भेजा और कहा कि आप गवर्नर एड्रैस पर बोलिए और डाक्टर सीताराम जी ने कहा कि मेरे पास बोलने के लिए कोई मसाला नहीं है।

उसके बाद आपने साहिदा खीं जी को कहा। साहिदा खीं जी ने भी कहा कि मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है और वे बैठे–बैठे कामैन्ट्री करते रहे। इसके अलावा जब बहुजन समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे तो उस समय उनकी सोच में वे माननीय सदस्य व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे थे। जब आपने सत्ता पक्ष के साथियों को निर्देश दिया कि किसी सदस्य ने बीच में किसी प्रकार की कोई टीका–टिप्पणी नहीं करनी है चाहे वह गलत भी कहें और एक कानून की तरह हमने अपनी बात को माना। जब इन्दौरा जी बोल रहे थे उन्होंने घोर अनर्गल और अशोभनीय चाते कही तो सत्ता पक्ष के किसी सदस्य ने और इण्डिपैंडेट सदस्यों ने कोई टिप्पणी उन पर नहीं की। जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे तो वे उनको मारने को दौड़े। जब बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य बोल रहे थे तो उनकी तरफ आक्रामक रूख उन्होंने अपनाया। आज जब इण्डिपेंडेंट साथी राधेश्याम जी और नरेश शर्मा जी केवल हाथ जोड़कर उनसे विनती करने के लिए आए तो उन पर भी आक्रामक रूख और मारने के लिए उन की तरफ दौड़े। उनका यह किस प्रकार का रवैया है, किस प्रकार से विधानसभा और विधायिका चलेगी, किन मापदण्डों से यह विधायिका चलने वाली है। अध्यक्ष महोदय, कालेज की बहुत सारी नौजवान छात्राएं आज इस विधान सभा की कार्यवाही को देखने के लिए आई हुई थी। मुझे स्वयं, इस सदन को भी ओर विशेष तौर से सदन के नेता को भी इस बात की चिन्ता है कि जिस तरह से एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर

देती है उसी तरह से एक व्यक्ति की गलत मानसिकता, एक व्यक्ति की अपाहिज मानसिकता, एक व्यक्ति की बीमार मानसिकता पूरी विधायिका की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। आये दिन हम पूरे देश की विधायिकाओं के अन्दर देखते हैं कि किस प्रकार का दुव्यर्वहार सदस्य कर रहे हैं। अगर लोकदल के साथी समझते हैं कि उनका कद कोई खबर बनाकर०ंचा हो जाएगा, कल के समाचार पत्रों में सुर्खियां बनाकर उनका कद०ंचा हो जाएगा और वे अपने नेता या अपनी पार्टी की गरिमा को बना रहे हें तो मैं यह कहूंगा कि वे कम से कम बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। ये प्रजातंत्र है और हम आलोचनाओं को सर झुकाकार स्वीकार करेंगे। सरकार जहां गलती पर है हम हमेशा उसको दुरूस्त करने के लिए तैयार हैं। जब कई बार अच्छे सुझाव आते हैं, विपक्ष के सुझावों पर भी अनेकों सड्कों, अनेकों स्कीमों, अनेकों स्कूलों और अनेकों डिस्पैंसरियों के लिए करोड़ों रुपयों की अनाउसमैंट सदन के नेता खड़े होकर करते हैं, चाहे मंत्रीगण का जवाब यह भी हो कि हम बजट की कमी की वजह से नहीं दे सकते। सदन के नेता कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है यह ठीक नहीं है तो वे एकदम कहते हैं कि यह होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को कहूंगा कि यह काम हो और वे निर्देश देते हैं और उनके निर्देशों को हम लागू करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी कई बार सुझाव देते हैं, चाहे मंत्री का जवाब न में भी हो। विपक्ष के साथियों के जवाब पर चाहे विभाग का जवाब न में भी आ जाए तब भी आप मंत्रीगण और सरकार को निर्देश देते हैं कि नहीं, आपको नीति में बदलाव करने की

आवश्यक्ता है। अध्यक्ष महोदय, आपके हर शब्द को हम कानून की तरह मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार की उच्श्रृखलता का व्यवहार विपक्ष के साथियों ने किया है, केवल इसलिए कि चौटाला जी ने उन्हें कहा कि रैली फेल हो गई। यहां तो हरियाणा का जन समर्थन आया नहीं, यहां तो हरियाणा कै लोग आए नहीं। इसलिए आप विधान सभा में जाइए और वहीं उदण्डता और उच्श्रूखलता दिखाइए। उसी प्रकार की उच्श्रूखलता का व्यवहार करिए जिसके लिए लोकदल मशहूर है। एक पार्टी को रेहडी और दुकान लूटने वालों के नाम की संज्ञा दी जाती थी। उस पार्टी की जब रैली हुआ करती थी तो रेहडी वाला, गरीब आदमी, दुकानदार और दलित भाई सड्कों को छोड्कर चले जाते थे कि अमुक पार्टी की रैली है। अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत दूसरे विपक्षी दलों की भी रैली होती है उनमें ऐसा नहीं होता। इन्होंने उच्श्रृखल व्यवहार का उदाहरण दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह अशोभनीय और निंदनीय है और मैं सारे सदन से बड़ी विनम्रता से और हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा हालांकि उनके०पर निंदा प्रस्तावों का कोई असर नहीं होता क्योंकि जिन की शर्म का घड़ा उतर जाता है फिर उनकी किसी–प्रकार की शर्म नहीं बचती। अध्यक्ष महोदय, विधायिका की जो हमारी मान्यताएं हैं, उनका पालन करते हुए इस प्रकार के उच्श्रृखल और उदण्ड व्यवहार की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इन साथियों के व्यवहार के बारे में एक निंदा प्रस्ताव यह सदन पारित करे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मेरा आपके माध्यम से इस सदन को अनुरोध है।

Finance Minister (Sh. Birender Singh): Sir, the Parliamentary Affairs Minister has made a point that naming the Hon'ble members or sending them out of the House for one day or for the entire Session is not going to change their behaviour. I am not talking of only INLD, I am talking about any Hon'ble member, who is in the habit of creating problems for the House. If you want to tame them or if you want to contain them that such type of incident should not take place in the House then we must find some way out. I have seen in Parliament that very rare any member is named by the Hon'ble Speaker and that too when Parliament is to have a sitting for 50 days. There may not be any single instance when any member is named in the Parliament. In our House this has been the practice to name the Hon'ble Members. Whosoeve is the Speaker or sitting on the Chair of the Speaker, he use to see that by naming such members, if House comes to order then we may be able to transact our business but that has never happened. If the things are decided in a planned manner then things would be better. Sir, my suggestion to you is that if they have this fear in mind that even their membership can go or they can be disqualified for such behaviour then they would not behave like this, otherwise, this practice is not going to help anybody. I have seen adjourning the House twice or thrice in a day. In the previous Session, I have seen this but that does not serve the purpose. So, my humble submission to you is that there must be some methodology, where this type of behaviour, which is most unbecoming, should not be allowed. I do not know how they are being tutored or they have been asked to behave like that they do not have the brain. If they are to repeat here whatever is being tutored then it is most unfortunate. My humble submission is

either you appoint some Committee to see that which are the most stringent methods, by which they can be tamed. They should behave in a democratic way, otherwise, this kind of behaviour is most unbecoming. Even if Minister has proposed this but thing is not going to help us. This is the wastage of the House. This is what I want to submit, Sin

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, I would request that the Censure Motion atleast be carried. Of course, Ch. Birender Singh has given a valuable suggestion in this regard. Sir, I would request you to deliberate upon the issue and to take appropriate action. The Government will be more wilHing to abide by your direction in this regard.

Shri Tejender Pal Singh Mann: Mr. Speaker Sir, Shri Birender Singh has commented on the behaviour of the members in a positive manner. Such people who are always out to create problems, I think they come with a set mind that they are not going to let anybody speak in the House till the time they are there. I think you should tell them that if they will behave properly only then I will call them to speak, otherwise, there is no point of calling them to speak because once they come, they create problems and you send them out one by one. This is not going to serve the purpose.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: मान साहब, अब आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः धन्यवाद स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन और इस सैशन के दौरान बहुत सी विभूतियां हमारे बीच में से चली गई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति दोनों भी हमारे बचि में नहीं रहे, जिनके बारे में यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। हमारे बीच में से हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी जिनको इमोशनली पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हममें से बहुत से आदमी जानते थे और जिनका हरियाणा और पंजाब के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में सभी को व्यक्तिगत ब्यौरा था। उनके लिए स्वाभाविक है कि हमारे दिलों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो। ऐसे सपूत के लिए जिन्होंने हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत र्बड भूमिका निभाई हो और जिनके बाद इतना डेकोरेटिड कोई पालिटिकल आदमी हो भी न सके। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत से सुझाव आये जैसे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने उनके नाम पर एक इंस्टीच्यूट बनाने की बात की, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने पार्लियामैंट में उनका स्टेच्यू लगाने की बात की। मेरे विचार से हम सभी को मिलजुल कर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हमारे आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह जी का स्टेच्यू पार्लियामैंट में लगे और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के सुझाव पर मैं भी पक छोटी सी तरमीम करना चाहता हूं कि वह इंस्टीच्यूट तो बने ही बने लेकिन इमीजेटली जिन लोगों का चरित्र हम यहां पर

देखते हैं ऐसे आदमियां को भी सुधारने के लिए इस विधान सभा में इन्हीं की अध्यक्षता में एक ऐसा क्लब मैंबरज ऑफ दी हाऊस का बनाया जाए जिसमें लोग एक ऐसी निगाह रखकर आनेस्टी के०पर, इंफास्ट्रक्चर क्रिएशन के०पर, मैथडालोजी के०पर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के०पर, इन सारी बातों के०पर हम विधान सभा के अन्दर बैठकर चन्द मैम्बर और बाकियों को एसोसिएटस बनाकर बात करें और उस नीति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी और दूसरी फोरम के माध्यम से अपनी स्टेट में लागू करें ताकि जो हमारा इंफास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हम उसकी हर प्रकार से योग्यता के साथ देखभाल करते हुए उसका बचाव कर सकें। आदरणीय स्पीकर सर, इस दौरान केन्द्र की सरकार ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए, वड़ी मुश्किलों के बावजूद देश की०र्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, न्यूक्लियर पॉलिसी के०पर पूरी तरह से अपने आपको दांव पर लगाते हुए देश के लिए जो कुछ किया उसकी बड़ी सराहना करनी वाजिब है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री रवी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को बहुत–बहुत बधाई देते हैं कि यह जानते हुए भी कि इस फैसले से उनकी सरकार गिर सकती है फिर भी देश की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। इसके लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस दौरान दुनिया भर में मंदी का दौर भी आया और उससे हम भी जूझ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपके बजट में जो दर्शाया गया है कि इस साल 10 हजार करोड़ का बजट होगा जिसको मुख्य मंत्री जी ने, आपकी सरकार ने ज्योमैट्रिकली इम्प्रूव किया है। 2238 करोड़

के बजट से 10 हजार करोड़ पर लेकर आये हैं तो स्वाभाविक है कि जब इतना खर्चा सरकार करेगी तो इस मंदी को कंट्रोल करने में हमारी सरकार कुछ नौकरियां निकालेगी और कुछ न कुछ सहायता होगी तो उस मंदी को हम कहीं न कहीं कंट्रोल कर पायेंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि और फार्मर के कन्सर्न की बात की है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमारी एग्रीकल्चर इप्रूव हो रही है लेकिन दुर्भाग्य से उसमें एग्रीकल्चर विभाग का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। किसान इतना जागृत हो गया है कि वह तरह–तरह की जगह से और जैसा कि श्री सुरजेवाला जी ने कहा कि कहीं एक नैक्सस हो गया है between agriculture officers and those sells spurious drugs, spurious pesticides and spurious Fertilizers. सरकार को चाहिए कि जो जहां कहीं पकड़ा जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्होंने कुछ आकड़े भी दिये थे जिसमें यह देखा गया था कि बहुत ही कम आदमियों को स्पूरियस चीजों के मामले में पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है और हम सब लोग किसान हैं ओर हम जानते हैं कि जब गरीब आदमी विशेषकर जब अपने आढ़ती के माध्यम से फाइनैंस करवा कर चीजें खरीदता है तो उसको सब–स्टैंडर्ड चीजें मिलती हैं। उनके०पर हमें प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। चाहे जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाये, चाहे कोई फ्लाइंग दस्ता बनाया जाये, उनके माध्यम से कोई न कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जो इस प्रकार के ऑफिसर्ज हैं उनको बहुत सख्त सजा दी जाये और अगर उनको सजा दी गई तो मैं

समझता हूं कि किसी प्रकार की धांधली हो नहीं सकती। यह सारा कुछ हमारे अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के इस प्रकार के काम नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, हम एग्रीकल्चर में डाईवर्सिफिकेशन की सदा बात करते हैं लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि व्हीट और पैडी का जो पैकेज है वह बहुत लुक्रेटिव है। हमारी सरकार ने गन्ने के रेट भी बहुत बढाये हैं जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं लेकिन गेहूं और चावल के मुकाबले गन्ने में बचत बहुत कम है। गेहूं और चावल में जहां ग्रोस बचत 50 हजार हैं वहीं गन्ने में 50 हजार है, तो गन्ना कौन लगायेगा। हमारे को–आपरेटिव शूगर मिल हैं जैसे एक और नया करनाल में खुल गया है। इस मामले में हमें हमारे केन डिपार्टमैंट को स्ट्रैथन करना पड़ेगा और अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे शूगर मिल टू द कैपेस्टी चलें तो इन्सैन्टिव देकर गन्ने को भिजवाना पड़ेगा। हालांकि हमारे एक–दो हार मिल्स ने नैशनल लेवल पर इनाम भी जीते हैं लेकिन हम सबको मालूम है कि को–ऑपरेटिव की कुछ मुश्किलें हैं जैसे ओवर स्टाफिंग भी है। अभी हमारे इलाके में गन्ने का बीज बहुत ही कम रह गया है। शूगर मिल बन्द हो गये हैं। अगर हम इस बीज को बहुत अच्छे तरीके से बहुत इन्सैन्टिव तरीके से खेत में नहीं डलवायेंगे तो अगले सीजन में भी गन्ने का उत्पादन कम होगा। इसी प्रकार से पोटैटो की बात है। बहुत से किसान जो प्रोग्रैसिव फार्मर्स हैं आलू की खेती करते हैं। इस बार भी आलू पिट गया। जब आलू पिट गया तो अगले साल वह जमीन भी व्हीट

और पैडी के साईकिल में आ जायेगीं इसको भी हमें कहीं न कहीं कई और फसलों की भी स्पोर्ट प्राईस देनी चाहिए ताकि लोग गेहूं और चावल की खेती की तरफ न भागें। चाहे वह हम स्टेट लेवल पर दें जैसे हमने बहुत साल पहले एक बार हैफेड के माध्यम से आलू की खरीद की थी और विदेश भेजा था। उसी प्रकार से अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो ये लोग जो पोटैटो में गये हुए हैं, पल्सिज में गये हुए हैं, सरसों में गये हुए हैं ये वहां पर टिके रहें इतनी कोशिश सरकार को अवश्य करनी चाहिए। उन तिलहन और इन सारी चीजों को स्पोर्ट प्राईस इस प्रकार की दें कि वे भी गेहूं और चावल के बराबर मुनाफा कमा सकें। स्पीकर सर, सरकार की ओर से किसी प्रकार की न तो फाईनैंस की कमी है न सबसिडीज की कमी है हम जहां पर भी कोई सुझाव देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको मान लेते हैं। जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, उसमें सुधार की जरूरत है चाहे स्प्रिकलर की बात है या पाईपलाईन्ज की बात है इसके बारे में मुझे कुछ पर्सनल– नालेज है। कोई किसान विभाग के अन्दर गया और उसके बाद वह मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि विभाग वाले कहते हैं कि पाईप तो हम खरीद कर देंगे और काम भी हम ही कर के देंगे। उसने मुझे बताया कि बाजार में पाईप बहुत सस्ता मिलता है लेकिन विभाग के लोग बाजार से सस्ता पाईप लेकर काम नहीं करने देते। जब मैंने उनको डांटा तो विभाग के लोगों ने कहा कि अच्छा जी हम बाजार से खरीद कर काम करेंगे। स्पीकर सर, मेरा कहना यह है कि इस प्रकार डिस्क्रीशन उनके पास नहीं होनी चाहिए। जो

भी सबसिडी है जो भी राहत है, चाहे वह पाईप्स पर है, चाहे इम्पलीमैंट्स पर है, चाहे स्प्रिकंलर इरीगेशन पर है उसमें किसान की मर्जी होनी चाहिए कि वह इसे कहां से खरीदे। सरकार की तरफ से किसान को सबसिडी का चौक मिलना चाहिए। इसमें एक और प्रतिक्रिया आ सकती है कि कहीं–कहीं किसान भी बेईमानी कर सकता है उनको चौक करना हमारे सरकारी अधिकारियों का काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। धान की जो पूसा 1121 किस्म है इन्होंने दिल्ली की सरकार से इसके एक्सपोर्ट करवाने के आदेश करवाएं हैं जिसके लिए हम किसान सदा ही इनके ऋणी रहेंगे। इनकी सारी कोशिशों के बावजूद और टैक्स हटवाने के बाद मन्दे का दौर चल गया 3300 से 1600–1400–1200 तक जीरी के भाव आ गये लेकिन वे भाव अभी तक इप्रूव नहीं हुए हैं। इस बारे में जब मैंने इण्डस्ट्रीज से पता किया तो उन्होंने मुझे यह बताया कि साहब अभी हमारी क्रेट्स लोडिड नहीं हुई हैं, हमारी सारी चीज बन्दरगाहों पर पड़ी है। अगर केन्द्र की सरकार से तालमेल करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यह करवा देंगे तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ज्योंही एक्सपोर्ट या कोई वायब्लिटी आएगी उसी से क्रॉप का रेट बढ़ेगा। हालांकि यह भाव पिछले साल से तो अभी भी कम नहीं है लेकिन फिर भी एक बार ज्यादा रेट्स पर बेचने के बाद कम भाव पर बेचना किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदरणीय स्पीकर सर, एक डैट वेवर

की बात है। बहुत से कर्जे सरकार ने मुआफ किये, सूद मुआफ किये लेकिन इसमें एक चीज है कि सारे हरियाणा भर में जो लोग गुड पे मास्टर्ज थे उनको कोई राहत नही मिली। हालांकि बिजली के बिलों में थोड़ा सा इन्सैंटिव उस वक्त पेमैंट्स में दिया गया लेकिन वह काफी नहीं है। जिसने 1997 से अपना बिल पे नहीं किया है उनमें से बहुत से लोग मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जो डिफाल्टरज हैं उनके पास पैसा होते हुए भी वह बिलों की पेमैंट नहीं करते हैं। वह यह सोचते हैं कि कभी न कभी, कहीं न कहीं से बिलों की अदायगी में मुआफी आएगी। अभी जो कॉआपरेटिव बैंकों के लोन्ज हो रहे हैं उनमें कॉआपरेटिव डिपार्टमैंट ने जो गुड पे मास्टर्ज थे उनकी लिमिटस बढ़ा दी हैं उसकी वजह से कुछ पैसा उगया है। जो गुड पे मास्टर्ज थे उनके दिमाग में भी यह बात आ गई कि इसकी पेमैंट तो करनी ही नहीं कहीं न कहीं से मुआफी तो आएगी ही। चन्द लोग ऐसे हैं जो कई–कई बार इस प्रकार की स्कीमों का फायदा उठा चुके हैं। स्पीकर सर, इसी विषय में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पता नहीं कहीं न कहीं छोटी–मोटी गलती हुई है जो देहातों में हमारे छोटे दस्तकार है कॉआपरेटिव बेंकों का जो सूद 7 परसैंट हुआ है वह उन लोगों का नहीं हुआ है और न ही हमारी कैश क्रैडिट लिमिट जो किसानों की है उस पर ब्याज कम हुआ है। आदरणीय मुख्यमन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि इन सारे लोन्ज को ईवन कर दें सात परसैंट कर दें रिवाल्विंग का जो सूद है वह भी जो दस्तकार या छोटे आदमी हैं उनके लिए भी ईवन करने की मेहरबानी करें।

इसके लिए अभी भी ज्यादा सूद चार्ज किया जा रहा है। लिमिट कुछ बढ़ा दी है इसलिए किसान बैंकों के कुछ पैसे दे रहे हैं। स्पीकर सर, किसान पर एक बड़ा भारी जुल्म हो रहा है। किसान कर्ज लेता है उस पर ब्याज पिछली सरकार के समय तो 18 परसैंट होता था लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार ने इसको सात परसैंट कर दिया है लेकिन कॉआपरेटिव में लिकेजिज हैं। किसान को एम०सी०एल० का पांच परसैंट बैंक का या सोसायटी का शेयर खरीदना पड़ता है उस पर उसको कुछ नहीं मिलता है। जिसको हम सात परसैंट कहते हैं वह सूद ज्यादा पड़ता है क्योंकि सात एकड़ वाले का पांच प्रतिशत है सात से ज्यादा वाले का दस प्रतिशत है। नॉन एग्रीकल्चर में भी दस प्रतिशत है। इस प्रकार से 10 प्रतिशत की बजाए 5 प्रतिशत पर उनको एक शेयर खरीदने का हुक्म होना चाहिए ताकि वे कौआपरेटिव सोसायटी के मैम्बर्ज रहें। स्पीकर सर, आप स्वयं कॉओरटिव मिनिस्टर रहे हैं। 'आपको मालूम हैं ये लिंकेज हैं हमारे हरियाणा में कोई इस प्रकार की सोसायटी नहीं है जिसमें वह मुनाफा हुआ है। यह लिंकेज टोटल कैश हैं, यह डैड कैश है जो उसको अपनी तरफ से देना पड़ता है। स्पीकर सर, एक हमने पैक बनाये थे, बहुत से जिलों में वे पैक हाईकोर्ट ने टर्न डाऊन कर दिए हैं, वे वॉयबल नहीं है। मैंने पहले भी विधान सभा में बोला . था कि हमने 40 सालों की मेहनत से कोआप्रेटिव सोसाईटीज को गांव–गांव में पहुंचाया था, हमने इसके माध्यम से खाद, बीज ऋण और दूसरी सारी चीजें गांवों में पहुंचा दी थी। पता नहीं सरकार

की क्या कम्पलशन हुई कि उन्होंने मठ और 7–7 गांवों का कलस्टर बना दिया। अब जो आपकी बिल्डिंग्ज हैं वे गिर जाएंगी जो कि हमने कर्जे लेकर बनाई थी और उससे सरकार के दो पैसे बच जाते थे। आज भी सारे के सारे कर्मचारी वहीं पर बैठे हुए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन अब किसानों को चार कट्टों के लिए 8– 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज देने पड़ते हैं।

स्पीकर सर, अब मैं एनिमल हस्बैंडरी के बारे में कथना चाहूंगा कि हमारे कैथल जिले में मुर्राह ब्रिड को अपनाया गया है। इसके अलावा जींद, रोहतक, शायद झज्जार और दूसरे 4–5 जिलों में भी इस नस्ल को अपनाया गया है और यह नस्ल बहुत ही अच्छी चल रही हे। मैं इस महकमे को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने दो बड़े ही सराहनीय काम किये हैं। एक जो फुट और माऊथ की बीमारी थी वह लगभग–लगभग इरैडिकेट हो गई है। अगर कोई छोटा–मोटा इंसिडैट होता है तो एकदम से टीका लगाकर उसका इलाज कर दिया जाता है। स्पीकर सर, जानवर हमारी इक्नौमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। छोटा किसान जानवर से भी उतनी ही आमदनी करता है जितनी कि एग्रीकल्चर से करता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि हमारे हर गांव में हजारों जानवर हैं और आज एक–एक जानवर की कीमत 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए से लेकर 1.60 लाख रुपए की होती है। अगर जानवर को कोई दिक्कत हो जाती है तो

उसकी मोरटैलिटी को रोकने के लिए डिस्पैंसरी हर गांवों में होनी चाहिए और उनको मैडीकल हैल्प मिलनी चाहिए ताकि वे अपने पशुधन का ठीक से प्रयोग कर सकें।

श्री अध्यक्षः मान साहब, अब आप ककल्यूड करें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, अब मैं फारेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि हम भी आते–जाते देखते हैं कि तरक्की हुई है, सड्कों के किनारे जहां पर भी जगह बची हुई हे वहां पर पेड़ू लगाए गए हैं। आज फेंसिंग का बहुत बढ़िया आइडिया इस सरकार कै बनने के बाद दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से फैंसिंग तो लगा दी गई, जगह–जगह कंक्रीट के पोल लगा कर तार लगा दिए गए हैं लेकिन उनकी मैंटनेस नहीं है। जहां पर पोल गिर गया, वहीं गिर गया। सरकार की तरफ से डी०एफ०ओ० इत्यादि को सख्त हिदायत होनी चाहिए कि यह जो करोड़ों रुपए सरकार ने लगाए हैं, उनको बचा कर रखा जाए। उनकी मैनटेनैंस भी समय–समय पर होती रहनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि बी०पी०एल० फैमलीज के लिए दिये जा रहे फूड और उसकी सप्लाई में बहुत कमियां हैं। उनको जो कैरोसिन ऑयल दिया जाता हे उसमें दो–दो और तीन–तीन लीटर की कटौती कर दी जाती है। यह जो धांधली होती है इसको रोकने के लिए चाहे यहां से टीम या कोई और सिस्टम अपना कर इसको रोका जाए।

इस बारे में मेरे पास कुछ सुझाव भी हैं लेकिन मेरे पास बोलने का समय बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है नहीं तो मैं सदन में बहुत ही अच्छे–अच्छे सुझाव दे देता।

स्पीकर सर, अब मैं इरिगेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इरिगेशन के लिए वहुत सी चीजें बनाई गई हैं। सरकार ने हमारे इलाके में बहुत से रजवाहे बनाए हैं। बी०एम०एल० भी मेरे हल्के से होकर जाती है और जी थैप्ट ऑफ वाटर हायर रीचिज में है, वह काबू में नहीं आ रही है। यह जो थैप्ट आफ वाटर पिछली सरकार के समय पर होती थी और उस समय में जिन लोगों के मुंह मे खून लग गया था, आज भी वे लोग बाज नहीं आ रहे हैं। स्पीकर सर, इस चोरी को सरकार द्वारा गार्ड लगाकर रोका जाना चाहिए। पुलिस इसमें मदद देती नहों है। आज टैलीफोन और मोबाईल का जमाना है। अगर उस बारे में कम्पलेंट भी की जाती है और टीम वहां पर जाती है तो उनके पहुंचने से पहले ही हमारे ही बेलदार उन आदमी को टैलीफोन करके बता देते हैं कि टीम आ रही है भाग जाओ यहां से। जब तक पानी टेल पर पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा तब तक काम नहीं चलेगा। रात को भी जब हम रजवाहे पर जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त पाईप उठ जाती हैं इसलिए इसका प्रबन्ध करना भी बहुत जरूरी है ताकि हर आदमी को अपने हिस्से का पानी मिल सके। स्पीकर साहब, बाकी कई और भी इरीगेशन के काम इस सरकार ने किए हैं जोकि बहुत सराहनीय हैं। दादुपुर नलवी नहर बन रही हैं हम

तो भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी यह नहर बन जाए। स्पीकर साहब, पहले भी इसमें ये लोकदल वाले ही अड़चन डालते थे। हमारे हल्के के अंदर जितनी भी इस बारे में लिटीगेशज हैं वह इन लोकदल के वर्कर्ज के द्वारा ही हैं। इसी प्रकार से हांसी–बुटाना लिंक कैनाल के बारे में भी इन लोगों ने ऐसा ही किया है। पहले ये लोअर कोर्ट में गए और फिर हाईकोर्ट में गए। सारी जगह से हारने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने प्रकाश सिंह बादल की सहायता लेकर इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझा दिया है ताकि इनकी साईड का पानी हमारी साईड में न आ जाए। मेरी सरकार से दरखास्त है कि सरकार ने जो यह सराहनीय कार्य कई जिलों के लिए शुरू किया है इसको पूरा जोर लगाकर कम्पलीट करवाया जाए और पानी पंचर करने का प्रावधान करवाया जाए ताकि सब लोग इस भमि। का यूज कर सकें। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने मांगे राम गुप्ता जी से एक सवाल के जवाब में सारा मैटीरियल ले लिया है। मेरी यही दरखास्त है कि जो गांवों के आदमी बस सर्विस से महरूम रह जाते हैं उनके लिए सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। टूरिज्म में सब ठीक है यह हमारा सब्जैक्ट नहीं है लेकिन अच्छी बात है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले।

श्री अध्यक्षः मान साहब, क्या आपने बोलने के लिए लिख रखा है या गवर्नर ऐड्रैस को देखकर बोल रहे हैं?

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः सर, मैं तो गवर्नर ऐड्रैस को देखकर ही अपने हिसाब से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, मान साहब, अब आप बैठें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः सर, आप मुझे पांच मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः मान साहब, आपको बोलते हुए बीस मिनट हो गए हैं इसलिए अब आप बैठें। अब मक्कड साहब बोलेंगे।

श्री अमीर चन्द भक्कड (हांसी): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने विधान सभा में जो अपना गवर्नर ऐड्रैस दिया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरियाणा सरकार जो विकास कार्य हरियाणा में कर रही है वह हरियाणा को एक नम्बर पर लाने के लिए आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू करवा रखे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जिन कार्यों के लिए ऐलान कर रखा है उनके लिए वे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में चाहे वह ऐजुकेशन का हो, चाहे रोड्ज का हो, चाहे गरीब बच्चों की पढ़ाई का हो या चाहे विकास कार्य हो, वे उनको पूरा करवाकर उन शहीदों को और उन देशभक्तों के स्वप्नों कौ साकार करने में लगे हैं जो उन्होंने देखे थे इसलिए इनकी जितनी तारीफ की जाए वह थोड़ी है। बहुत ही अच्छे काम उन्होंने हरियाणा में शुरू कर रखे हैं। आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा का इतना विकास नहीं किया है जितना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करने लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि आदरणीय

चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो इनके पिता जी भी थे और एक फ्रीडम फाईटर भी थे तथा वे पूरी तरह से देशभक्त भी थे, उनके स्वप्नो को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पूरा करने में लगे हुए हैं। चौधरी रणबीर सिंह जी की मिसाल कहीं नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने 15 साल की आयु में ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वे सबके लिए एक मिसाल थे। अपने जीवन में जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की वहीं उन्होंने देश के लिए भी बहुत काम किए और साथ ही उन्होंने अलग हरियाणा को बनाने की डिमांड भी उस समय रखी थी जो बाद में आकर पूरी हुई इसलिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह थोड़ी है। आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी उन देश भक्तों के स्वप्नों को साकार करने में लगे हुए हैं जोकि बहुत ही काबिलेतारीफ बात है। मैं समझता हूं कि मेरे हल्के में विकास कार्यों के अब थोड़े बहुत ही काम रह रहे हैं। स्पीकर साहब, ऐजुकेशन की तरफ भी हुड्डा साहब ने बहुत ध्यान दिया है। हर गरीब बच्चे की तरफ उन्होंने ध्यान दिया हैं पहले ये गरीब बच्चे या तो सड्कों पर भीख मांगते फिरते थे या फिर कहीं जाकर चोरी बगैरा करते–फिरते रहते थे लेकिन आज उनको शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। पहले गरीब बच्चे, हरिजन के बच्चे और बैकवर्ड क्लास के बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं जाते थे लेकिन अब हमारी सरकार वजीफा देकर, फीस माफ करके और हर किस्म से दूसरे प्रोत्साहन देकर उनको स्कूलों में जाने के लिए प्रेरित कर रही है जोकि बहुत ही काबिले तारीफ है। अब हरियाणा के गरीब बच्चे पढ़कर आगे जाकर अपना

रोजगार कर सकेंगे। स्पीकर साहब, आई०टी०आई० का भी अब विस्तार किया जा रहा है ताकि हर बच्चा टैक्नीकल शिक्षा लेकर अपना रोजगार कर सके। सरकारी नौकरियां इतनी नही है कि सबको दी जा सकें। लेकिन जो बच्चे अपना रोजगार चलाने के लिए काबिल हो जाएंगे उनको नौकरियों की जरूरत नहीं रहती, यही नही वह दूसरे बच्चों को भी नौकरी पर लगा सकते हैं। हरियाणा सरकार टैक्नीकल ऐजुकेशन और आई०टी०आई० का बहुत विस्तार कर रही है। सरकार के इस प्रयास की भी मैं बहुत तारीफ करता हूं। जहां तक सड्कों का सवाल है। सड्कों का जाल बिछाया जा रहा है। जी०टी० रोड छह मार्गीय और चार मार्गीय बनाए जा रहे हैं। दिल्ली से रोहतक और रोहतक से हिसार तक मी राजमार्ग बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। मेरे हल्के की भी कुछ सड़कें बननी जरूरी हैं। पिछली सरकार के समय में ढाणी से जमौडी तक की सड़क बनाने के वारे में वहां के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी और इस डिमांड के बारे में चौटाला साहब से मिले थे और उन्होंने इन दोनों सड्कों को बनवाने से इंकार कर दिया था, कहा था कि इन दोनों गांवों के लोग लोकदल के खिलाफ हैं। यहां– तक कि वे उस गांव के लोगों से मिलते भी नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के लोगों की यह मांग है और मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी भी वहां गए थे और इन्होंने घोषणा की थी कि यह सड़क जरूर बनाई जाएगी। पहले जमीन की कमी थी अब वहां गांव के लोगों ने जमीन देना भी स्वीकार कर लिया है। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना हैं कि

ढाणी से जमौडी, लालपुरा से ढाणी कुतुबपुर कुलाणा तक की जो सड़कें है इनको बनाना लोगों की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है। उन सड्कों को इलैक्शन से पहले–पहले बनाने की पूरी कार्यवाही कराएं ताकि लोगों की असुविधा को सुविधा में बदला जा सके। इसी तरह से पेयजल के बारे में कहना चाहूंगा कि हर गांव में 40 से लेकर 70 लीटर तक प्रति व्यक्ति को पानी मुहैया करवाया जा रहा है लेकिन मेरे हांसी हल्के के कई गांवों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी भी नहीं मिल पार रहा है। इसके लिए मैंने पहले भी सरकार के समक्ष आपके माध्यम से डिमांड रखी थी। मेरे हल्के की ढाणियों में ढाणी पिराली, ढाणी मैहदा, ढाणी खबपुर, राजू ढाणी, ढाणी ठाकरी, ढाणी गुजरान में बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन ढाणियों में कम से कम एक वाटर वर्क्स होना बहुत ही जरूरी है। ताकि उन ढाणियों के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। जमीन के नीचे पानी खारा है इसलिए भी वाटर वर्क्स बहुत जरूरी है। जैसे सरकार जगह–जगह पर वाटर वर्क्स बना रही है वैसे ही मेरे हल्के की इन ढाणियों में भी पानी के लिए ठीक जमीन ऐक्वायर करके वहां वाटर वर्क्स बनवाने का काम करें ताकि वहां के लोगों को पीने का साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। सभी जानते हैं कि हांसी शहर एक ऐतिहासिक शहर है और वहां की लाल सड़क वहां के देश भक्तों की कहानी कहती है। हांसी के लोगों ने 1957 की आजादी की लड़ाई में वहां के देशभक्तों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों ने उन देशभक्तों को वहां की उस सड़क पर लिटाकर उन पर गिरडी चला

दी थी और वह सड़क उन देशभक्तों के खून से रंग गई थी इसलिए वह लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। हांसी शहर में मी पेयजल की काफी कमी है। यहां तक कि खेतों में भी पानी नहीं मिलता है कई दफा मैंने इस बारे में डिमांड भी की है। सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से दूसरे वाटर वर्क्स की स्कीम चला रखी है। मेरी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी उस स्कीम को चलाकर पेयजल की कमी को पूरा किया जाए। नल्के लगाते हैं तो खारा पानी आ जाता है कुंए भी नहीं खोदे जा सकते हैं इसलिए वाटर वर्क्स शीघ्र बनाए जाएं। स्वच्छ पानी देने का और कोई तरीका नहीं है। हांसी में सीवर की भी काफी समस्या है। 40 साल पुराने सीवर कै पाइप डले हुए हैं। छोटे से पाइप पड़े हुए हैं तब आवश्यकता भी काफी कम थी। आबादी तब से अब तक दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। हालात ये हैं कि बारिश की दो बूंद पड़ते ही सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं और परिणामस्वरूप लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी भर जाता है क्योंकि सीवरेज का डिस्पोजल बहुत ही छोटा है और लोग बहुत परेशान होते हैं। इसके बारे मैं भी सरकार ने वर्ल्ड बैंक को स्कीम दी हुई है। मेरी प्रार्थना है कि इस स्कीम को जल्दी चालू करें। मैंने पहले भी कई दफा प्रार्थना की है कि सीवरेज के लिए पैसा दिया जाए। लोगों के घरों में सीवरेज डालने का कार्य किया जाए। यह सराहनीय कार्य हुड्डा साहव कर रहे हैं आज सारी जनता हरियाणा में यही आवाज लगा रही है कि हुड्डा साहब बहुत अच्छे कार्य कर रहे है आगे भी हुड्डा साहब को ही राज दिया

जाए लोग यहीं चाहते हैं लेकिन अफसरशाही जो चल रही हें। मैं समझता हूं कि इसके साथ–साथ अगर अफसरशाही पर भी कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगर अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं होगा तो जो सराहनीय कार्य हुड्डा साहब कर रहे हैं वे ठीक ढंग से नहीं होंगे। सिंचाई मंत्री शायद सदन में बैठे नहीं हैं। मैं इसका भुगतभोगी हूं मीटिंग में भी इस बात को रखा था कि मेरे खेत में अफसरों ने इतना घटिया खाला बनवाया है कि पानी खेत में लगता ही नहीं। इस बारे में मैंने साहब को शिकायत भी लिखकर दी और इस बारे में सी०एम० साहब को भी कहा था कि ये अफसर हें जिनको दस बार फोन करने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। जब सी०एम० साहब को कहा तब जाकर उस खाले पर पलस्तर लगाया जा रहा है लेकिन पलस्तर कोई काम का नहीं जब तक उसकी बुनियाद ठीक तरह से न हो। मेरी प्रार्थना हे कि देप्पल माईनर 14600 नम्बर खाल को दोबारा पक्का किया जाए ताकि हमेशा के लिए ठीक चल सके नहीं तो यह पानी बिलकुल सही नहीं चलेगा।

17.00 बजे

श्री अध्यक्षः मक्कड साहब, आप कंकल्यूड कीजिए।

श्री अमीर चन्द मक्कडः स्पीकर साहब, जहां तक एजुकेशन का मामला है मेरे हल्के के गांव पीरवाली ढाणी में वहां की पंचायत ने अपने खर्चे से 15– 16 कमरे बना दिए हैं इसलिए

वहां के स्कूल को मिडिल से हाई स्कूल तक अपग्रेड कर दिया जाए। (इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य आई०जी० शेर सिंह पदासीन हुए) सीसर गांव ने भी कमरे बना दिए हैं उनकी डिमाण्ड है कि प्राईमरी स्कूल को 10 जमा दो के स्कूल में अपग्रेड किया जाए और ढाणी कुतुतबपुर में जो मिडिल स्कूल है उसको भी हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। पहले हांसी के लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए भिवानी और हिसार जाया करते थे लेकिन हुड्डा साहब ने हांसी में कालेज बना दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से हांसी की आई०टी०आई० का विस्तार किया गया। इसी प्रकार मेरी एक डिमाण्ड हैं कि उमरा गांव में जो खेल नर्सरी बनाई हुई है वहां पर 25 बच्चों की मंजूरी है लेकिन वहां पर कमरे नहीं हैं मैं और छत्रपाल जी कल वहां पर गये थे। वहां पर चार कमरे और बना दिए जाएं ताकि वहां पर बच्चे ठीक ढंग से अपनी प्रैक्टिस कर सकें और उनको प्रोत्साहन मिल सके।

श्री सभापतिः मक्कड साहब, आप जल्दी कन्कल्यूड कीजिए।

श्री अमीर चन्द मक्कडः स्पीकर साहब, जहां तक रेलवे पुलों के विस्तार की बात है हुड्डा साहब ने 16 से बढ़ाकर 33 से ज्यादा रेलवे पुलों का विस्तार किया है। हांसी से उमरा रोड पर जो रेलवे फाटक है उस पर भी एक रेलवे पुल बनाया जाए क्योंकि वहां पर लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इसी प्रकार से रोहतक से हिसार जाने वाली रेलवे लाईन का प्रावधान चल रहा है अगर वह रेलवे लाईन जल्दी बन जाये तो उस इलाके के लोगों को दिल्ली जाने में काफी सहूलियत हो जायेगी क्योंकि उनको अब दिल्ली के लिए रेवाड़ी होकर जाना पड़ता है।

श्री सभापतिः मक्कड साहब, आप जल्दी कंकल्यूड कीजिए।

श्री अमीर चन्द मक्कडः आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़): सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियों को, सरकार के एक साल में किए गएँ कार्यों को और भविष्य में किस तरफ सरकार प्रदेश को ले जाना चाहती है इसको दर्शाता है लेकिन बड़े खेद से कहना पड़ता है कि इस अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश मे सबसे पहले कानून और व्यवस्था देखी जाती है। जिस प्रदेश की कानून और व्यवस्था ठीक न हो वहां चाहे उद्योगपति हों, आम नागरिक हों, माताएं और बहनें हों, सबके लिए परेशानी का सबब होता है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश की कानून और व्यवस्था को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आखिर में लिया गया है जबकि

यह चीज अभिभाषण के पहले पेज पर होनी चाहिए थी। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था सबसे लचर अवस्था में है। आज हर रोज मर्डर, चोरी और डकैती आम बातें हो गई हैं लेकिन सरकार को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे गांव इस्माइला में एक 8 साल का बच्चा जब स्कूल से घर की तरफ लौट रहा था तो उसको आवा कर लिया गया। पुलिस को उसी समय सूचना दी गई, व्यक्ति का नाम बताया गया और वह व्यक्ति अरैस्ट हो गया। वह व्यक्ति 3 दिन तक अरैस्ट रहा। एस०एच०ओ० दहिया ने बीच में डेढ़ लाख रुपये खाकर उस बच्चे की डैड बॉडी को खराब करने की कोशिश की।

श्री सभापतिः आपके पास क्या प्रूफ हैं कि उसने डेढ़ लाख रुपये खाए?

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, सरकार ने उसको सस्पैड किया है। मैंने यह बात मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखी। उसी दिन केस सी०आई०ए० के पास गया। दोपहर को डैड बॉडी मिल गई। पता नहीं 3 दिन तक वह उस की मेहमान नवाजी करता रहा। वह एस०एच०ओ० अब नौकरी में आ गया है। सभापति महोदय, क्या ऐसे अधिकारियों को पुलिस फोर्स में रहने की इजाजत है। सभापति महोदय, इसी तरह इस्माइला गांव में एक आदमी ताश खेल रहा था उसको सरेआम कोई गोली मार कर भाग गया।

श्री सभापतिः मलिक जी, यह व्यक्तिगत एनिमिटी में हुआ होगा।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, एक आदमी मर्डर करके चला जाता है लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसके बाद वही बदमाश उसके खेत में जाता है और उसके दूसरे भाई का मर्डर कर देता है! सभापति महोदय, अभी सांघी गांव में जो कि मुख्यमंत्री महोदय का गांव है, वहां कुछ यू०पी० के बदमाश आए और वे जिसको मारने आए थे उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने एक मिनट पहले कुर्सी चेंज की थी और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था तथा जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा था उसको गोलियों से भूनकर चले गए। गांव वालों की मदद से वे बदमाश पकड़े गए। इसी तरह खाफ के गांव में कोई मोटर साईकिल पर जा रहा था, दो आदमी आए और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। सभापति महोदय, इसी तरह से सब कुछ कारौर गांव में भी घटित हो रहा है। वहां ऐसा हो रहा है जैसा कभी अंग्रेजों के समय में भी नहीं देखा गया होगा। जैसा वहां पर आज हो रहा है ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता होगा। कारौर गांव में पांच भाई हैं और पै ही गांव में यह तय करते हैं कि कौन मैम्बर बनेगा। पिछली बार जब पंचायतों के आम चुनाव हुए तो उन्होंने पूरे गांव को इक्ट्ठा करके यह फरमान जारी कर दिया कि ये आदमी हमारे मैम्बर होंगे और हम सरपंच बनेंगे। किसी दूसरे ने चुनाव में खड़ा होन की कोशिश की तो उसे गोलियों से उड़ा

देंगे। सभापति महोदय, मैंने दो–ढाई साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी कि अगर रोहतक में कहीं पर सबसे बड़ी बदमाशी है तो वह कारौर गांव के अन्दर है। उनकी बदमाशी से पूरा गांव सन्न है। वह गांव पूरे तौर पर बदमाशों का अड्डा बना हुआ है। मेरी रिक्वैस्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कार्यवाही करवाई जिसमें वहां से नाजायज असला भी मिला। वहां से कुछ बैड एलीमैंटस भी मिले जो कि बाद में भाग गये। उसके बाद छ मर्डर के केसिज उन पांचों भाइयों पर चल रहे हैं। सभापति महोदय, एक नहीं, दो नहीं आठ–आठ मर्डर के केसिज उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं। उन पर आठ–आठ मर्डर के केसिज चलने के बावजूद भी उनकी धर्मपत्नियों के नाम तीन आर्म लाईसैंस बनाये गये हैं। इतना ही नहीं तीन आर्मज लाईसैंस देने के बावजूद भी उनको सरकार की तरफ से एक गनर भी दिया गया है। सभापति महोदय, दीपावली के दिन उन सभी भाइयों ने पिस्टलें लेकर कारौर गांव के अन्दर हिंसा और अपराध का नंगा नाच खेलते हुए मेरी कई माताओं और बहनों को गोलियों से भून डाला जिनमें से दे'। ने तो मौके पर दम तोड़ दिया और एक हास्पिटल में पड़ी रही। पूरे गांव में उनकी इतनी दहशत है कि गांव में से कोई भी आदमी जख्मी का हालचाल पूछने और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में नहीं पहुंचा। मैंने अगले दिन वहां पर पहुंचकर उनका पोस्टमार्टम करवाया और मृतकों का संस्कार करवाया। गांव का एक भी आदमी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। सभापति महोदय, इस प्रकार से छ मर्डर करने वाले

आदमियों को आर्मज लाईसैंस जिन अधिकारियों ने दिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभापति महोदय, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सरकारी गनर किसने दिये। यह जांच का विषय है। सभापति महोदय, जो गनर था वह भी दीपावली के दिन अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं था और अपनी स्टेनगन छोड्कर चला गया था। ऐसे बदमाशों के पास सरकारी स्टेनगन रहने की सूरत में वे पूरे के पूरे गांव को गोलियों से भून सकते थे। जो लोग पूरे गांव के अन्दर सरेआम तीन मर्डर कर सकते हैं। अगर उनके पास उस समय स्टेनगन होती तो वे पता नहीं कितनों को मार सकते थे। इस घटना के बाद संबंधित सिपाही को महज सस्पैंड किया गया। इसके अलावा उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभापति महोदय, मैं इस प्रकार की कितनी वारदातें गिनाऊ। अगर मैं सभी वारदातों के बारे में गिनाना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कि आपका समय हो गया है। इतनी लम्बी लिस्ट है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कारौर गांव के अन्दर जिन लोगों की अथारिटी से आर्म लाईसैंस बनाये गये हैं अब तक उन अधिकारियों के खिलाफ टर्मिनेशन की कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जो सिपाही मौके से अपनी स्टेनगन छोडगर भाग गया उसके खिलाफ सख्त अनुशसनिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

श्री सभापतिः नरेश जी, आप कोई और बात कीजिए Your statement has already been recorded. Whatever you have said वह रिकार्ड हो गया है।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, ऐसा तो कभी अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। केवल मात्र पांच लोगों ने पूरे गाँव को बंधक बना रखा है। कोई अपने खेत में नहीं जा सकता। अगर कोई खेत में जाता है तो उसको जबरदस्ती कहा जाता है कि हमारे खेतों को जोतकर आओ। उस गांव के अन्दर ऐसी शोचनीय स्थिति है। मैंने दो साल पहले इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी थी और मेरे कहने पर वहां पर उनके घर में रेड भी डाली गई थी। ऐसे आदमियों को जो अधिकारी सुविधायें देते हैं वे उनसे मिले हुए हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को ऐसे लोगों की तरफ से पैसे मिलते हैं।

Mr. Chairperson : Who gives to them? You have to give a proof so that such people can be charge-sheeted.

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, उन लोगों ने 9 मर्डर कर दिये उनकी चार्ज–शीट क्या मैं दाखिल करूंगा? उन्होंने तीन मर्डर और कर दिये उसके भी गवाह हें और भी सभी प्रूफ हैं। क्या इसको भी मैं ही जस्टीफाई करूंगा? क्या इसका प्रूफ भी मुझे ही देना होगा। जो पुलिस वाला गनर अपनी स्टेनगन छोड्कर भाग गया और जिसको इसके लिए सस्पैंड किया गया क्या ये सभी प्रूफ नहीं हैं?

श्री सभापतिः नरेश जी, यह बात हो चुकीं है, you may kindly proceed further. उसकी विटनैस वगैरह का काम यहां पर डिसाईड नहीं होगा।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, आप इसको इतनी छोटी बात कह रहे हैं। एक गांव में आज भी अंग्रेजों से भी बुरे हालात हैं आप उसको छोटी बात कहते हैं।

श्री सभापतिः नहीं छोटी बात नहीं है, आपने ठीक बतलाया आपने जो रैफ्रैंसिज दिये हैं ठीक हैं और उनकी विटनैसिज वगैरह के मुताबिक कोर्ट अपने आप कार्यवाही करेगी। आगे और कोई बात करो या और कोई सुझाव दीजिए।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, कोर्ट अगर करती तो एक आदमी 8–8 मर्डर कर दे और उसको फिर गनर दे दिया। आदमी ने 8–8 मर्डर कर रखे हों उसकी धर्मपत्नी का लाईसेस कैसे बन गया? उनकी 3 पत्नियों के लाईसैंस बन गये और उन्हीं लाईसैंसी हथियारों से जो एक नम्बर के लाईसैंस हैं, सरेआम जा कर दो औरतों को मार दिया गया और एक गम्भीर रूप से घायल है। सभापति महोदय, और भी ऐसी न जाने कितनी घटनायें हैं कहीं पर चेन छीन ली, कहीं पर मोबाईल छीन लिया और भी दुनिया भर की मर्डरों की लिस्ट है जिनके बारे में अगर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि आपका समय समाप्त हो गया है। सभापति महोदय, मेरा कहने का. तात्पर्य यह है कि जिस

प्रदेश में अमन–चौन नहीं है वह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी बात सभापति महोदय, बार–बार एस०वाई०एल० का जिक्र आता है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि किसी भी पार्टी को एस०वाई०एल० का फायदा मिलने वाला नहीं है। आज हर कोई दल इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहता है लेकिन मैं इस मुद्दे पर इतना जरूर कहना चाहूंगा वि) यह मुद्दा न तो कोर्ट के विचाराधीन होना चाहिए था और न ही किसी और के अधीन होना चाहिए था। सभापति महोदय, मुझे आज भी याद है कि जब हमारी एन०डी०ए० की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर ने जिस तरह से पंजाब ने कानून पास किया था, इसी प्रकार से कानून पास किया था कि जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत्ता मिलनी चाहिए। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तुरन्त कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अगर कांग्रेस की सरकार भी इसी ईमानदारी से काम करती तो बजाय वह राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीमकोर्ट में जाने के प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उस फैसले को निरस्त कर सकते थे क्योंकि कैबिनेट को इस प्रकार के अख्तियारात होते हैं।

Mr. Chairman : The Parliament will decide this issue. Kindly go ahead with the other issue.

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, जिस प्रकार हर बजट में बार–बार इस मुद्दे को रिपीट किया जाता है उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि यह मामला सुलझे।

अगर प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को सुलझाना चाहते तो यह उनका एक मिनट का काम था। सभापति महोदय, सी०ए०जी० की रिपोर्ट आई है। आज सारे अखबार भरे पड़े हैं कि बिजली की खरीद में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सी०ए०जी० की रिपोर्ट में लगभग 101 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया है। सी०ए०जी० की रिपोर्ट कोई इंडिविज्युल दस्तावेज नहीं है यह एक सरकारी दस्तावेज होता है। जब 2 रुपये 40 पैसे से 3 रुपये 54 पैसे तक बिजली मिल रही थी। उस समय 7 रुपये 28 पैसे के हिसाब से बिजली की खरीद की गई। इस प्रकार से सैंकड़ों करोड़ रुपये का यह घोटाला उजागर होता है। सभापति महोदय, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ कहा जाता है। यह भी सी०ए०वी० की रिपोर्ट में कहा गया है कि किस प्रकार रोजगार गारन्टी योजना में सिरसा और हिसार में झूठे बिल, दो–दो आदमियों से पैसे लिए गये, बड़े भारी घपले हुए हैं यह बिल्कुल क्लीयर दिया गया है। उसमें बड़ी भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। सभापति महोदय, हरियाणा की जेलों का भी बहुत बुरा हाल है। सोनीपत की जेल में जब अधिकारियों ने रेड मारी तो 8– 10 अपराधी वहां से गायब मिले। जब पुलिस अधिकारियों ने वहां पर छापा मारा तो जो विचाराधीन कैदी थे या जिनको उम्रकैद की सजा हुई थी वे आदमी वहां पर नहीं मिले। वे आदमी किसी का मर्डर करने गये हुए थे, उन्होंने सुपारी ली हुई थी।

श्री सभापतिः मलिक साहब, आप 15 मिनट बोल चुके हैं। अब आप वाइंड अप कीजिए।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों के बजट के बारे में इस अभिभाषण में लिखा है कि लगभग 120 करोड़ रुपये 75 नगरपालिकाओं को दिये गये हैं जबकि 28 प्रतिशत हमारी आबादी शहरों में रहती है। आज शहरों की हालत बद से बदतर है इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह राशि तीन गुणा होनी चाहिए। (विघ्न) मैं सरकार से यह चाहूंगा कि इस पर विचार होना चाहिए।

श्री सभापतिः तीन गुणा के बारे में आप क्या कह रहे हैं?

श्री नरेश मलिकः चेयरमैन सर, 120 करोड़ रुपये की राशि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए रखी है जिसका जिवय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है। प्रदेश की 28 परसैंट जनता शहरों में रहती है। नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस बजट को भी बढ़ाया जाए। चौयरमेन सर, वर्ष 2010 में कॉमन वेल्थ गेम्ज दिल्ली के अन्दर होने हैं। हरियाणा प्रदेश की यह खुशकिस्मती है कि दिल्ली के साथ तीन तरफ से एन०सीआार० का लगता एरिया हरियाणा का है चाहे वह सोनीपत हो, रोहतक हो, बादली हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो।

एन०सी०आर० के लिए बजट सरप्लस है विकास के प्रोजैक्ट्स बना कर चाहे जितना पैसा ले जाओ। सरकार ने कहा है कि कॉमन वैल्थ गेम्ज के समय हम 6500 कमरे बना कर देंगे। अगर चारों पांचों जिलों का एक अच्छा सा प्रोजैक्ट बना कर सरकार ने दिया होता तो उसका फायदा हरियाणा स्टेट को मिलता। मैं कहता हूं कि एन०सी० आर० के बजट में हर साल सैंट्रल गवर्नमैंट का पैसा लैप्स होता है यदि कोई अच्छा प्रोजैक्ट सरकार ने बनाया होता तो उसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट से पैसा मिल सक्ता था। यहां पर भी मैं सरकार की एक बड़ी विफलता मानता हूँ। सभापति महोदय, अभी रोडवेज के कर्मचारियों की भर्ती के लिए ड्राईवर्ज तथा कण्डक्टर्ज के शायद इन्दव्यू वगैरह चल रहे थे। शायद परिवहन मंत्री जी डेली वेजिज पर कुछ कर्मचारी ले रहे हैं।

श्री सभापतिः मलिक साहब, कोई इन्टरव्यू नहीं हुआ है अभी तो सिर्फ ड्राईविंग टैस्ट हुआ है।

श्री नरेश मलिकः चेयरमैन सर, पीछे वित्तमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास पैसा तो इतना है लेकिन काम करने के लिए ठेकेदार उपलब्ध नहीं हैं। ठेकेदार तो उपलब्ध हैं लेकिन लिमिटिड ठेकेदार हैं। अब अपने चहेतों को दोनों हाथों से लूटने की इजाजत दी जा रही है। इसका मैं एक उदाहरण ही नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। (विघन)

श्री सभापतिः मलिक साहब, यहां तो ओपन टैंडर का सिस्टम है anybody can apply for it.

श्री नरेश मलिकः जो इनके चहेते हैं टैंडर उन्हीं को देते हैं और उन्हीं के रूल्ज चलते हैं। (विघ्न) चेयरमैन सर, अब मैं सड्कों का जिक्र करूंगा। मैं मानता हूं कि बजट में काफी वृद्धि की गई है लगभग सवा दो गुणा से ज्यादा बजट बढ़ाया गया है लेकिन आज स्थिति यह है कि राजधानी क्षेत्र से बहादुरगढ़ को निकलो और जब हिसार सिरसा की तरफ जाओगे तो मेरे विचार से सड़क की हालत ऐसी है कि आप गाड़ी में टॉप गियर नहीं लगा सकते हैं (विघ्न)। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं।

श्री सभापतिः मलिक साहब, आप यह बताएं कि सड्कों पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है?

श्री नरेश मलिकः चेयरमैन सर, सिक्स लेन हाईवे कितने बड़े–बड़े प्रोजेक्टस थे। प्रधान मंत्री सड़क योजना प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन थी। आज भी पूरे देश में वही प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बीच में एक साल यह कार्यक्रम रोक कर भी देखा लेकिन उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। सभापति महोदय, अभी जैसे कि मन्दी का दौर चल रहा है। तीन दिन पहले टी०वी० में एक बहुत ही बड़ा सर्वेक्षण और आकलन भी आया कि पूरे विश्व के अन्दर लगभग पांच करोड़

और हिन्दुस्तान के अन्दर लगभग एक करोड़ नौजवान साथी बेरोजगारी की चपेट में आएंगे लेकिन केन्द्र की सरकार ने इस बात से यह कहते हुए पल्ला झाड लिया कि छः महीने का आधा वेतन देकर प्राईवेट कम्पनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सोच नहीं हे।

श्री सभापतिः मलिक साहब, हरियाणा में तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नरेश मलिकः चेयरमैन साहब, मैं हरियाणा के बारे में भी बता देता हूं। गुड़गांव तो हरियाणा में आता है।

श्री सभापतिः मलिक साहब, (मापको बोलते हुए बीस मिनट हो गए हैं इसलिए अब आप वाइंड अप करिये।

श्री नरेश मलिकः चेयरमैन सर, यह तो कोई बात नहीं हैं विपक्ष के सदस्य को बोलने को लिए आप थोड़ा ज्यादा समय देने की मेहरबानी करें। (विघन) अब मैं हरियाणा के गुड़गांव की बात भी बता देता हूं कि गुड़गांव के 26 साल के एक नवयुवक ने नौकरी चले जाने पर अपने आप को शूट कर लिया (विघन)। यह कोई गलत बात नहीं है यह कोई इम्पोसिबल बात नहीं है। चेयरमैन सार, टी०वी० में न्यूज आई थी उसके पूरे विवरण आए हैं। 26 साल के नौजवान साथी ने केवल नौकरी जाने से अपनी मां की पिस्तौल से गाड़ी में बैठकर अपनी कनपट्टी पर गोली।

मार ली थी। यह मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। यह आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। (विघन) सभापति महोदय, यह कदम मजबूरी में ही कोई उठाता है। (विघन) आज किसान मजबूरी में खुदकुशी कर रहा है। देश में अब तक 18 से 20 हजार के करीब किसान खुदकुशी कर चुके हैं। यह कोई मर्जी से नहीं कर रहा है। उनके हालात ऐसे बन जावे हैं कि उनको खुदकुशी करनी पड़ती है।

श्री सभापतिः मलिक जी, आपको बोलते हुए काफी समय दी गया है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री नरेश मलिकः चेयरमैन सर, मेरे से पहले बोलते हुए भी टमाटर की फसलों के बारे में कहा गया है। टमाटर की फसल किसानों ने बहुत ही मेहनत से लगाई थी। जब उनकी फसल तैयार हो गई और उसको बेचने का समय आया तो उसका रेट एक रुपए किलो के हिसाब से भी उनको नहीं मिला है। उन्होंने क्या–क्या सोच कर टमाटर की फसल को बोया था आप उनकी छाती पर हाथ लगा कर देखें कि उनके साथ क्या बीती है। उनकी इस बारे में क्या–क्या सोच थी? उनकी सोच उनकी फसल के तैयार होने के साथ ही मर गई। एन०डी०टी०वी० पर उनके टमाटरों की फसल को गायों को खाते हुए दिखाया गया था।

श्री सभापतिः मलिक जी, आप कन्कल्यूड करें। दूसरे मैम्बर्ज ने भी बोलना है आपको बोलते हुए 20–25 मिनट हो गए हैं।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, जो नॉन एग्रीकल्चर कर्जदार हैं वे 1 लाख 6 हजार 17 हैं। उनके लिए 1990 से स्कीम चल रही है और इन जमींदारों को कर्जों पर सरकार ने 44.42 करोड़ रुपए की रियायत दी है। सरकार ने उनको वही रियायत दी होगी जो कानून के मुताबिक होगी। इसके अलावा बी०पी०एल० 8 लाख 52 हजार परिवार इस हरियाणा प्रदेश में हैं और 1 लाख 6 हजार आदमियों को सहायता दी गई है। मैं नहीं मानता हूं कि यह अधिक सहायता है मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इनकी तरफ से जो 10– 15 साल पुराने कर्जे हैं, उनको समाप्त किया जाए और नए सिरे से कर्जे दिए जाएं।

श्री सभापतिः मलिक जी, आप कन्कल्यूड करें। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, सहकारी समितियां और मोर्टगेज बैक्स से छोटे किसानों को सहायता देने के लिए इस अभिभाषण में कोई पॉलिसी नहीं है। इस बारे में सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि उनके लिए कोई पालिसी क्यों नहीं है।

श्री सभापतिः मलिक जी, इस बारे में आपको बजट में पता लगेगा 'अब 'आप बैठ जाएं। प्लीज आप बैठें। दूसरे मैम्बर्ज को भी बोलने का समय देना है।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, इस साल धान की फसल में बहुत नुकसान हुआ है। शायद करनाल में कम हुआ होगा। मैं अपने क्षेत्र की बात ही बता सकता हूं। लोगों के साथ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उनको उनकी कटाई की मजदूरी भी अपनी जेब से देनी पड़ी थी, सरकार ने इस तरफ भी कोई ज्यादा काम नहीं किया है। इसके साथ ही जापानी बैंकों से वन परियोजना को लागू करने में बहुत ही हेराफेरी हुई है। (विघ्न) सर, यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट था।

श्री सभापतिः मलिक जी, आप लिखकर दे दें उस बारे में इन्कवायरी करवा ली जाएगी। अब आप बैठें।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, मुझे पता था कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने अपनी बनाई हुई लिस्ट नहीं पढ़ी है। अब मैं अपनी आखिरी बात कह लेता हूं। मैं आखिर में सरकार की अच्छी बात बताना चाहता हूं और सरकार की तारीफ भी करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सरकार की एक तारीफ भी करने का मौका नहीं देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापतिः नहीं नहीं, आप बैठ जाएं।

श्री नरेश मलिकः सर, मैं सरकार की एक ही– अच्छी बात बताने जा रहा हूं क्या आप मुझे वह भी बोलने नहीं देंगे। मैं तो सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सांपला में साइबर सिटी, मेडी सिटी स्थापित करने के लिए सरकार ने जो योजना बनायी है उसके लिए मुझे पता नहीं कि बजट में कितना प्रावधान होगा लेकिन इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद कि आपने सदन के कीमती समय में से कुछ समय मुझे बोलने के लिए दिया। श्री राधे शाम शर्मा अमर (नारनौल): चेयरमैन साहब, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने का समय दिया दुसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जब मैं इस अभिभाषण को पड़ रहा था तौ मुझे एक बात याद आ गयी। मैं किसी मंदिर में गया हुआ था उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि चिन्ता किसे है देश की, सब स्वार्थ में अंधे हुए, देश सेवा, देश भक्ति आज सब धंधे हुए। जब मैंने इस अभिभाषण को पड़ा तो पाया कि हमारे महामहिम जी ने और हमारे सारे सदन ने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, आर्य समाजी, गरीबों और किसानों के हितैषी स्वर्गीय रणबीर सिंह हुड्डा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तभी उनकी तस्वीर मेरे सामने आयी। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें या न रहें। मातृभूमि का जो वैभव है, जो गरिमा है वह बनी रहे चाहे हम रहें या न रहें। चेयरमैन साहब, तब यह बात मुझे झूठी लगी कि अभी जो भारत

भूमि है वह देशभक्तो से, वीरों से, दानियों से खाली नहीं छै। यह रत्न गर्भा भूमि अभी भी भरी हुई है। यही वह संस्कार हैं, यही पारिवारिक जीवन की पहली पाठशाला है। चेयरमैन साहब, आप जानते ही हैं कि परिवार के संस्कार, मां बाप के संस्कार परिवार के सदस्यों और बच्चों पर आते हैं। उस महान स्वतंत्रता सेनानी ने जो संस्कार दिए थे वही संस्कार हमारे मुख्यमंत्री जी के अन्दर आए हैं क्योंकि माता–पिता का असर बच्चों पर जरूर होता है। यही कारण है, यह बात है और यही ताकत इसके पीछे है कि कभी जो प्रदेश एक तरह से जंगलराज के रूप में पिछली सरकार के वक्त में जाना जाता था .और डकैती का या लूट खसोट का पर्याय बन गया था इस सरकार के आने के बाद आज नम्बर एक का प्रदेश बन गया है। जैसा कि हमारे काबिल भाई बता रहे थे कि हरियाणा में उस समय कोई सेफ और सुरक्षित नहीं था। लेकिन ऐसे बिगडे हुए हालात को हमारी सरकार ने पटरी पर ला दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी सारी टीम का उस बिगड़े हुए हालात को पटरी पर लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन साहब, यह जो अभिभाषण है इसमें भी बजट की छाया दिखाई देती है क्योंकि अब वार्षिक योजना को बढ़ाकर दस हजार करोड़ रुपय का किया जा रहा है और प्रजातंत्र की स्थापना की जा रही है। पिछली सरकार के वक्त तो प्रजातंत्र समाप्त हो गया था। इस समय हमारे ये साथी सुनने के लिए यहां पर नहीं है क्योंकि वे सारे उठकर चले गए हैं। चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 जनवरी को एक सभा माननीय मुख्यमंत्री जी

की निजामपुर में हुई थी। उस सभा में बिना बुलाए ही सात आठ हजार आदमी आए थे। आपने भी उस रैली के बारे में सुना होगा। जब मैने वहां पर रैली के बारे मैं रिश्तेदारों से पूछा कि बताओ पाँच साल पहले भी क्या कोई आदमी आया था और अगर आया था तो क्या हुआ था? उन्होंने मुझे बेझिझक बताया कि पांच साल पहले ओम प्रकाश चौटाला जी आये थे और मालाओं की गठरी बांध–बांधकर ले गए थे। चेयरमैन साहब, लेकिन अब क्या हुआ? मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां के लिए दो पी०एच०सीज० बनायी और नलवाडी क्षेत्र के प्रत्येक गांव को 10– 10 लाख रुपये दिए। इस तरह से उन्होंने वहां के गांवों के विकास के लिए एक करोड़ तीस लाख रुपये दिए हैं। इसी तरह से दो गांवों को उन्होंने 25–26 लाख रुपये दिए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने घोषणा की कि मैं दो करोड़ रुपये इस हल्के के विकास के लिए और देता हूं। मैंने जब लोगों से पूछा कि इस सरकार में, इस मुख्यमंत्री में और इस व्यवस्था में आपको क्या अंतर लगा तो लोगों ने जो मुझे बताया वह मैं बताना चाहता हूं। हमारे इधर के बी०जे०पी० के साथी अब चले गए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस पार्टी का ये साथ देने जा रहे हैं उससे इनका कुछ भला होने वाला नहीं है। उन लोगों ने मेरे गांव से ही अपनी वह यात्रा शुरू की थी। उन्होंने उस यात्रा को जन आक्रोश यात्रा की संज्ञा दी है। चेयरमैन साहब, दुर्भाग्य की या सौभाग्य की बात कहिए कि उस समय वहां से मेरी गाड़ी आ रही थी। उन्होंने मेरी गाड़ी को घेर लिया और मुझसे कहा कि बताओ पंडित जी

यात्रा की शुरुआत कैसी रही? वहां पर जानने वाले एक साथी थे मैंने कहा कि आप सब बाहर से आए हुए हो 'और आपका जो कर्म है गाड़ियों को घेरना और रास्तों को रोकना, वह आप दिखा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जनाक्रोश तो है लेकिन हमारी सरकार के प्रति कोई जनाक्रोश नहीं है। जनाक्रोश तो जो इनैलो और भाजपा की मिली जुली पिछली सरकार थी और उन्होंने जो जनता पर जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे उसके बारे में है। जनता के मन में जनाक्रोश इस बात के प्रति है कि जो हमारी सरकार ने हांसी बुटाना लिंक नहर बनाई है उससे जो पानी मिलना था उस पानी को उन्होंने रोका है। उसके प्रति जनाक्रोश है और अब चुनाव आने वाले हैं। एक कहावत है जिसमें किसी जाति का भी जिक्र आता है और मैं किसी जाति के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि बाल कितने काटेगा तो वह कहने लगा जजमान तेरे आगे आ जाएंगे। मेरा यह कहना है दिन आगे चुनाव आएंगे तो आप इसका परिणाम देख लेना। इन साथियों की पार्टी के कुछ सदस्य अच्छे हैं लेकिन वे भी साथ में पाप के भागी हो रहे हैं। इनको इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। चेयनमैन सर, सिंचाई के कारे में कहना चाहूंगा कि हमारे एरिया में मसानी बांध की नहर बनाई और हमीदपुर की नहर बनाई, उसके लिए मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देता हूं। मेरे हल्के में एक गोदवाला क्षेत्र की छोटी नहर की बहुत आवश्यकता है और मेरी ये मांग है, उसको ये पूरा करें। हमारे माइल क्षेत्र में सर्वे की जरूरत है। मेरे हल्के में नलवाटी

निजामपुर में पानी के लिए नहर की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हू कि जन स्वास्थ्य के लिए बहुत पैसा दिया गया है, नलकूप लगाए गए हैं। टयूबवैल लगाए गए हैं, पीने के लिए पानी दिया गया है लेकिन यह सब अस्थाई व्यवस्था है। एक स्कीम हमने तैयार करवाई है और उसके बारे में सरकार को लिखकर भिजवाया है। इस स्कीम के लिए 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिससे 20 गांवों को लाभ मिलेगा। बजट में जो 10 हजार करोड रुपये का प्रावधान रखा जाएगा उसमें से इस उठ करोड़ रुपये की स्कीम को भी मंजूर किया जाए जिससे कि जो जमीन के नीचे पानी कडुवा है और०पर पानी है नहीं उस समस्या से निजात मिल सके और मेरे एरिया के लोगों को पीने का पानी दिलाने में कामयाबी मिल सके।

चेयरमैन सर, बिजली की कमी है और हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते भी हैं। सच्चा आदमी वह होता है जो सच्चाई को माने। झूठा आदमी सच्चाई को नहीं मानता है लेकिन वह एक दो दिन ही लारा लप्पा लगा सकता है परन्तु हमेशा के लिए कामयाब नहीं हो सकता है। बिजली की कमी दूर की जा सकती थी लेकिन किसी ने नेकनीयती से काम नहीं किया। अब मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से झाडली, खेदड, हिसार और फरीदाबाद, यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट्स पर काम शुरू हो गया है और शीघ्र ही जब ये प्लांट्स चालू हो जाएंगे तो बिजली की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। अब विपक्ष– के पास कोई मुद्दा

है ही नहीं। जबरदस्ती शोर मचाते हैं। चेयरमैन सर, हमारे यहां नांगल चौधरी का सव स्टेशन है उसकी मशीनरी काफी पुरानी हो गई है उसको ठीक किया जाए ताकि वह सव स्टेशन ठीक ढंग से काम कर सके। निजामपुर के सब स्टेशन में भी लोड बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए उसका लोड बढ़ाया जाए। मेरे हल्के का डकौडा और नैण का क्षेत्र ऐसा है जहां 15 गांव इकट्ठे बसे हुए हैं। उनमें बिजली की बहुत कमी है इसलिए मैं वहां नये सब स्टेशन की मांग करता हूं। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिजली के पोल बदलने के लिए मैंने पिछले सत्र में भी सवाल उठाया था और सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि इनको छह महीनों में पूरा कर देंगे लेकिन अब तक कुछ पोल ही बदले गए हैं। वहां से लोहे के पोल हटाकर सीमेंट के पोल लगाए जाएं क्योंकि वहां पर हमारे किसानों की दो भैंसे करंट से मर गई हैं और उनको अब तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उनको मुआवजा भी दिया जाए। चेयरमैन सर, मैं टेल्स के बारे में कुछ कहना चाहता है। सर, टोटल 66 टेल्ज हैं जिनमें से मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके उठ टेल्स पर पानी पहुंचा दिया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में टोटल 2 ही टेल्ज हैं और दोनों पर पानी नहीं पहुंचता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों टेलों पर पानी पहुंचाया जाए। किसाऊ, रेणुका और लखवारी डैम के बारे में चौधरी रणबीर सिंह जी ने प्रयास किया

था और उन्होंने किसाऊ डैम को स्वयं जाकर देखा। मुख्यमंत्री जी का व्यान मैंने इस बारे में पड़ा था उन्होंने कहा है कि किसाऊ डैम को जल्द पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वह करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे जल्दी पूरा किया जाए ताकि दक्षिण हरियाणा में पानी थोड़ा ज्यादा पहुंच सके। शहरों और गांवों के विकास के बारे में महामहिम के अभिभाषण में कहा गया है। यह ठीक है कि खूब विकास हुआ है। नारनौल में बहुत विकास हुआ, नई सब्जी मण्डी का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। पानी का बहुत बड़ा टैंक बना दिया है इसके अलावा आडिटोरियम बनाया जा रहा है। बी०एड० कालेज की बिल्डिंग बन रही है। सीवर बनाया गया है। इसके बावजूद कुछ मोहल्लों में सीवर की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो पाई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मोहल्ले रह गये हैं वहां पर भी सीवर की व्यवस्था के लिए और पैसा दिया जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम के लिए जो इतना धन दिया है वह अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सके। इस बात के लिए चेयरमैन साहब मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं। चेयरमैन साहब, परिवहन का जहां तक सवाल है माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं इनको मैं समय–समय पर मिलता रहता हूं और ये बड़ी सद्भावना पूर्ण तरीके से मिलते हैं और ये बहुत अच्छे हैं हमारे अनुरोध को मान भी लेते हैं और पूरा भी करते हैं। हमने इनसे बस चलाने के लिए कहा तो इन्होंने एक बार तो बस चला दी थी लेकिन 10–15 दिन में वह बस बंद हो गई। लेकिन

हमारे जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर बसें नहीं जाती हैं और एक आध बस जाती है तो जो रूट्स हैं उनको कंडक्टर और ड्राईवर छोड़ देते हैं हमारी लड़कियां जो 25 किलोमीटर से नारनौल कालेज में पढ़ने के लिए आती हैं उनके लिए या तो बस चला दी जाए या फिर निजामपुर में लड़कियों का कालेज बना दिया जाए।

श्री सभापतिः शर्मा जी, आप कन्कल्यूड कीजिए।

श्री राधे श्याम शर्मा अमरः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्यटन के बारे में बधाई देना चाहता है जिन्होंने हमारी चमन ऋषि की भूमि ढोसी हिल्म के लिए 5 करोड रुपये देकर एक शानदार हर्बल पार्क बनाया है उसके लिए मैं उनको बार–बार बधाई देता हूं। चेयरमैन साहब, नारनौल– एक ऐतिहासिक शहर है और पर्यटकों को शुभाने के लिए बहुत अच्छा है अगर इसका थोड़ा और विस्तार किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और इसके माध्यम से इस शहर का गौरव बढ़ेगा। चेयरमैन साहब आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर दोहराना चाहता हूं जो हमारे विपक्ष के भाई हैं, उनके लिए मैं एक निवेदन करता हूं कि उन पर अंकुश लगाने के लिए एक लाईन का जवाब बना लिया जाए और उनके हाउस में आने के दाद उनसे पूछ लिया जाए कि आप सदन में रहना चाहते हो या बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि इससे बहुत अनुशासनहीनता होती है

जिसकी वजह से हमारी विधानसभा बदनाम होती है। चेयरमैन साहब, मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि इनको वह दिन याद आता है जब ये लोगों को लूटते थे। आज सदन में आकर कह रहे थे कि इतनी कानून व्यवस्था खराब हुई, इतनी घटनाएं हो रही हैं, गोलियां चल रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके राज के मुकाबले में आज कितनी गोलियां चल रही हैं। जिनको आपने छूट दी थी, जो जंगलराज इनके राज में कायम किया गया था, जो बुराई इन्होंने शुरू की थी, बुराई को तो आप एक मिनट में शुरू कर सकते हैं। यह इतना शानदार भवन है इसको बनाने में बहुत समय लगा होगा लेकिन आप इसको एक मिनट में गिरा सकते हैं। जो उन्होंने बुराई शुरू की थी उसकी जड़ जमाई थी उन बुराइयों को समाप्त करने में कुछ समय लगेगा जो गुण्डा एलीमैंटस इन्होंने बैठा रखा है उसको इस सरकार ने इतना रोका है कि यह कोई छोटी बात नहीं है आज वे अनुशासन की बात करते हैं। आप यह जानते हैं कि इनके समय के अन्दर जितने विपक्ष के भाई थे। मुझे इन्होंने एक चार्ज शीट दी कि आपने मंदिर का कमरा कहां से बनाया, आपने स्कूल का कमरा कहां से बनाया? इनको और कुछ तो मिला नहीं। मेरी ईंटें गिनी वे पूरी पाई मेरी जो जमीन की आमदनी है उससे कहीं कम बनती हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपने यह स्टेडियम की दीवार कहां से बनाई तो मैंने ऐफीडेविट दिया कि मेरा भाई एम०एल०ए० था, मेरी धर्मपली जिला परिषद् की चेयरमैन थी और मैं इलैक्शन लड़ रहा था। हम तीनों को लोग तौलते थे और हमने यह प्रतिज्ञा

की थी और हमने यह वायदा किया हुआ है कि उस पैसे को धर्म खाते में लगायेंगे। यह तो मेरा ऐफिडेविट है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि चौटाला साहब की गाड़ी में जो पैसा जाता है उसका क्या हिसाब है? आज तक वे जवाब नहीं दे पाये। चेयरमैन साहब, मैं डूबते जहाज को पत्थर नहीं मारता हूं। जब चौटाला साहब फरवरी में मुख्यमंत्री बने तो मार्च में मैं हरियाणा भवन में इनके पास गया था और मैं इनको कहकर गया था कि आपने बेईमानी करके मेरे 16 हजार वोट्स को 15 हजार काउंट करके मुझे 15427 वोटों से हराया है। मैं विधायक बनकर आऊंगा, यह जनता जनार्दन का फैसला है लेकिन आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। मैं यह बात उस समय कहकर आया था जब इनका सूर्य शिखर पर था। आज ये जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। यह सब फ्राड है और यह सब धोखा है। इनके पास आदमी नहीं थे, वे जबरदस्ती आदमियों को उठा–उठा कर ला रहे थे।

Mr. Chairperson : In democratic system, people automatically punish and they have been punished.

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब 4 साल इनका राज बीता तो जब ये रैलियां करते थे, जन सभाएं करते थे तो इनके पटवारी क्या, थानेदार क्या और यहां तक कि सारे का सारा सरकारी अमला जबरदस्ती लोगों को लाते थे फिर भी लोग नहीं आते थे। मैं मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को उनकी जन हितैषी नीतियों के

लिए बधाई देता हूं। 4 साल बीतने के बाद लोग आते हैं और हमें कहते हैं कि विधायक जी हमारी फलानी बिल्डिंग का उद्घाटन कर दो, शिलान्यास कर दो। इनके पास आदमी आते नहीं थे और इनका बहिष्कार होता था। यह लोक कल्याणकारी राज है। हमारे मुख्यमंत्री में अच्छे राजा के गुण हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि यथा राजा तथा प्रजा। जबकि इनका जब राज था तो ये लूटेरों की तरह लोगों को देखते थे। मेरे शहर के नेतराम जैन ने चौटाला जी को अपने घर पर चाय के लिए बुला लिया। उसने सोचा कि मुख्यमंत्री जी आएंगें तो अधिकारी दबते रहेंगे, पता नहीं तू क्या–क्या काम करा लेगा। अध्यक्ष महोदय, चाहे तो इसकी इंकवायरी करवा ली जाए। जब मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने कहा जैन तेरी ये कोठी कितने की बनी। मैं हरियाणा का सबसे बड़ा लैडलोर्ड हूं और मेरे पास भी इतनी बड़ी कोठी नहीं है। जैन ने मुख्यमंत्री को 15 लाख रुपये देकर पीछा छुड़वाया। मुख्यमंत्री की गाड़ी जब भी वहां से जाती थी तो वह अस्पताल में भर्ती हो जाता था कि कहीं उसे बुला न लें। राजा होते हुए इनके ऐसे हालात थे। जबकि राजा जब आता है तो लोग सोचते हैं कि राजा आएगा तो खजाने खोलेगा और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तीन बार नारनौल में गए और तीनों बार हमारे नारनौल जैसे बैकवर्ड क्षेत्र को 114 करोड़ रुपये देकर आए। सभापति महोदय ये तो 500–500 की माला लेने में सारा समय लगाते थे, ये जनता को क्या देखते थे। इनकी नजर कहां जाती थी आपकी कोठी पर। आपके टायलैट में कैसी टाइलें लगी हैं? ये

हालात थे उस समय के राजा के। हमारे मुख्यमंत्री महोदय की नजर कहां जाती है कि इस गांव को कितना कष्ट है, पानी की इस गांव में कितनी कमी है? यह नजर का फर्क है। नजर तो देखती है। आखें तो देखती हैं लेकिन देखने का तरीका अलग–अलग है। राजा का यह कर्त्तव्य है कि प्रजा को देखें, प्रजा की तकलीफ को देखें और उसकी तकलीफ का निवारण करे। मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वे हमारी तकलीफों का निवारण करते हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि––

'कर्म प्रधान विश्व रची सुखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा।' '

यह संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये जो आपके सामने खाली सीटें पड़ी हैं, इन्होंने जैसा कर्म किया था उसका फल भोग लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर्म कर रहे हैं। उसका नतीजा आप देख लें, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है और गांव की बात तो गलियारे ही बता देते हैं और चुनाव बता देंगे।

श्री सभापतिः राधेश्याम जी, जब हम इधर बैठा करते थे और तब इधर से आवाज आया करती थी कि इधर से कोई उधर नहीं आ सकता। इस विषय में हमारे माननीय मंत्री मांगेराम गुप्ता जी ही बता सकते हैं। In democracy, automatically public gives

proper reply and they have been given. (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

श्री राधेभाम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय आ गए हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री महोदय जी को भी बधाई देता हूं कि ये इनको बोलने के लिए इतना समय देते हैं वरना वह समय भी मैंने देखा है जव इधर ते चिटकणी लगा देते थे और अंदर नहीं घुसने देते थे। (विघ्न) वायदे तो वायदे होते हैं। वे वायदे क्या जो निभाए न जाएं। ये तो केवल कहना जानते हैं और अपनी बात का जवाब सुनने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये अपने वायदे पूरे नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, अपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, श्री नरेश मलिक जी जो कि भाजपा के दो सदस्यीय दल के नेता हैं आपने उनसे विशेष तौर से अनुरोध भी किया था कि आप बोलने के लिए पूरा समय ले लेकिन वोलने कै बाद आप हाऊस से बाहर नहीं जायेंगे। वे बाहर चले गये थे लेकिन मुझे खुशी है वे मेरे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं वे अब वापिस आ गये हैं। उन्होने बहुत सारी बातों की चर्चा की उसका माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। विशेष तौर से उन्होंने एक बात की चर्चा की कैग रिपोर्ट की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करवाकर। मैं केवल उसके बारे में उनकी टिप्पणी का जवाब देना

चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बिजली का जो सामयिक खरीद है यह एक कमर्शियल डिसीजन है। हर साल हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास 600 मैगावाट के करीब अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हौती है जौ वै गर्मियों मे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान को बेचते हैं वर्ष 2007 के बारे में कैग रिपोर्ट में भी चर्चा की गइ है। हम कैग को भी लिखकर भेज रहे हैं। उसमें 600 में से 100 मैगावाट क्योंकि हम अपने सीमित साधनों के मुताबिक चाहे वह सरकारे से सरकार की ही खरीद हो पर फिर' भी हम उतनी ही बिजली लेते हैं जितने हमारे पास साधन हों। वे पहले तो हमें नैगोशिएट करके ठीक रेट पर अर्थात् 4 या 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दे दिया करते थे। जब वहां पर कांग्रेस कीं सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने वहां की विधान सभा के अंदर एक प्रश्न उठाया जिसमें यह कहा कि आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान को आपस में बगैर बोली करवाये बिजली क्यों देते हो और मजबूरन उस समय की सरकार को यह आश्वासन देना पड़ा कि हम आगे से नहीं देंगे और हम आगे से पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन जिसमें भारत सरकार का भी होल्ड है के माध्यम से बोली करवाकर बिजली देंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथियों के प्रश्न के चलते वर्ष 2007 में यह फैसला किया कि वे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान को बिजली बोली करवाकर देंगे और जब बोली करवाई गई तो रेट 7. 15 रुपये आया। इस पर हमने कहा कि हम तो केवल 100 मैगावाट लेंगे इस रेट पर 600 मैगावाट लेने की हमारी हिम्मत

नहीं है। इस प्रकार से हमने उस समय 100 मैगावाट 7.15 रुपये के हिसाब से ली जिसमें लैंडिड कॉस्ट और ट्रांसमिशन कास्ट अलग से शामिल होती है। इस प्रकार से वह बिजली हमें 740 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिली। अध्यक्ष महोदय, जब हम बिजली खरीदते हैं तो हम 6 महीने पहले खरीद लेते हैं। क्योंकि बिजली अगर भूटान या उत्तर पूर्व से आनी है तो हमें उसके लिए लाईन की बुकिंग करवानी होती है। अगर मैं यह चाहूं कि मुझे कल पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल की बिजली मिलनी शुरू हो जाये तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लाईन जो कि एक है उसे कोई और बुक करवा लेगा। इसलिए लाईन की बुकिंग 6 महीने पहले करवाते हैं। कैग ने यह पाया कि छ महीने बाद जून–जुलाई में हमने वह बिजली ली क्योंकि इस समय हमारे पास बिजली की बड़ी तंगी होती है। हर तरफ बिजली के लिए त्राहि–त्राहि मची होती है। उस समय हमारी यही कोशिश होती है कि एकएक मैगावाट भी हमें जहां की से भी जिस रेट पर भी हमें बिजली मिले हम खरीदकर अपने उपभोक्ताओं को दे सकें। जब बिजली खरीदी गई उस समय ग्रिड का रेट कम था ९ अध्यक्ष महोदय एक तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमने यह बिजली सरकार से खरीदी न कि किसी प्राईवेट पार्टी से, दूसरी बात जिस रेट पर हमने बिजली खरीदी उसी रेट पर तत्कालीन राजस्थान सरकार ने भी खरीदी, उसी रेट पर पंजाब ने और उसी रेट पर दिल्ली ने खरीदी। हमने 600 मैगावाट में से केवल 100 मैगावाट ली क्योंकि हम ज्यादा नहीं ले सकते थे।

पिल्ले साल मी हमने हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बिजली ली है और इस साल फिर लेंगे क्योंकि गर्मियों की मौसम में हमें ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम सर्दी के मौसम में लगभग 200 मैगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश को दे देते हैं और इतनी ही बिजली हम उनसे गर्मियों के मौसम में ले लेते हैं। इस सिस्टम को बैंकिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ हम उनसे मोल ले लेते हैं। यह एक कमर्शियल डिसीजन होता है इसमें कैग ने यह एतराज किया है कि आप उस समय ग्रिड से ओवरड्रा करते। लेकिन हमें क्या पता था कि ग्रिड का रेट जून–जुलाई में क्या होगा हम तो 8 महीने पहले खरीद चुके हैं। इसलिए यह एक कमर्शियल डिसीजन था। केवल व्यवस्था का प्रश्न था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है और मैं मानता हूं कि आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं और इस बात को समझ भी सकते हैं पड़ोसियों की तरह नहीं हैं जो केवल अनर्गल बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, नरेश जी एक सूझवान, बुद्धिमान और पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं और अच्छा विचार रखते हैं इसलिए मुझे लगा कि ये बात आपके माध्यम से सदन को और इनको भी बताई जाये।

श्री नरेश मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कर रहा था वह तथ्यों के आधार पर कर रहा था और उसको माननीय मंत्री जी भी मना नहीं कर सकते। यह प्रदेश के हितों की बात थी इसलिए मैंने यह बात उठाई। अव मंत्री जी ने जबाव दे दिया है

और मैं जबाव से संतुष्ट हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, यहां कोई डिबेट नहीं हो रही है। आपने बात कही थी उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। आप फिर बोल लेना अब मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान बोलेंगे।

Major Nirpender Singh Sangwan (Dadri) : Sir, on the onset, I would like to remember late Ch. Ranbir Singh, and his principles that he followed in his life. He was a great leader not only for Haryana but also for the whole of India. Going through his authobiography and seeing the film that we saw yesterday one relies what a great Header he had been. I had the good fortune of meeting him with my Grandfather Ch. Suraj Mal when I was in school and 1 found him to be a very loving and caring elderly grandfather and for him I am reminded of four lines of a stanza of a poetry caHled the sum of life

"Lives of great men all reminders, we can make a live sublime and departing leave behind us footprints on the sends of time."

18.00 बजे

The present Government when it assumed office the plan size in the year 2004-05, it was Rs. 2236 crore, Against this, the size of the proposed plan is Rs. 10000 crore. I must congratulate the Government, the Chief Minister, the Finance Minister and all other, who have been in the whole cog, who have planed the budget progressively over the last four years.

In the agriculture sector, the farmers' concerns are so prominent because of the spurious seeds, pesticides and fertilizers which are still available. We must make a rule and see that any kind of spurious seeds pesticides and fertilizers sold in the market. The person who is responsible for this should be going in for a very torturous guilt. Only then we will be able to solve this problem. The underwater in most of our areas is depHeated. The ground water is going down. So, we have to make a State Policy to save ground water so that nobody can dig a well at his own thought. जब भी चाहे वे कुंआ खोद लेते है जिसको वजह से आज की तारीख में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। सिंचाई विभाग की तरफ से बहुत सारे नये नाले बनाये गये हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में पानी का समान बंटवारा हो रहा है परन्तु आज की तारीख में बहुत से ऐर्से खाल हैं जिनकी रिपेयर बहुत जरूरी है और जिनको आगे बढ़ाने से, थोड़ा बहुत काम करने से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। पब्लिक हैल्थ का काम भी काफी होना बाकी है। मैं और शहरों का जिक्र न करते हुए अपने खुद के शहर दादरी के बारे मैं बताना चाहता हूं। पब्लिक हैल्थ एक ऐसा डिपार्टमैंट है जिससे आम आदमी बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है और आज के दिन दादरी शहर में पब्लिक हैल्थ की सीवरेज और वाटर सप्लाई में बहुत काम करने की जरूरत है। वहां पर जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी हैं मैं अन्पके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उनके०पर निगरानी रखी जाए ताकि सरकार जो काम करवाना चाहती है वह तरीके से हों और टाईम

पर पूरे किये जा सके। हम बिजली के बडे–बड़े प्रोजैक्ट्स लगाने जा रहे हैं इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में उनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। जब तक यह उत्पादन शुरू नहीं हो जाता तब तक बिजली का सही बंटवारा करना बहुत जरूरी है। इस बारे में माननीय मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि बिजली का समान बंटवारा किया जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि शहरों और गांव के जो टयूबवैल्ज हैं उनके कण्डक्टर्ज और सप्लाईज अलग–अलग कर दी जाए। बिल्डिंगज और रोडज काफी बनाई गई है। माननीय मंत्री जी ने उन पर काफी ध्यान भी दिया है परन्तु आज की तारीख में भी इनकी क्वालिटी कण्ट्रोल पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी जगहों पर जहां पर नई रोड्ज बनाई गई हैं उनके अन्दर त्रुटियां आ गई हैं, खड्डे पड गए हैं, जिसकी वजह से असहूलियत तो है ही, सरकार की इसमें कई दफा छवि खराब होती है यह सोचने में आता है और लोग उसके बारे में बात करते हें। लेबर और इम्पलायमैंट के बारे में जहां तक सवाल है हम इन्तजार कर रहे हैं कि कब एस०ई०जैड बनें और कब हमारे बच्चों को इम्पलॉयमैंट मिलेगी।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिह यादव): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। कल भी यहां पर सड्कों का काफी मुद्दा उठाया गया था मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा डिपार्टमैंट सोफ्ट है। जिन अधिकारियों ने अपनी टैन्योर में कोई

अनियमितताएं की हैं या कोई गलतियां की हैं, हमने उन 120 अधिकारियों को चार्जशीट किया है। सर, ऐसा नहीं है कि सरकार इस बारे में कुछ विचार नहीं कर रही है। हम इस बारे में चिन्तित हैं। स्पीकर सर, पिछले साल बरसात बहुत ज्यादा हुई थी इसलिए कुछ दिक्कत रही है लेकिन फिर भी हमने 120 गजेटिड आफिसर्ज को चार्जशीट किया है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः स्पीकर सर, ट्रांसपोर्ट के लिए मेरी यह गुजारिश हैं किं दादरी के अन्दर पहले एक ट्रांसपोर्ट डिपो हुआ करता था जिसे तोड़ दिया गया था। मेरा यह निवेदन है कि इसको दोबारा से बहाल किया जाए और इस डिपो को अपग्रेड भी किया जाए। अर्बन डिवैल्पमैंट और टूरिज्म के जो–जो काम हमारी सरकार ने किये हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं! रूरल डिवैल्पमैंट के अन्दर जितना काम हमारी सरकार ने पिछले चार साल में किया है उतना काम शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गांवों के अन्दर सी०सी० की रोडज और इन्टरलॉक की रोडज बनाई गई हैं। आज हरियाणा के अन्दर शायद ही कोई ऐसा गांव हो जिसके अन्दर कोई मेन गली आज की तारीख में कच्ची हो। ऐजुकेशन डिपार्टमैंट में माननीय मंत्री जी ने इतनी भर्तियां की हैं परन्तु आज भी कई ऐसे ज्या हैं जिनमें स्टाफ की कमी है। इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर और नई भर्तियां करके स्टाफ पूरा करना चाहिए। स्पीकर सर, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज की तारीख में जो बच्चे प्राईवेट स्कूलों में चले

गए थे वे दोबारा गवर्नमैंट स्कूलों के अन्दर भर्ती होने लगे हैं। स्पीकर सर, आखिर में मैं डिफैंस परसोनल्ज की बात करूंगा। पंजाब स्टेट के बाद हमारी स्टेट के अन्दर सबसे ज्यादा 1.68 लाख सर्विंग सोलजर्ज और 2 .8 लाख ऐक्स–सर्विसमैन हैं। हमारी सरकार ने इनके लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ और करने जा रही है। उनको सारी चीजें तथा कई सहूलियतें दी गई हैं और इनके भत्तों के अन्दर बढ़ोतरी की गई है। इनके बच्चों के लिए नई–नई जगहों पर पर सैंटर्ज खोले गए हैं ताकि वे वहां पर कुछ सीख सकें। स्पीकर साहब, मैं सरकार से एक और गुजारिश करना चाहता हूं जो यंग वार विडोज हैं उनके सीखने के लिए, उनको काम देने के लिए और उनको नौकरी देने के लिए एक स्पैशल स्कीम होनी चाहिए ताकि वे पैंशन पर ही निर्भर न रह कर अपना व्यवसाय चलाकर अपना और अपने बच्चों का भरण–पोषण कर सकें। श्री बचन सिंह आर्य (सफीदों): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद की आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सर्व–प्रथम देश–भक्त, स्वतंत्रता सेनानी, गांधीव्रता, कुशल राजनैतिज्ञ, समाज सुधारक चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के बारे में जिक्र किया गया है। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के जीवन के बारे में मुझे काफी जबरदस्त बातें पता चली जोकि मुझे पहले पता नहीं थीं। एक लेखक ने उनके जीवन के बारे में बहुत ही बढ़िया 'स्वराज के स्वर ' नामक पुस्तक लिखी हे और मैंने उसको पढ़ा है। उस पुस्तक को पढ़कर, देखकर, समझकर और उसका मनन

करने से पता चलता है कि राजनीति में किस तरह से ईमानदारी और सहजता से समाज और राजनीति को साथ लेकर अपना जीवन जिया जाता है। मुझे गर्व इस बात का है कि वे महर्षि दयानंद के अनुयायी आर्य समाजी परिवार से संबंध रखते थे और कभी भी कोई दिखावा नहीं करते थे। वे संविधान निर्मात्री कमेटी के सदस्य रहे, विभिन्न विधान सभाओं, राज्य सभा और लोक सभा में रहे थे। उन्होंने मंत्री पद को भी सुशोभित किया और उसके बावजूद उन्होंने 64 वर्ष की उस में एक उदाहरण पेश किया। जो सस्ता और लोलूपता दिल और दिमाग में रहती है, उन सारी बातों को भूल कर राजनीति से सन्यास ले लिया। उसके बाद वे सक्रिय रूप से समाज कल्याण के कार्य में लग गए और लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। वे 8–9 जेलों में रहे और जब बाहर आए तथा देश आजाद हुआ तो उन्होंने सर्व–प्रथम हरियाणा की मांग की थी। (विघ्न) यह गर्व की बात है कि उनके पिता चौधरी मातुराम जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ मिलकर, महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए एक ललकार दी थी कि अंग्रेजों देश से बाहर जाओ। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए बहुत से साथियों ने कहा कि उन्होंने सीमित साधनों के होते हुए देश की आजादी के लिए काम किया था। बहुत सी चीजों का अभाव होते हुए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। मुझे कथिक जी की वह बात याद आती है और उनके बारे में वही बात ठीक बैठती है –

वह खून कहो किस मतलब का,

जिसमें उबाल का नाम नहीं।

वह खून कहो किस मतलब का,

जो आवे देश के काम नहीं।।

वह खून कहो किस मतलब का,

जिसमें हरकत नरवानी है।

जो परवश होकर बहता है,

वह खून नहीं वह पानी है।।

जिन चौधरी मातूराम जी ने श्रद्धानंद जी के साथ मिलकर के देश की आजादी के इतिहास के पन्नों में अपना नाम किया था, उनका खून चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के अन्दर था और उन्होंने अपना खून देश की सेवा के लिए लगाया। ' 'यह आजादी का संग्राम नहीं, पैसों से खेला जाता है। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। '' इसी कहावत को चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने सार्थक किया। मैं एक बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ सीनियर साथियों ने कहा कि वे आर्य समाजी थे। ठीक है वे आर्य समाजी थे लेकिन वे और धर्मों का भी आदर करते थे, वे साम्प्रदायिक नहीं थे। मुझे खुशी है कि वे आर्य समाजी थे और

मुझे यह भी खुशी है कि देश को आजाद करवाने के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी और आर्य समाजी लगे हुए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आर्य समाजी हैं, वैदिक धर्मी हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय भी प्योर आर्य समाजी हैं। आज पूरा हरियाणा एक श्रेष्ठ राज्य बना हुआ है। ऐसे ही राज्य की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की थी और उसके लिए संघर्ष किया था। आर्य समाज को मानने वाले लोग भी देशभक्त हैं उनको आप साम्प्रदायिक रूप में नहीं ले सकते। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरियाणा की उन्नति के लिए बहुत सी बातें कही हैं। मैं इतना ही इस बारे में कह सकता हूं कि जब से हरियाणा बना है तब से और बीस साल से जब से मैं राजनीति में हूं जितने विकास कार्य अब चल रहे हैं शायद आज तक कभी भी इतने विकास कार्य न हो पाए हों। अगर किसी को इस बात को कहने में हिचक है तो वह उसकी ओच्छी मानसिकता हो सकती है। अध्यक्ष महोदय चाहे प्रदेश की वार्षिक योजना की बात हो। इस बार वार्षिक योजना को बढ़ाकर दस हजार करोड़ रुपये के आसपास करना यह कोई छोटी बात नहीं है। पांच गुणा से भी ज्यादा इसमें वृद्धि की गयी है। इसी तरह से चाहे काले कानून को खत्म करने को बात हो या चाहें और बहुत से विकास कार्यों की बात हो, सब तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून हमारे किसानों के, मजदूरों के०पर जुल्म करता था। कोआपरेटिव सोसायटीज और भूमि विकास बैंक के कर्मचारी और अधिकारी आकर इनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। अगर किसी

मजदूर ने मजबूरी की वजह से अपनी दस हजार रुपये की किश्त न दी हो या अगर किसी किसान ने फसल के खराब होने की मजबूरी की वजह से अपनी किश्त न भरी हो तो बैंक के अधिकारी आकर उनको जीपों में डालकर ले जाया करते थे और ले जाकर बैंक की अलग से बनी हुई जेल में डाल दिया करते थे तथा उस दौरान उनसे खायी हुई रोटी के पैसे भी लिए जाते थे। इसलिए मैं सरकार का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है कि इन्होंने अपनी कलम से इस काले कानून को मिटाया है। किसान के लिए एवं मजदूर के लिए अगर कोई काम हुए हैं तो वह इस सरकार के समय में हुए हैं। इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। कोओपरेटिव सोसायटीज के ऋणों का व्याज माफ करने का और बिजली के बिलों के 1600 करोड़ रुपये माफ करने का भी काम इस सरकार ने ही किया है। इसी प्रकार से धान का भाव बढ़ाकर किसान को और मजदूर को जीने के लिए भी इस सरकार ने ही सहूलियत दी है। वे लोग बहुत लम्बे समय. से दबे हुए थे। इस समय हमारे विपक्ष के साथी बैठे हुए नहीं हैं। वे शोर मचा रहे थे और वे सच्चाई को मान नहीं रहे थे। उनको याद करना चाहिए कि किसान को चार साल पहले एक एकड़ जीरी का भाव केवल 6–6 हजार रुपये मिलता था। उस समय इतने ही भाव में किसान अपनी जीरी बेचकर जाया करते थे। उस समय लौग उनका देखकर किलकारियां मारा करते थे और कहते थे कि चौटाला तेरे राज में जीरी गयी व्याज में और पुराल गयी लिहाज में क्योंकि पुराल लोग मांगकर ले जाया करते थे या उठाकर ले जाया करते

थे। लेकिन आज हुड्डा साहब ने किसान को जो धान की 1121 पूसा वैरायटी का या दूसरी अन्य वैरायटीज का भाव दिया है वह काबिलेतारीफ है। उन्होंने केन्द्र सरकार से कहकर जो 1121 पूसा वैरायटी का एक्सपोर्ट खुलवाया है उससे किसानों में खुशहाली आयी है। स्पीकर साहब, कहां 6 हजार रुपये एक एकड़ में धान की फसल के भाव मिलते थे और आज कहां 50 हजार रुपये 48 हजार रुपये या 45 हजार रुपये तक एक एकड़ में धान की फसल के मिल रहे हैं। आज किसान का जो बेटा या मजदूर पांचवे हिस्से में धान लगाता है और जब आयशर ट्रैक्टर पर बैठकर 6 एकड़ की तीन लाख रुपये की जीरी बेचकर ट्रैक्टर पर थापी मारकर कहता है कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गयी जहाज में तो उसका चेहरा देखने वाला होता है। अब वह घर आकर खुश होता है। आज किसान और गरीब मजदूर खुश हुआ है जोकि बहुत उपकार की बात है। जहां तक गांव के विकास की बात है। गांवों में कंक्रीट की गलियां पहले देखने को नहीं मिलती थी। अब जब ये विपक्ष के साथी गांवों में वोट मांगने के लिए जायेंगे तो इनको संभलकर चलना पड़ेगा सर, हो सकता है कि ये फिसल जाएं क्योंकि चार साल पहले इन्होंने ऐसी सड़कें नहीं देखी थी। कभी दिल्ली के कनाट प्लेस पर ऐसी सड़कें देखने को मिला करती थी। अब हरियाणा प्रदेश में गांव की गलियों में मुख्यमंत्री जी ने ऐसी सड़कें बनवाई हैं। 11 हजार वाल्मीकि एस०सी० को स्वीपर के पदों पर लगाया गया है और एक स्वीपर को 3500 रुपये प्रति माह के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है और यह साल की 42 हजार रुपये

बनती है। पहले ऐसे 'अनपढ आदमी 20 हजार रुपये साल की तनख्वाह पर किसान के यहां नौकरी पर लगता था और रात दिन उसका नौकर हुआ करता था। रात को खेत में पानी चलाना, भैंस को पालना, सुबह भैंस को चारा डालना, इस प्रकार वह दिन रात जुटा रहता था और तनख्वाह इतनी कम मिलती थी। अब 42 हजार रुपये साल की तनख्याह लेकर दिन में 3–4 घंटे गलियों की सफाई का काम करके वह अपने बच्चों के साथ आराम करता है, बच्चों की देखरेख करता है अपनी गाय–भैंस पालता है। मुख्यमंत्री जी ने यह बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके अलावा अभी–अभी जो वर्तमान की समस्या थी जो कि पूरे हरियाणा में हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट का फैसला था जिसकी वजह से लोग त्राहि–त्राहि करने लगे थे। यमुनानगर से लेकर बीच से निकलते हुए मतलौडा सफीदों और जींद तक रोड के दोनों तरफ 30–30 मीटर तक बुलडोजर चलने की बात आ गई थी। 50–50 मीटर के दायरे तक दुकानों और मकानों को गिराये जाने की बात थी। लोग मुख्यमंत्री जी से मिले ओर दर्खास्त दी और हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कानून में अमैंडमैंट करके उन मजदूरों, किसानों और दुकानदारों की मेहनत को बचाया है। बड़ी मुश्किल से गरीब लोगों का एक मकान बन पाता है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी दरियादिली दिखाकर एक उदाहरण और मिसाल पेश की, पहली बार ऐसा हुआ। इसके अलावा मैं पशुधन के बारे में भी कहना चाहूंगा कि मुर्राह नस्ल की भैसों के सुधार की बात यहां लगातार आती रहती है। हरियाणा में आज से

चार साल पहले मुर्राह नस्ल की भैंसे 25 से 50 हजार रुपये मैं बिकती थी, अब यह 1 – 1 लाख और सवा व डेढ़ लाख रुपये तक में बिक रही हैं। यह अच्छी बात है कि बजट में मुर्राह नस्ल की भैंसो के सुधार के लिए अच्छा बजट रखा गया है लेकिन अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ता है कि गायों के बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो और किसी पशु के प्रति नतमस्तक ही न हों लेकिन गऊओं के सम्मान में हम उनके प्रति 'नतमस्तक जरूर होते हैं उनके लिए बजट की मात्रा ज्यादा नहीं दी। मेरी मांग है कि गऊओं के लिए सब्सिडी व दूसरी जो भी सुविधायें दी जानी चाहिएं वह दी जाएं। कानून व्यवस्था के बारे में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था के बारे में बी०जे०पी० के साथी ने थोड़ा बहुत जिक्र किया है। ये जो जिक्र कर रहे हैं ये लोगों के आपस के झगड़े हैं, किसी के खेत के, किसी के नाली के, किसी के जोहड़ के, किसी के और चीजों के हैं। अन्यथा हरियाणा में पूरी तरह से शान्ति है। जब से ये सरकार बनी उससे पहले जो लोग जेलों में बैठकर सरकार चलाया करते थे। भाई साहब के नाम से कानून को तोड़ा करते थे। अजय चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे हैं, उनके नाम पर गुंडागर्दी हुआ करती थी। उस समय ये जितने भी बदमाश थे वे या तो जेलों में चले गए या फिर प्रदेश छोड्कर दूसरे प्रदेशों में चले गए। अब पूरी तरह से प्रदेश में राम राज्य है। आज ये कानून

की बात करते हैं वह कानून तब कहां चला गया था जब मांगे राम गुप्ता जी के हल्के में और मेरे जिले के किसानों के बेटों पर गोलियां चलाई गई थी। इन्होंने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने की बात कही थी। बाद में किसानों ने कहा कि हमें समय दे दो हमारी फसल खराब हो गई है इसलिए हमें थोड़ा समय दे दो, हम बिल भर देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं और आदेश दिया कि जाओ और कनैक्शन काटो, मगर वह्हां के किसानों ने और वहां के मजदूरों ने और वहां की बहन और बेटियां सब अपने खम्भों से लिपट गये कि हमारी फसल खराब हो जायेगी और किसान मर जायेगा। परन्तु उस जालिम ने उस समय के मुख्यमंत्री ने उसी समय आदेश दे दिया कि कुछ भी हो यह ट्रांसफार्मर उतार कर लाओ भले ही गोलियां चलानी पड़े। उस समय की सरकार के आदेश से दनादन गोलियां चली और नौ किसान और मजदूरों के बेटों के सीनों के पार हो गई थी। आज भी जींद जिले के कण्डेला गांव की धरती उनके बेटों के खून से लाल हो रही है। जींद जिले का या हरियाणा का आज भी कोई ऐसा इन्सान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी खानदानी आदमी ऐसे परिवार को वोट देने का नाम ही नहीं लेता। सारी उस तक वह बहन और बेटी जिसका 28 साल का बेटा चला गया, वह मां होली के दिन खाना बनाया करेगी और रखा करेगी और रोया करेगी और सिसकारियां भरा करेगी मेरा 28 साल का इकलौता बेटा आयेगा और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। उसकी आखों में आसू होंगे और वह रो–रो कर अपने बिस्तर को गीला

कर दिया करेगी और इस जालिम को कोसा करेगी। आज वे लोग इस सरकार के अन्दर कानून व्यवस्था की बात करते हैं। राजनीति किस तरह से की जाती है यह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से सीखें और इनसे उनको मार्गदर्शन लेना चाहिए कि जीवन किस तरह से जिया जाता है। बहुत सी बातें और हैं जो हरियाणा की उपलब्धियों के बारे में हैं। मेरे हल्के सफीदों में बहुत से काम किये गये हैं जो पहले कभी नहीं हो पाये थे वे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। मेरे हल्के सफीदों में एक बहुत पुराना होस्पिटल था वह जनरल होस्पिटल दोबारा से बनाया गया है। वहां की कम से कम 24 सड्कों में से कुछ तो बन गई हैं और कुछ पर काम चल रहा है इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। बुजुर्गों के पहचान पत्र हर हल्के में बन रहे हैं जिससे उनको हर प्रकार की सुविधा दी जायेगी। माननीय गुप्ता जी कह रहे हैं कि राज्य की वरिष्ठ महिलाओं के पहचान पत्र बनाकर उनका हरियाणा रोडवेज की बसों में 5० प्रतिशत तक किराया माफ किया जायेगा यह बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे हल्के का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ सड़कें हैं जिनकी बहुत ही आवश्यकता है, ये सड़कें हैं बडौद से साहनपुर, रेलवे स्टेशन से शिलाखेडी रोझला से बिटानी, बुढाखेडा से खरकगागर, ऐथरा खुर्द से हरिगढ, साहनपुर से धर्मगढ, गांव मलिकपुर से डेराबधावासिंह, लिंक रोड रिसालवा से निमनाबाद, सिवाना माल से भम्भेवा, खेड़ा खेमावती से रामपुरा और कुछ स्कूल मी हैं जिनको अपग्रेड करने की बहुत ही आवश्यकता है। ये स्कूल हैं करसित्धु गवर्नमैंट मिडिल स्कूल से

गवर्नमैंट हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए, राताखेडा गवर्नमैंट मिडिल स्कूल से गवर्नमैंट हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए, खेड़ा खेमावती गवर्नमैंट हाई स्कूल को गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में अपग्रेड किया जाए, गवर्नमैंट कन्या हाई स्कूल हाट को गवर्नमैंट कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाए और बागडु खुर्द एवं बागडू कलां गवर्नमैंट हाई स्कूल को गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में अपग्रेड किया जाए।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, आप ये सब लिखकर भिजवा दैना। यह सब बात रिकार्ड में ले ली जायेंगी।

श्री बचन सिंह आर्यः अध्यक्ष महोदय सिर्फ दो एक बातें रह गई हैं वे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। इसके अलावा हाट सब मार्डनर हट्टकेशर मन्दिर का जोकि ऐतिहासिक स्थान है सफीदों में 'और जींद जिले के 'अन्दर है जोकि बहुत जरूरी है राजा के समय से चला करती थी जो 'अब बंद हो गई है, मलार माईनर जहां सिंचाई मंत्री बनी भी गये थे और उसको मंजूर करके आये थे उसको भी बनवाया जाये। हाट 33 के०वी० पावर हाउस को 182 के०वी० का अपग्रेड करवाया जाये, गांव हरिगढ में पीने के पानी का टयूबवैल लगवाया जाये। निमनाबाद गांव में पशु अस्पताल की बिल्डिंग जो जर्जर हालात में है उसको बनवाया जाये, बागडु खुर्द में आयुर्वैदिक अस्पताल की बिल्डिंग बनवाई जाये। बागडु कलां गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवायी

जाए। वहां पर ट्यूबवैल लगवाया (जाए। आपने मुझे टाईम दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० छत्तरपाल सिंह (घिराय): मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 5 साल के बाद व्यवस्थाएं आती हैं, चली जाती हैं। आज इन 5 साल के टैन्योर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका हरियाणा की जनता एक्सपीयरैंस कर रही है। This is the best system in comparison with the previous system. अध्यक्ष महोदय, दोनों में दिन रात का अंतर है। यह हरियाणा की जो विधान सभा है इसके अंदर हम बहुत पवित्र आत्माओं के आने की उम्मीद करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सुदृढ़ और स्वच्छ किस्म के व्यक्ति यहां आकर चाहे उनका अपोजीशन का रोल हो और चाहे रूलिग दमा रोल डरो वे हरियाणा के हित के, हरियाणा के लोगों की भलाई के काम करें। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस टैन्योर में अपोजीशन न हमारे साथ बैठकर कोई कंस्ट्रक्टिव बात कह पाती है और न ही सुन पाती है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी डैमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अकैडमिक एजुकेशन और मोरल एजुकेशन दोनों ही आवश्यक हैं। अध्यक्ष महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि इन्फर्मेशन का जो अधिकार हमें मिला है वह तीसरा पहलू है। प्रजातांत्रिक सिस्टम में चाहे जो भी लोग हैं चाहे वे अधिकारी/कर्मचारी हैं और चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके लिए ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि इंडियन नैशनल लोकदल की जो

पार्टी है उसमें जिस आदमी के पास ये तीनों चीजें नहीं हैं, उसकी सीधी एंट्री है। यहां इनका जो रोल देखने को मिलता है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है 1 डैमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे जो संविधान की प्रणाली है उसके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि चुनी हुई जो भी संस्थाएं है वे बहुत ही सुलझे हुए लोगों की हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके रोल के द्वारा यहां से जो मैसेज जाता है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है और उसका कारण यह है कि न इनके पास कोई एकैडमिक एजुकेशन है न ही मोरल एजुकेशन है और न ही इनके पास कोई इन्फर्मेशन सिस्टम है। इनका सिर्फ एक ही कार्यक्रम है कि जो कुछ भी मास्टर जी ने बता दिया उसका पालन करना है और उसका अनुसरण करना है। मास्टर जी जो बताते हैं वह सिर्फ यह बताते हैं कि जाकर विधान सभा को डिस्टर्ब करना है, हाई लाइट्स में आना है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर आपने हमेशा इनको बोलने का मौका दिया है, आपने इनको प्रवोक किया है कि अगर कोई ऐसा सरकार का क्रिटीसिज्म आपके पास है, आपकी शिक्षा ठीक है, आपकी इन्फर्मेशन ठीक है तो हाउस को बताओ। अध्यक्ष महादेय, मैं .आपका बहुत 'आभारी हूं कि आप कई बार यहां तक सहयोग देते हैं कि मिनिस्टर्ज को बताते हैं कि आपका जवाब ठीक नहीं है, आप स्टेट के इंट्रस्ट के अंदर जो माननीय सदस्य की बातें हैं, उसमें उनको सैटिसफाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी यदि उसका हमारे साथी फायदा नहीं उठा सकते हो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रांत का और क्या हो सकता है? कितने डिग्निटरीज हमारे बीच से चले गए, बड़ा अच्छा

लगा जब चौधरी रणबीर सिंह जी के देहांत पर अपोजीशन के लोग वहां नजर आए। लोगों को भी पता लगा कि अपोजीशन के लोग हैं लेकिन यहां इस पंचायत के अंदर ओब्चूरी रैफैसिंज में उनकी महानता के०पर उनका जो डैमोक्रेटिक पैटर्न में, पार्लियामैंट में और असैम्बली में रोल रहा है, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये हमारे साथी इतने तंग दिमाग थे कि इनके पास उनके खिलाफ कुछ कहने को नहीं था और पक्ष में सुनने की ये क्षमता नहीं रखते थे इसलिए एक स्ट्रैजी के तहत यहां से गायब होकर चले गए।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for half an hour?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for half an hour.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० छत्तरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से उनका बचकर भाग जाना यह स्टेट में कोई अच्छा मैसेज नहीं देता। मैं शिक्षा मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वे शिक्षा के०पर इतना जोर दें कि हरियाणा में कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति न बचे जो इनैलो पार्टी में एंट्री लेने की क्षमता रखता हो।

अगर आप हरियाणा की जनता को शैक्षणिक और नैतिक दृष्टि से निपुण कर देंगे, उनका कम्पलीट इनफर्मेशन सिस्टम निपुण कर देंगे तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इण्डियन नेशनल लोकदल की कोई भी रसीद काटकर उसकी मैम्बरशिप नहीं लेगा because that is a different nature of institution और आपका ईस्टीच्युशन दूसरे किस्म का है। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी से चर्चा की गई कि आप ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों को क्यों पास करते हो? इन्होंने इस बारे में एक साल का उदाहरण दिया लेकिन जब हमने दूसरे सालों के बारे में पूछा तो इन्होंने उसमें कई साल बता दिये। स्पीकर सर, हम यह चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री महोदय कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम कर दें ताकि स्कूलों में हमारी शिक्षा की जो फाऊंडेशन है उसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाये ताकि हम अपने प्रजातांत्रिक ढांचे के अन्दर निपुण व्यक्ति तैयार कर सकें चाहे अधिकारियों के रूप में उनका रिकूटमैंट हो, चाहे कर्मचारियों के रूप में उनका रिकूटमैंट हो, चाहे पॉलिटिक्स के अन्दर उनका रिकूटमैंट हो, चाहे वे फौज में भर्ती हों और चाहे वे पुलिस में भर्ती हों, अगर हम उनकी शिक्षा की फाऊंडेशन अच्छी बना देते हैं तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं जो हाऊस के अन्दर आज हमारे लिए एक चिंता का विषय है जिसको हम करप्शन की बात कहते हैं जिसको हम लथारजिक एटीच्यूड की बात कहते हैं, जो हम नोन वर्किंग एटीच्यूड की बात कहते हैं, ठगी से खाने की बात कहते हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। आज जिस तरीके से इन सारी चोरियों को करके भी लोग बचकर भाग जाते हैं और

पब्लिक के सामने अपना अच्छा चेहरा दिखा देते हैं, यह देखने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा होगा तो फिर ये सारी की सारी निपुणतायें खत्म हो जायेंगी और जो एक वास्तविक निपुणता है जो एक व्यकित के अन्दर हमारा ह्यूमन रिसोर्सिस डिपार्टमैंट अपेक्षा करता है, शिक्षा विभाग और शैक्षिक इंस्टीच्यूशंज के माध्यम से हम अपनी शिक्षा की फाऊंडेशन को मजबूत करें। जब तक हमारी शिक्षा की फाऊंडेशन मजबूत नहीं होगी तब तक यह दिक्कतें हमारे सामने खड़ी होती ही रहेंगी। इसके लिए मैंने शिक्षा मंत्री महोदय को सुझाव दिया था कि आपकी ट्रांसफर पालिसी जो पांच साल के लिए है जिसे आज हार्ड कोर्ट ऑबजर्ब कर रहा है जिसके मुताबिक आपके पास डायरैक्शज हैं कि पांच साल से कम यदि किसी का स्टे है तो उसको जब तक कोई सरकमस्टासिज न हों आप उसको न बदलें। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप शिक्षकों की अकाऊंटेबिलिटी तय कर दें तो हम ट्रांसफर के लिए जोर देने वाले नहीं हैं। आज अगर हम देहात में जाते हैं तो वहां पर उस गांव के स्कूल का मास्टर सबसे बड़ा ठेकेदार मिलता है। वह कहता है कि अगर हम उसकी बात मानेंगे तब ही वह उस गांव में हमारी वोटे पक्की करवायेगा और अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वोटिंग के समय वह उस गांव में गड़बड़ करवा देगा। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी अध्यापक का इस किस्म का एटीच्यूड है तो फिर वह बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देगा? मैं माननीय मंत्री जी से यही रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि वे सभी माननीय

सदस्यों की मीटिग लेकर ट्रौसफर पालिसी के बारे में कोई ठोस निर्णय लें।

Mr. Speaker : Chhattar Pal Ji, please come to the point.

Prof. Chhattar Pal Singh : Sir, I am very much on the point.

Mr. Speaker : You are discussing other things.

Prof. Chhattar Pal Singh : Sir, this is a relevant thing for the Minister.

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, माननीय छत्तरपाल सिंह जी बहुत वैलिड– सुझाव दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन्होंने आपसे मिलकर एक विशेष अनुरोध किया था परन्तु मुझे लगता है कि ये शायद उसे भूल गये हैं मैं यही चाहूंगा कि इन्हें उसे अवश्य पूरा करना चाहिए।

श्री छत्तर पाल सिंह: स्पीकर सर, मुझे इनका वह अनुरोध बहुत अच्छी प्रकार से याद है और इनका वह अनुरोध in due course of time बहुत जल्द ही पूरा किया जायेगा। स्पीकर सर, यह नितांत आवश्यक है कि जब तक हम अच्छा पड़ाने वालों को कोई विशेष एडवांटेज नहीं देंगे और जिनके रिजल्टस खराब आते हैं उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, उनकी कोई इंक्रीमैंट नहीं काटेंगे या इस प्रकार की दूसरी कोई फाईनैंशियल पनिशमैट उनको नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि शिक्षा के अन्दर कोई

वैलिड सुधार होने वाला हैं यह बात ठीक है कि जब अच्छा चीफ मिनिस्टर रहता है और अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर होता है तभी हमारा शिक्षा से जुड़ा पूरा सिस्टम सहीं फंक्शन करता है। इसके अलावा अगर शिक्षा के आधारभूत ढांचे में पूर्ण सुधार की प्रक्रिया कम से कम 5 से 10 साल चलती है तभी किसी ठोस सुधार की उम्मीद की जा सकती है लेकिन अगर बीच में कोई अनपढ़ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार आ जाती है तो वे सम्पूर्ण सिस्टम को और पत्नी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। इसलिए आज अगर इसका कोई परमानैंट सिस्टम बन जाये जिसमें किसी भी प्रकार का पालिटिकल हस्तक्षेप भी न हो तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि जब तक हम अपनी शिक्षा के फाऊंडेशन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तब तक हम किसी अच्छे प्रान्त की, अच्छे देश की और अच्छे समाज की स्थापना की अपेक्षा नहीं कर पायेंगे। स्पीकर सर, हमें आजादी अनेक देशभक्तों की कुर्बानी के आधार पर मिली है। आज हमें इस बात को इश्योर करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें नहीं कोसे और वे हमारे बारे में यह जरूर कह सकें कि जिस किस्म का प्रान्त हमें मिला था उसे हमने उससे बैटर बनाकर आने वानी पीढ़ियों के लिए छोड़ा है। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं स्कूलों के बच्चों के मुतल्लक एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम देहात में जाते हैं, इलाके में जाते हैं तो यह आम शिकायत रहती हैं कि बच्चों को आने–जाने के लिए बसों की असुविधा रहती है। अभी पिछले दिनों कुछ रोडवेज के कर्मचारी भी धरने पर बैठे थे। मंत्री महोदय से मेरी बात भी हुई

थी। हमने स्टाफ रिफ्ट किया हैं पिछली सरकार ने तो बहुत बुरी हालत में ट्रांसपोर्ट को छोड़ा था। बसों में कंडक्टर–ड्राईवर नहीं थे। अब सरकार ने नई बसें भी खरीदी हैं लेकिन अभी भी कमी है। मंत्री जी ने इस बात को माना था कि हिसार डिपो में कुछ नई बसें और जुडनी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिक्कत और भो आती है कि प्राईवेट बसिज के और सरकारी बसों के कुछ क्लैशिज हैं। प्राईवेट बस ऑप्रेटर की मनमानी होती है अगर बस खाली है तो रूट पर चला देते हैं और यदि उनको कोई अच्छी बुकिंग मिल जाती है तो वे वहां पर चले जाते हैं। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उस गांव के यात्रियों को परेशानी न हो, स्कूल के बच्चे प्रभावित न हों, लड़कियां प्रभावित न हों। मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जिसमें मेरा अपना गांव फरीदपुर है, कंडूल गांव की भी यही शिकायत हे। नयणा, खरड, रायपुर, शिकारपुर, मिर्जापुर अनेक गांव ऐसे हैं जहां से ये रिपिटिड कंप्लेटस आती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर विशेष ध्यान देंगे। अध्यक्ष महोदय, रोडस के बारे में मेरी गुजारिश थी। मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दे दिया था कि किनाला से दौलतपुर की रोड कम्पलीट करेंगे। इसके लिए आश्वासन पहले भी आया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आश्वासन हाउस में दे दी जाये उस आश्वासन को तो टाईम बाऊंड करके पूरा कर दिया जाये अन्यथा यहां पर सरकार के नोटिस में लाने का कोई फायदा नहीं रहता। उसके०पर जरूर सरकार को इस प्रकार की हिदायत दें कि

जो यहां आश्वासन दिये जायें उनको पूरा किया जाना चाहिए। जो रोड आधी बनी हुई हैं उनको पूरा करना तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि आधा पैसा लग चुका होता है और रिपेयर भी सरकार की प्रायरटी में होनी चाहिए। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो जो रोड द्रुमने मंत्री जी को लिख कर दे रखी डे उनको टेकअप कर लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना तो यह है कि पहले यदि कोई लिंक गैप है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जाये ताकि कम पैसे में एक वायबल रूट बन सके और उसके बाद दूसरी रोड की लिया जा सकता है। इरीगेशन से मुतल्लिक बात मैंने कही थी। इस मामले में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी। इस सरकार के बनने के बाद भाखड़ा के सिस्टम पर महीने में 16 दिन पानी देने की बात हुई थी। पहले दो साल जब भाखड़ा में पानी की उपलब्धता अच्छी थी तो हमने 16 दिन पानी दिया भै। था बीच मो भाखड़ा में पानी कम आया तो फिर हमें प्रोग्राम रिवाईज करना पडा। आज फिर भाखड़ा में पानी की एवेलेबिलिटी अच्छी है अब फिर हमने 16 दिन पानी की व्यवस्था कर दी है। अध्यक्ष महोदय मैं सिंचाई मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लेकर आया हूं कि एक हफ्ते पानी ठीक चलता है दूसरे हफ्ते वह सिस्टम ठीक से फैक्शन नही कर पाता है। उसमें आधा या एक चौथाई ही पानी चलता है और टेलों पर पानी पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है। विशेष तौर से हिसार के राजस्थान से लगते गांव में पानी टेल तक बहुत कम पहुंचता है। भिवानी में भी जो हिसार से लगता इलाका है वहां से

भी इस प्रकार कै। शिकायत आती है। मैंने अधिकारियों से इसकी पूछताछ की तो बताया गया कि कहीं पर किनारे कमजोर हैं और कैपेस्टी आफ दी रिवर है वह ले नहीं पाती है, कहीं पर स्लैब गिर गये हैं। अध्यक्ष महोदय, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हैं। मिनिस्टर साहब के नोटिस में हमेशा यह रहना चाहिए कि किस इलाके में रिवर को फंक्शनिग ठीक रहा है। उनको डेली चौक करवाना चाहिए कि पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर विधायक या लोग आकर शिकायत करें उसके बाद उसको रैक्टीफाई करने में समय लग जाता है। उसमें किसान का हफ्ता चला जाता है। आप समझसे होंगे कि किसान की फसल पर यदि एक–दो हफ्ते की मार पड़ जाती हैं तो उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैंने इरीगेशन के अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा था कि जो खाले रिमॉडल होने हैं, रिपेयर होने हैं, उनको ठीक करवाएं। उसके लिए दो साल का समय दिया गया था। स्पीकर सर, मैं यह भी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की उस बात को प्रशासन ऑन करे। अगर दो साल का समय दिया है तो वह दो साल में ही पूरे होने चाहिएं। आज भी बहुत सी डिमांड्ज पैंडिंग पड़ी हैं। मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं के बावजूद उसमें बहुत सीरियस डिले है जो नहीं होना चाहिए। पावर डिपार्टमैंट में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ढाणियों के अन्दर बिजली की व्यवस्था के लिए माननीय मंत्री जी ने ऐश्योर किया कि कोई न कोई तरीका उसमें निकालेंगे। वैसे तो सरकार ने जो थर्मल पावर प्लांट में बिजली जैनरेशन का कार्यक्रम शुरू किया है वह काबिले तारीफ

है। स्पीकर सर, मैंने तो उस दिन ओम प्रकाश चौटाला जी से सवाल भी किया था कि जिन प्रोजैक्टों की लैंड ऐक्यायर हो चुकी थी .प्रोजैक्ट तैयार थे लेकिन आप अपनी सरकार में बैठे रहे और एक भी ईंट आपने वहां पर नहीं लगाई। हमने उसमें खेदड का उदाहरण दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए और उसके०पर युद्धगति से काम चल रहा है। कम्पलीशन टाईम से दो महीने पहले ही आप उसकी जैनरेशन देने के लिए तैयार खड़े हैं। स्पीकर सर, आपकी सरकार ने बड़े ही रैवोल्यूशनरी काम किये हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रिएटिव जो ढिलाइयां हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी चुस्त–दुरूस्त करेंगे। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मेरे नोटिस में कुछ ऐसे विलेजिज आए हैं।

श्री अध्यक्षः प्रोफेसर साहब, आप लिख कर भिजवा दीजिए।

प्रो० छत्तरपाल सिंहः माननीय पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं मैं एक मिनट और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। स्पीकर सर, मेरी कांस्टीच्यूऐंसी के दो गांव सातरोड क्लां और चानर में पीने का पानी गंदा चलता है। मैंने इस बारे में अधिकारियों को बुला कर उनको काफी कुछ कहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर जी इस बारे में सख्त नोटिस लें। देहातों के अन्दर अगर पीने का पानी गंदा जाता रहे तो उससे लोग बीमार हो जाएंगे। जो जे०ईज० और एस०डी०ओज०

हैं उन पर कोई कार्यवाही न हो तो ठीक नहीं है। उनका यह काम है और उन्हें लाईन पर रखना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बाकी की बात आप लिखकर भिजवा दीजिए।

प्रो० छत्तरपाल सिंहः स्पीकर सर, स्पोर्टस की मेरी एक डिमाण्ड है। यह बहुत ही इम्पोर्टैन्ट है। उमरा गांव के अन्दर गद् दा है वहां पर नर्सरी तो सैंक्शन हो चुकी है लेकिन वहां पर शैड नहीं है तो स्पोर्ट डिपार्टमैंट वहां पर शैड बनवाये। सिसाय गांव में नर्सरी की बाकी सारी बिल्डिंग तैयार है शैड और कमरे बने हुए हैं। वहां पर होस्टल भी बना हुआ है लेकिन वहां पर नर्सरी सैंक्शन नहीं है, मैं चाहूंगा कि वहां पर नर्सरी सैंक्शन की जाए। थी अध्यक्षः इनकी नर्सरी का ध्यान रख लीजिए। प्रोफैसर साहब, ठीक है अब आप बैठें।

प्रो० छत्तर पाल सिंहः स्पीकर सर, सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिये हैं और उम्मीद है कि वे जल्दी ही हमें रिलीफ देंगे। स्पीकर साहब, आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वैरी मच।

डा० शिवशंकर भारद्वाज (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय श्री रणबीर सिंह

हुड्डा जी के बारे में जो कुछ कहा है वह शतप्रतिशत सच हैं एक बार हमें भी मौका मिला और हमने उनको भिवानी बुलवाया था। उनकी आख का ऑपरेशन हुआ था उसके बावजूद भी वे भिवानी आए। उन्होंने भिवानी में पंडित नेकी राम जी के साथ काफी काम किया और उनके जो संस्मरण थे वे उन्होंने हम सब के बीच में बाटे। श्री बनारसी दास गुप्ता जी और हुक्म सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे उनके बीच में उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए। उनके वे संस्मरण वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और आगे आने वाली जैनरेशन के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। स्पीकर सर, गवर्नर साहब ने जो कहा जहां तक राष्ट्र की बात है, हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम परमाणु क्लब के सदस्य हैं और हिन्दुस्तान ने चांद पर भी मिशन भेजा है। यह सब कुछ कांग्रेस के राज में श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशन में सम्भव हो पाया है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हमारी योजना का आकार 6650 करोड़ रुपये से बढ़ कर दस हजार करोड़ रुपये हुआ है। मैं समझता हूं कि हरियाणा का बच्चा–बच्चा इस सम्बन्ध में गर्व महसूस कर सकता है क्योंकि योजना का आकार बढ़ने से ही इन्फरास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हमारा हरियाणा तरक्की करेगा। वर्ष 2009 को किसान–मजदूर वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसान और मजदूर हरियाणा की आत्मा है। हम सबके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक महामहिम गर्वनर महोदय ने सिंचाई का जिक्र किया भूमिगत पाईपलाईन जो डाली जाती हैं इससे पानी को बडी

बचत होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम से भी पानी की काफी बचत होती है। पिछली बार अपने रैजोल्यूशन में भी मैंने कहा था कि हमारे हरियाणा में जलस्तर काफी तेजी से गिरता जा रहा है और इसको०पर लाने के लिए हमें हर सम्भव उपाय करने चाहिएं। वर्ष 2008–09 में नये पशु चिकित्सा संस्थान खोलने के लिए जो बातें कही गई हैं ये बहुत आवश्यक हैं। मेरे क्षेत्र में एक गांव राजगढ़ है जहां पर हमने कोशिश की है कि कम से कम एक वेटरनरी डिस्पैंसरी वहां पर खुलनी चाहिए लेकिन अभी तक खुली नहीं है। मेरी आपके माध्यम से रिक्वैस्ट है कि वह जल्दी से जल्दी खोली जाए ताकि वहां के हमारे लोगों को फायदा हो और उस इलाके के पशुधन में तरक्की हो सके। जैसे कि बताया गया है कि 281 लाख नए पौधे हरियाणा में लगाए जाएंगे और अगले वर्ष 425 लाख नये पौधे लगाए जाएंगे। जब तक हम हरियाणा को ग्रीनरी नहीं बनाएंगे तब तक हमारी पानी की समस्या दूर नहीं होगी। जहां पर वन होंगे वहीं पर वर्षा होगी। इस बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। जहां तक राशन कार्ड को इलैक्ट्रानिक स्मार्ट कार्ड में बदलने का प्रावधान किया गया है मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा है। इसके बनने से जो छोटे लैवल पर गड़बड़ियां होती हैं, वे रुक जाएगी–। सर, कई बार सामान के वितरण में बहुत धांधलियां हो जाती हें जिसके बारे में हम लोगों के पास बहुत शिकायतें आती हैं ओर हमें उनका निराकरण भी करना पड़ता है। अगर ये इलैक्ट्रानिक स्मार्ट कार्ड बन जाएंगे तो आम आदमी को इससे बहुत राहत मिलेगी। सर, राजीव गांधी पेय

जल योजना और रिवर्स आसमोसिज टैक्नोलोजी का जिक्र गवर्नर साहब के अभिभाषण में हुआ था और इसी तरह से सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का भी जिक्र हुआ था। सर, भिवानी में भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की बहुत जरूरत है। हमारी भिवानी–घग्गर ड्रेन करीब–करीब बनकर तैयार हो गई है। सर, हमारे यहाँ देवसर चुगी पर जो डिस्पोजल को एफल्यूएंट है अगर वहां पर ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाए तो उस पानी को इरीगेशन के लायक बनाया जा सकता है। उस पानी को अगर भिवानी–घग्गर ड्रेन में डाल दिया जाए तो वह पानी और अच्छे तरीके से इरीगेशन के काम में आ सकता है। सर, मेरा एक फोर प्वायंट प्रोग्राम है जिसमें पहला प्वायंट शुद्ध पेय–जल का है। इसमें काफी तरक्की हुई है। दूसरा प्लायंट, हर घर में शौचालय हो, उसमें भी काफी तरक्की हुई है। तीसरा प्वायंट शिक्षा के बारे में है और चौथा प्वायंट क्रप्शन कम हो। इस दिशा में काम चल रहा है लेकिन इसको तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। सर, रेलवे ओवर ब्रिज का अभिभाषण में जिक्र हुआ था। उस बारे मैं 'मैं कहना चाहता हूं कि भिवानी में हमारे दो रेलवे ओवर ब्रिजिज सैंक्शन हुए थे। एक पर काम शुरू ही गया है लेकिन वह काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस काम में तीव्रता लाई जाए ताकि यह काम इसी वर्ष में पूरा हो जाए नहीं तो यह पूरा नहीं होगा। सर, हमारे भिवानी में जो मेन समस्याएं हैं, वह स्ट्राम वाटर ड्रेनेज और सीवरेज की है। पीछे जब बरसात हुई तो भिवानी का बहुत सा इलाका जलमग्न हो गया था।

मुख्यमंत्री जी वहां पर गए थे और मुख्यमंत्री जी ने वहां पर यह भी कहा था कि इस समस्या का एक स्थाई समाधान किया जाएगा। जब तक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज और सीवरेज का अलग–अलग से प्लान नहीं बन जाता है तब तक इसका समाधान नहीं हो सक्ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारे यहां हालू मोहल्ला, पी०एन०बी० के सामने कोर्ट रोड पर कृपा राम की ढाणी है वहां पर सीवरेज की समस्या है, स्टॉम वाटर ड्रेनेज की समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सी कालोनियां हैं जैसे आदर्श नगर हसनपुर कालोनी है, शिव नगर कालोनी है, वर्मा और डाबर कालोनी है जोकि स्ट्राम वाटर ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या से जलमग्न हो जाती हैं। इनके लिए सरकार को एक प्लान बनानी चाहिए और उसमें देरी नहीं की जानी चाहिए ताकि जब भी बरसात. हो तो उसके पानी से इन कालोनियों को डूबने से बचाया जा सकै। सर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगा कि भिवानी में पहले ही दो हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियां थीं और अब एक और हाऊसिंग बोर्ड की कालोनी बना दी गई है। इस कालोनी के पास पहले से ही अम्बेदकर बस्ती और बाल्मीकि बस्ती है और इस हाऊसिंग बोर्ड की कालोनी बनने से उन बस्तियों का रास्ता रुक गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए थे और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि वहां पर 12 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ा जाएगा। वहां पर वह रास्ता करीब–करीब 700 फुट लम्बा है। अगर यह रास्ता नहीं छोड़ा जाता है तो वहां पर उन बस्तियों में जाने का रास्ता बंद हो

जाएगा। अगर वहां पर कभी कोई जरूरत पड़ गई तो वहां पर न तो कोई ट्रैक्टर जा पाएगा और न ही फायरब्रिगेड की गाड़ी जा पाएगी। सर, अभी वहां पर यह रास्ता नहीं छोड़ा गया है, इसमें अभी भी थोड़ा विवाद चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन गरीब बस्तियों के लिए रास्ता जरूर छोड़ा जाना चाहिए। वहां के लोगों के मन में अभी भी इस रास्ते को लेकर शंकाएं हैं। हालांकि मैं उनकी उन शंकाओं को समय–समय पर दूर करता रहता हूं फिर भी उनके लिए और कुछ करने की जरूरत है। सर, भिवानी में एक गर्ल्ज स्कूल की आवश्यकता पिछले काफी समय से है। आज भिवानी में लड़कियों का एक ही स्कूल है और वहां पर 2500 से ज्यादा लड़कियां पड़ती हैं। यह स्कूल दो शिफ्टों में चलता है। वहां पर सी०एम० साहब ने लड़कियों के लिए एक और स्कूल खोलने की 15.11.2006 को घोषणा की थी लेकिन यह स्कूल अभी तक नहीं बना है। मेरा आपके माध्यम से सी०एम० साहब से और शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि लड़कियों का यह स्कूल जल्दी से जल्दी से बनना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को कुछ और सुविधा हो सके। बहुत सी सड्कों पर हमारे यहां पर काम हुए हैं लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जैसे पतराम गेट से सर्कुलर रोड और गीता भवन के सामने की रोड जिनको जल्दी बनाने की जरूरत हे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि हमारी ये सड़कें बननी चाहिएं। भिवानी के बाई पास का जिक्र भी मैंने पहले किया था 1 बाई पास के बिना ट्रैफिक कंजैशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं आदरणीय मंत्री

कैप्टन अजय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जल बाई पास का एक हिस्सा मैटीनैंस कै लिए पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एंड आर०) को दे दिया है। लेकिन रोहतक रोड से महम रोड और रोहतक रोड से दादरी रोड का भी बाई पास अगर नहीं बनेगा तो हमारी ट्रैफिक की समस्या कंट्रोल नही होगी।

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, अब आप कंक्लूड करें।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः स्पीकर सर, मैं दो मिनट में कच्छ कर रहा हूं। इसी तरह से प्रहलादपुर में एक वाटर वर्क्स बनना था जोकि अभी तक नहीं बना है। गौरीपुर में और उमरावत में भी वाटर वर्क्स की हमें सख्त जरूरत है। इसी तरह से हमारे यहां के लिए दो सड़कें रूपगढ से ढाणी कम तक और नांगल से निनहान तक की भी सैंक्शन हो चुकी है लेकिन वह भी अभी तक बनी नहीं है इसलिए इन पर भी काम होना चाहिए। 132 के०वी० का सब स्टेशन बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था इसलिए उसमें भी थोडी तीव्रता आनी चाहिए। स्पीकर साहब, भिवानी का 'अस्पताल हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ा अस्पताल है। वहां पर कैंसर के मरीजों के लिए कोबाल्ट यूनिट सैंक्शन है लेकिन वह भी अभी तक बनी नहीं है। हालांकि इस विभाग ने वहां पर काफी काम किए हैं। वहां पर स्पेशलिस्ट्स की पोस्टिंग की है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं लेकिन अभी तक भी वहां पर पूरे स्पेशलिस्ट्स नहीं है इसलिए वहाँ पर स्पैशलिस्ट्स पूरे किए जाने चाहिए। सर, भिवानी जिला

पिछले कुछ सालों से हरियाणा में दूसरे जिलों के मुकाबले पिछड़ गया है। अगर इसको सारे प्रदेश के साथ मूव करना है तो वहां पर बहुत सी चीजें होनी चाहिए। वहां पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नेशनल लॉ कालेज होना चाहिए या वहां पर मैडीकल कालेज होना चाहिए। इसी तरह से वहां पर थोड़ा इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्पीकर सर, हरियाणा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है अगर वह भिवानी में बन जाए तो ठीक रहेगा या फिर वहां पर यदि कालो टर्मिनल बन जाए तो इससे हमारे इलाके की तरक्की हो सकती है। स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री सुखवीर सिंह (रोहट): स्पीकर साहब, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं और सदन में जो शोक प्रस्ताव पास किए गए थे उनमें भी मैं अपने आपको जोड़ता हूं। स्पीकर साहब, हमारे बीच से हमारे आदरणीय बहुत०ंची सोच वाले बहुत ही नेक, ईमानदार मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी कै पिता जी चौधरी रणबीर सिंह जो बहुत बड़े फीडम फाईटर थे, हरियाणा के बहुत बड़े आर्य समाजी थे, चले गए हैं। स्पीकर साहब, जब हरियाणा में शिक्षा न के बराबर थी उस समय उन्होंने दिल्ली के हंसराज कालेज से बी०ए० की डिग्री की पढ़ाई की। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए, देश के सुधार के लिए, देश की तरक्की के लिए लगा दिया था। विधान सभा में जो यह प्रस्ताव किया गया है कि संसद में उनकी प्रतिमा

लगाएं तो इस बात का मैं समर्थन करता हूं। मैं तो यह भी कहता हूं कि उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जाए। वे केवल 15 साल की उम्र में ही जेल में गए इसलिए उनकी यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। वे कई बार जेल में गए और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसके बाद में उन्होंने कई चुनाव लड़े और मंत्री बने! स्पीकर साहब, उन्होंने देश क्रो तो आजाद करवाया ही साथ ही यदि आज हरियाणा में किसान और मजदूर जिंदा है तो उनके कारण ही है क्योंकि उन्होने भाखड़ा डैम की नींव रखवाकर उसको बनवाया था। उनकी बदौलत ही हरियाणा का किसान और मजदूर जिंदा हैं। स्पीकर साहब, जब हरियाणा में शिक्षा दिखाई नहीं देती थी और 50 किलोमीटर तक स्कूल नहीं था उस समय में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। रोहतक में जाट स्कूल की नींव रखकर उसको वनवाने का काम चौधरी मातुराम जी ने किया। इस तरह से मातुराम जी ने उस स्कूल की शुरुआत की 'और उसके प्रैजीडैंट भी रहे। रणबीर सिंह जी ने खुद भी अच्छी शिक्षा ली और दूसरों के लिए भी शिक्षा का प्रसार किया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। आज हिन्दुस्तान में हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में नम्बर वन है। अब हरियाणा में चाहे कहीं मैडीकल की शिक्षा प्राप्त करो, चाहे कहीं ए०एन०एम०, नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करो। पहले हमारे बच्चे भोपाल, (म०प्र०) व नागपुर (महाराष्ट्र) में पढ़ाई के लिए धक्के खाते फिरते थे। अब हमारे यहां के बच्चों के लिए पढ़ाई की कोई समस्या नहीं रह गई है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्

डा जी ने अपने पिता जी के रास्ते पर चलते हुए हरियाणा का पूरे हिंदुस्तान में नाम०चा किया है। मैं चाहता हूं वि? इसी सैशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं चाहे इंजीनियरिंग कालेज हैं या दूसरे कालेज हैं उन सभी में चौधरी देवी लाल के नाम से स्टेच्यू खड़े कर दिये जबकि चौधरी रणबीर सिह जी तों काफी बड़े शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। चौधरी रणबीर सिंह जी तो बहुत बड़े आर्यसमाजी थे। उन्होंने हंसराज कालेज से उस समय बी०ए० किया था। आज यदि कोई हंसराज कालेज से बी०ए० कर ले या रामजस कालेज से या करोडीमल कालेज से बी०ए० करता है तो निश्चित रूप से आई०ए०एस० या आई०पी०एस० बनता है। मेरा तो यही कहना है कि जितनी भी हरियाणा प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं या चाहे इंजीनियरिंग कालेज हैं या फिजिकल कालेज हैं, डिग्री कालेज हैं या यूनीवर्सिटीज हैं उन सभी संस्थाओं में उनके नाम पर उनमें स्टेचू लगने चाहिए, यह आपका हक भी बनता है और नौजवानों को जो डिग्रियां मिलती हैं उन सभी डिग्रियों में उनका नाम होना चाहिए तभी उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया और अपने आदर्श तां उम्र रखे, सादगी से जीवन व्यतीत किया। यदि हम यह सब न कर सके तो उनको श्रद्धांजलि देने में कंजूसी मानी जाएगी। यह बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बैठे हैं। मुझे तो स्पीकर साहब आपने पहले ही कह दिया था कि आपने आज ही बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसे समाजसुधारक

और शिक्षाविद् नहीं देखे। उन्होंने 65 साल की आयु में ही राजनीति से संन्यास ले लिया था। आज तो केन्द्र में 80–80 साल की उम्र में भी नेता लोग मंत्री पद पर बैठे हैं। वे महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। वे भी चाहते तो मरते दम तक सैंटर में मंत्री पद पर रह सकते थे लकिन उनके आदर्श थे। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा और मेरा पोता राजनीति में हैं इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। मैं तो अपनी भी बात करता हूं कि जब मेरी 62–63 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो मैं भी कोई इलैक्शन नहीं लडूंगा। मैं तो चाहता हूं कि सभी को इस बात का अनुसरण करना चाहिए

श्री अध्यक्षः प्लीज कंक्लूड।

श्री सुखवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं चौधरी रणबीर सिंह जी बहुत बड़े महान समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे और बाबा आबेंडकर साहब के साथ मिलकर संविधान लिखने वाले थे। हरिजनों की इतनी बड़ी खुशकिस्मती थी कि उनके लिए रिजर्वेशन लागू करवाने वाले भी वे थे। वे अम्बेडकर साहब का साथ देने वाले थे क्योंकि वे सच्चे आर्य–समायी थे और जातपात से दूर थे। जिन्होंने हरिजनों के मुंह से मुंह लगाया था।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the

time of the sitting of the House be extended for five minutes?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for five minutes.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सुखवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग भी रखना चाहता हूं कि पेंशन की राशि 500 रुपये की जानी चाहिए। बाकी तो मांगने के लिए कुछ रहा नहीं है। बिन मांगे हुड्डा साहब ने मोती दे दिये हैं। 500 रुपये पेंशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी यह बात जरूर मान लें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, इनकी तो मैंने कोई भी बात नहीं टाली है।

19.00 बजे

श्री सुखबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि सिसाणे गांव में 10वी कक्षा की बोर्ड की परीक्षा का सैंटर होना चाहिए।

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 13th February, 2009.

19.01 Hrs.

(The Sabha then * adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 13th February, 2009).